बढ़ता संघर्ष

ईरान और इजरायल के बीच सोमवार को फिर हुई घातक बमबारी से आशंका यही है कि यह संघर्ष लंबा खिंचने वाला है। जैसे-जैसे दोनों देशों को नुकसान होता जाएगा, वैसे-वैसे उनके बीच शत्रुता भी बढ़ती जाएगी। उनके हमले भी समय के साथ घातक से और घातक होते चले जाएंगे। सोमवार के हमलों में सबसे खास बात यह है कि इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्डो पर भी हमला किया है। फोर्डो पर अमेरिका ने भी हमला किया था। सोमवार को फोर्डो के अलावा करीब छह सैन्य ठिकानों या एयरपोर्ट पर इजरायल ने हमला बोला है, जिनसे ईरान को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। वैसे, अगर ईरान में सोमवार सुबह युद्ध के सायरन बजते रहे, तो इजरायल के शहरों में भी खूब सायरन बजे। ईरान ने भी मिसाइलों से इजरायल पर खूब प्रहार किए हैं। जहां तक नुकसान का सवाल है, ईरान में अभी तक 400 लोग मारे गए हैं, तो इजरायल में 24 से ज्यादा मरे हैं। हालांकि, प्रचार युद्ध भी तेज है और नुकसान के आंकड़े दोनों पक्ष छिपा रहे हों, तो अचरज नहीं।

पहले यह माना जा रहा था कि ईरान ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएगा, मगर जिस तरह से इजरायल को जवाब मिल रहा है, उससे साफ है कि ईरान एक सैन्य ताकत है। अगर ईरान को कुछ देशों के माध्यम से मदद मिली, तो वह इजरायल के विरुद्ध ज्यादा समय तक खड़ा हो सकेगा। ध्यान रहे, यूक्रेन में उतनी ताकत नहीं थी, पर रूस के खिलाफ कुछ देशों ने यूक्रेन की काफी मदद की है और वह लगातार युद्ध में टिका हुआ है। आज ईरान के जुझारू इरादे को देखते हुए यही चर्चा हो रही है कि अगर ईरान को कुछ देशों ने परोक्ष रूप से भी समर्थन दे दिया, तो एशिया में यह युद्ध बहुत लंबे चलेगा। इजरायल को नुकसान पहुंचाने में ईरान को बड़ी कामयाबी मिल रही है। अगर ईरान को इसी तरह कामयाबी मिलती रही, तो धीरे-धीरे उसे मिलने वाले समर्थन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, अगर युद्ध लंबा चला, तो दुनिया में तेल का संकट बढ़ेगा, अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने विकास की रफ्तार को बनाए रखना कठिन होता चला जाएगा। अतः दुनिया के ताकतवर देशों को यह कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध विराम के प्रयास ईमानदारी से किए जाएं। अभी ज्यादातर देश ईरान को संयम की सलाह दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने ईरान से युद्ध भड़कने की आशंकाओं के चलते पीछे हटने का आग्रह किया है, तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने तेहरान से कहा है कि वह युद्ध बढ़ाने से बचने के प्रयास करे। क्या इतना पर्याप्त है?

दुनिया के ताकतवर देशों को यह कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध विराम के प्रयास ईमानदारी से किए जाएं। अभी ज्यादातर देश ईरान को विराम की सलाह दे रहे हैं।

हालांकि, कुछ बड़े सवालों के जवाब खोजने चाहिए। पहला सवाल तो यही है कि ईरान को समझाने वाले बहुत हैं, पर इजरायल को समझाने वालों की कमी क्यों है? क्या इजरायल समझाने से नहीं मानेगा? दूसरा सवाल यह है कि इजरायल के इरादे क्या हैं? एक तरफ, संवाद की कोशिश और दूसरी तरफ, सीधे हमले की नीति सही नहीं है। ईरान की यही शिकायत है। दरअसल, अमेरिका व इजरायल, दोनों की कोशिश है कि ईरान को खासकर वायु रक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए। युद्ध में यह रणनीति पुरानी है और जिसमें अब तक इजरायल कामयाब होता रहा है। ईरान की मारक क्षमता कम हो जाएगी, तो उसे परमाणु शक्ति से वंचित करने में आसानी होगी। तीसरा सवाल, क्या अमेरिका और इजरायल ईरानी सत्ता में परिवर्तन देखना चाहते हैं? वास्तव में, ये बहुत मुश्किल सवाल हैं, लेकिन युद्ध रोकने के लिए इन सवालों से दुनिया को गुजरना ही होगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 22 जून, 1950

नेहरू जी के सम्मान में भोज

रंगून, 21 जून। आज भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू बर्मा में काफी व्यस्त रहे। सबसे पहिले उन्होंने श्वेडागन पगोड़ा के दर्शन किए। इसमें आप एक घंटे तक रहे। कल रात को बर्मा के प्रधानमंत्री थाकिन नू ने नेहरू जी के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। नेहरू जी ने बर्मा के उन सात मंत्रियों की समाधि पर फूल चढ़ाए, जिनकी हत्या आज से तीन वर्ष पूर्व कर दी गई थी।

भारत के प्रधानमंत्री ने आज पगोड़ा देखा। बौद्धों में यह सर्वाधिक पवित्र तीर्थस्थान समझा जाता है। वे बच्चों समेत एक घंटे तक पगोड़े में रहे। इस बौद्ध विहार की कला को वह देर तक देखते रहे। इसमें पीतल और संतखली की हजारों बौद्ध प्रतिमाएं रखी हुई हैं। रात को वर्षा हो चुकी थी। इसलिए दिन में पगोड़े का घंटाकार सुनहरा स्तूप धूप में खूब चमक रहा था और उधर नेहरू जी दर्शक-पंजिका में हिन्दी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर रहे थे। ''भगवान बुद्ध के इस सुन्दर और स्फूर्तिदायक को फिर से देखने आना अहोभाग्य का विषय है।'' नेहरू जी ने कहा।

नेहरू जी एक सीढ़ी से पहले मंच पर पहुंचे। बर्मा के प्रधानमंत्री थाकिन नू उनके साथ थे। नेहरू जी ने पगोड़े के एक मुख्य स्थान पर स्वर्ण पत्र चस्पां कर दिए। नेहरू जी सफेद वेश में थे। पगोड़े की सीढ़ियों पर प्रहरियों ने उनका स्वागत किया। एक प्रहरी ने उन्हें फूलों का गुच्छा दिया। काफी भारतीय उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। वे 168 सीढ़ियों के एक वृताकार मंच पर पहुंचे। वहां पहुंचकर नेहरू जी को पगोड़े की खास-खास बातों का परिचय दिया गया। नेहरू जी पगोड़े के भीतर शीशे की पच्चीकारी से अत्यधिक प्रभावित हुए। बर्मा की स्वाधीनता की घोषणा पर डा. राजेन्द्र प्रसाद भारत की ओर से बोधि-वृक्ष की टहनी लाये थे, उसे एक स्थान पर रखा गया है। नेहरू जी ने इसे भी दिलचस्पी से देखा।

नेहरू जी के सम्मान में बर्मा के प्रधानमंत्री ने कहा-''भारत के प्रधानमंत्री बर्मा के मित्र रहे हैं। मुसीबत के दिनों में उनकी सहायता व उनकी रहनुमाई बर्मा के लिए बहुमूल्य साबित हुई है। आज विश्व की घटनाएं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की आजादी के लिए खतरा साबित हो रही हैं। इसलिए इन देशों का एक-दूसरे के निकट आना अत्यावश्यक है।''

सीमित साधनों से कितना लड़ेगा ईरान

यहां स्कैन करें

शशांक | पूर्व विदेश सचिव

अगर ईरान अमेरिकी ठिकानों पर कोई जवाबी कार्रवाई करता है, तो जैसा राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, अमेरिका की तरफ से उस पर और अधिक हमले हो सकते हैं।

ना-ना कहते हुए भी अमेरिका आखिरकार इजरायल-ईरान युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो ही गया। वह काफी समय से इस संकट के कूटनीतिक समाधान की वकालत कर रहा था। ईरान के साथ परमाणु समझौते के लिए उसने 60 दिनों का वक्त भी दिया था। मगर जब बात बनती नहीं दिखी, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बी-2 बॉम्बर को ईरान भेजना मुनासिब समझा।

इस युद्ध में अमेरिका की सीधी सहभागिता के कयास इसलिए भी नहीं लगाए जा रहे थे, क्योंकि विकसित देशों में यह सोच है कि यदि ईरान अस्थिर होता है, तो पूरे क्षेत्र, विशेषकर मध्य एशिया पर इसका खतरनाक असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, इतिहास यह भी बताता है कि अमेरिका यहां के जिन-जिन मसलों में सीधे तौर पर शामिल हुआ, वहां उसे पूरी सफलता नहीं मिल सकी, फिर चाहे वह इराक हो, सीरिया हो या फिर अफगानिस्तान। एक तर्क यह भी दिया जा रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति और अमन के हिमायती हैं, यहां तक कि पद संभालते ही उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने का दावा किया था। हां, वह इसमें सफल नहीं हो सके, लेकिन माना यही जा रहा था कि वह शायद ही कोई नया मोर्चा खोलना पसंद करेंगे।

अब जब उन्होंने हमला बोल दिया है, तो नजरें ईरान पर टिक गई हैं कि वह किस तरह की प्रतिक्रिया देता है? फिलहाल, ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर इस युद्ध को बढ़ा दिया है, और अब उसे जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। संकेत साफ है, अमेरिका को ईरान करारा जवाब देना चाहता है। उसने खाड़ी में स्थित अमेरिकी बेस को भी निशाने पर लेने की बात कही है। अगर ईरान ऐसा करता है, तो मुमकिन है कि जैसा राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, अमेरिका की तरफ से ईरान पर और अधिक हमले हो सकते हैं। तो, क्या ईरान इसके लिए तैयार है?

जवाबी प्रतिक्रिया के रूप में ईरान की संसद ने रणनीतिक रूप से अहम उस होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने का फैसला किया है, जहां से लगभग 1.7 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। दरअसल, यह एक संकरा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी व अरब सागर से जोड़ता है। चूंकि फारस की खाड़ी से निर्यात होने वाले कच्चे तेल का करीब-करीब 85 फीसदी हिस्सा इसी जलमार्ग से आता है, इसलिए इसकी अहमियत काफी ज्यादा है। हालांकि, ईरान के लिए इसकी नाकेबंदी करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे इजरायल, अमेरिका ही नहीं, उसके मित्र देशों को भी खासा नुकसान होगा। यहां तक कि चीन को भी दिक्कतें पेश आएंगी, जो उससे तेल लेता रहा है।

इसी कारण यह उम्मीद की जा रही है कि ईरान शायद ही अमेरिका से साथ युद्ध आगे बढ़ाना चाहेगा। हां, इजरायल के साथ वह मुकाबला करता रहेगा, हालांकि इसको भी रोका जाना चाहिए। दोनों देशों में तनातनी इसलिए है, क्योंकि इजरायल मानता है कि हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसे संगठन मूलतः ईरान-समर्थित हैं और तेहरान परोक्ष रूप से आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है।

संयुक्त राष्ट्र ने भी तुरंत संघर्ष-विराम करने का आह्वान किया है। सैन्य हस्तक्षेप को पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस संघर्ष के और अधिक अंतरराष्ट्रीयकरण से बचने की अपील की है। इसका क्या असर होता है, यह तो अगले कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन आतंकवाद एक मुद्दा जरूर है। भारत ने पिछले दिनों गाजा संघर्ष-विराम पर संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग से खुद को दूर कर लिया था, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले की आलोचना इस्लामी देशों ने उस तरह से नहीं की, जैसी उम्मीद थी। वे पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा करने से बचते दिखे थे।

हालांकि, भारत इस संघर्ष के खाड़ी क्षेत्र पर पड़ने वाले असर से वाकिफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत ईरान के राष्ट्रपति से बात भी की है। अगर यह प्रयास सफल होता है, तो भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। दरअसल, ईरान को भड़काने वाले कई देश हैं। कुछ ने तो परमाणु हथियार बनाने में मदद करने की बात भी कही है। हालांकि, मुमकिन यह भी है कि मदद का भरोसा देने वाले देश वास्तव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की थाह लेना चाहते हों। ऐसा पूर्व में हो भी चुका है, जब पाकिस्तान उसे मदद देने की बात कहकर मुकर गया था। यहां तक कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर पिछले दिनों अमेरिका भी गए और माना जा रहा है कि ईरान पर हमले में उन्होंने अमेरिका की मदद भी की है।

ऐसे में, आगे ईरान के पास क्या विकल्प हैं? अगर वह अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता है, तो पड़ोसी देशों में अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे पूरे क्षेत्र पर असर पड़ेगा। ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में शांति बनाए रखना काफी जरूरी है। दूसरा, वह अपने छद्म गुटों से हमलों को अंजाम दिला सकता है। वह पहले भी ऐसा करता रहा है। तीसरा, इजरायल पर उसका हमला जारी रह सकता है। अमेरिकी हमले के बाद भी ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं।

जाहिर है, खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन परमाणु युद्ध का खतरा फिलहाल नहीं लगता, क्योंकि किसी पक्ष ने इसकी चेतावनी नहीं दी है। अगर ईरान की परमाणु क्षमता अमेरिकी हमले में बच भी गई हो, तब भी मिसाइल द्वारा उसके इस्तेमाल की कितनी ताकत ईरान के पास रह बची है, उस पर सवाल बना हुआ है। यह मान भी लें कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं, तब भी वह शायद ही इसका अभी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमाणु क्षमता से संपन्न होने के बावजूद पाकिस्तान की हैसियत इस्लामी देशों में वैसी नहीं बन सकी है, जैसी ईरान, सऊदी अरब या तुर्किये की है। यही कारण है कि ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करके अस्थिरता को न्योता देने के बजाय अन्य मामलों में अपना दबदबा बनाए रखना चाहेगा।

वैसे भी, ईरान को अपनी आंतरिक चुनौतियों से अभी जूझना है। मोसाद ने जिस तरह से उसके घर में घुसकर कार्रवाई की, उससे यह संदेह पुख्ता होता है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के इस्लामी शासन के शायद ही सभी पक्षधर हैं। अभी ईरानी शासक अपने लोगों की भावनाओं का भी आकलन कर रहे होंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भाजपा-तेदेपा की नजदीकियां, दूरियां और कुछ मजबूरियां

दक्षिण एक्सप्रेस

यहां स्कैन करें

एस. श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नया आकर्षक सहयोगी मिला है। इस नई राजनीतिक जोड़ी को लेकर दोनों तेलुगुभाषी राज्यों में अटकलों का बाजार गर्म है।

बीती 17 मई को नारा लोकेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ प्रधानमंत्री से उनके नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर मिले। इस मौके पर मोदी ने 2024 के संसदीय चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में नारा की 3,132 किलोमीटर की पदयात्रा पर केंद्रित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। पिछले हफ्ते भी नारा लोकेश सपरिवार प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और लगभग दो घंटे वहां रहे। जारी तस्वीरों में से एक में प्रधानमंत्री मोदी चंद्रबाबू नायडू के पोते व नारा के बेटे को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। इन तस्वीरों का आंध्र में जबरदस्त असर हुआ है और टीडीपी का एक उत्साहित वर्ग नायडू से नारा को अपना उत्तराधिकारी बनाने की मांग करने लगा है। हाल में विश्व योग दिवस पर नारा लोकेश ने विशाखापट्टनम में भारी भीड़ जुटाई, जिसमें मोदी भी शामिल हुए थे। यह समारोह इतना विशाल हुआ कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा गया। इससे नारा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि इस जुटान को लेकर मोदी ने उनकी संगठनात्मक क्षमता की खुलकर प्रशंसा की और उनके प्रयासों के लिए उन्हें बधाई दी। अपने दिल्ली दौरे के दौरान नारा ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी कई बैठकें कीं।

समय का पहिया ऐसा घूमा कि चंद्रबाबू नायडू को जितनी नरेंद्र मोदी की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा मोदी के लिए नायडू जरूरी बन गए।

केंद्र के साथ मधुर संबंध होने के बावजूद चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लिए कोई विशेष मांग करने से परहेज बरता है। यहां तक कि अपने सपनों की नगरी अमरावती के लिए भी उन्होंने केंद्र से कोई विशेष मांग नहीं की है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को एक मेगा सिटी के रूप में विकसित करना नायडू का सपना है। इसके लिए केंद्र से उन्हें सिर्फ बहुपक्षीय एजेंसियों से कर्ज लेने की गारंटी मिली हुई है।

चंद्रबाबू नायडू साल 2014 से ही भाजपा के साथ शह-मात का खेल खेलते रहे। मगर इस बीच, समय का पहिया ऐसा घूमा कि नायडू को जितनी मोदी की जरूरत बनी, उससे कहीं ज्यादा मोदी के लिए नायडू जरूरी बन गए। तब से दोनों ओर से रिश्ते मधुर बने हुए हैं। नायडू अकड़ दिखाने के बजाय नियमित रूप से दिल्ली का दौरा कर केंद्रीय नेतृत्व को लुभाने की कोशिश करते हैं। इससे राजनीतिक पंडितों को आश्चर्य हो रहा है। मगर यह उतना ही साफ है कि नायडू के पास विकल्प सीमित हैं। अपने तेजतर्रार व ताकतवर प्रतिद्वंद्वी जगन मोहन रेड्डी को रोकना है, तो उन्हें यह सब करना होगा। चंद्रबाबू नायडू की उम्र भी बढ़ रही है। उन्हें लगता है कि अगली पीढ़ी के नेता को कमान सौंपने का समय आ गया है।

विदेश से बिजनेस में स्नातक नारा लोकेश राजनीति में सक्रिय नहीं थे। वह अपने पिता की डेयरी कंपनी हेरिटेज का प्रबंधन संभाल रहे थे। लेकिन सितंबर 2023 की एक घटना ने उनके करियर को बदल दिया। नायडू गिरफ्तार हुए और करीब 54 दिनों तक जेल में रहे। तब नारा ने टीडीपी की कमान संभाली। राज्य में 2024 में टीडीपी की सरकार बनने पर उन्हें आईटी और मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। टीडीपी के हाल ही में संपन्न कडप्पा सम्मेलन में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि नारा को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी, मगर नायडू की चुप्पी ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे की ताकत व कमजोरी, दोनों को समझते हैं। मगर मोदी द्वारा लोकेश को आगे बढ़ाने से परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। अब उन्हें केंद्र में पार्टी का चेहरा माना जाने लगा है। सवाल है कि मोदी उन्हें क्यों आगे बढ़ा रहे हैं?

असल में, भाजपा उन्हीं राज्यों में आगे बढ़ रही है, जहां कोई क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में है। वह उसके साथ गठबंधन करती है और अपना आधार मजबूत कर लेती है। आंध्र के क्षेत्रीय दल- टीडीपी व जन सेना के साथ अभी भाजपा गठबंधन में है। जब तक वह इस राज्य में अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर लेती, तब तक किसी बड़ी पार्टी के वारिस को अपने साथ रखने से बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है उसके लिए?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

खुद को क्या छलना

वह एक अभिनेता था, जिसने कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, परंतु वह अब भी इतना तरुण था कि उसमें जिज्ञासा थी। उसने पूछा, कोई अभिनय किसलिए करता है? कुछ के लिए तो रंगमंच जीविका का साधन मात्र है, कुछ व्यक्तियों को यह उनके दंभ को अभिव्यक्त करने का साधन देता है तथा दूसरे कुछ लोगों के लिए विविध भूमिकाएं निभाना एक बड़ा उद्दीपन होता है। रंगमंच जीवन की वास्तविकताओं से एक शानदार पलायन भी पेश करता है। मैं इन सभी कारणों से अभिनय करता हूं और शायद इसलिए भी कि मुझे आशा है कि रंगमंच द्वारा मैं कुछ शुभ कर पाऊंगा।

क्या अभिनय से स्व को, अहं को अधिक बल नहीं मिलता? हम भंगिमाएं प्रस्तुत करते हैं, चेहरे पहनते हैं और धीरे-धीरे वह भंगिमा, वह चेहरा हमारी दैनंदिन आदत बन जाता है, जिससे अंतर्विरोध, लोभ, द्वेष इत्यादि के अनेक अहं ढक जाते हैं। जो आदर्श है, वह तो एक भंगिमा, मुखौटा है, जो असलियत को ढक देता है। क्या कोई रंगभूमि द्वारा कुछ शुभ कर सकता है?

क्या आपका तात्पर्य है कि कोई ऐसा नहीं कर सकता? नहीं, यह प्रश्न है, निर्णय नहीं। नाटक लिखते समय लेखक की विशिष्ट धारणाएं, मंशाएं रहती हैं, जिनको वह संप्रेषित करना चाहता है; अभिनेता माध्यम है। उनके द्वारा लोगों का मनोरंजन या शिक्षण होता है। क्या इस शिक्षण से कुछ शुभ होता है या लेखक द्वारा ईजाद किए गए भले या बुरे, बुद्धिमान या मूर्खतापूर्ण प्रारूप के अनुसार मन को संस्कारित मात्र किया जाता है?

हे ईश्वर, इस सबका तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। देखिए, अभिनय में पूरी तरह से खो जाने से पहले मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि अभिनय मेरे जीवन की रीति बनने वाला है या नहीं?

क्या कोई और इसका निर्णय कर सकता है कि किसी के जीवन की रीति कैसी होनी चाहिए? कोई भी गतिविधि, जो स्व पर, अहं पर जोर देती है, विनाशकारी होती है; वह दुख ही लाती है। मुख्य मुद्दा यही है। है न? आपने पहले कहा कि आपकी इच्छा कुछ शुभ करने की है, परंतु जब किसी भी व्यवसाय अथवा गतिविधि से जाने-अनजाने अहं को पोषण और सातत्य मिलता हो,

जब किसी भी व्यवसाय अथवा गतिविधि से जाने-अनजाने अहं को पोषण और सातत्य मिलता हो, तो निश्चित मानिए कि उससे शुभ की संभावना नहीं है।

तो निश्चित मानिए कि उससे शुभ की संभावना नहीं है।

तो क्या समस्त कर्म अहं के कायम रहने पर ही आधारित नहीं है? शायद सदैव नहीं। बाहर से कभी ऐसा दिख सकता है कि कोई कर्म अहं को संरक्षित करने वाला है, परंतु भीतरी तौर पर हो सकता है कि वह वैसा बिल्कुल न हो। अन्य लोग इस संदर्भ में क्या कहते या सोचते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति को अपने आप को छलना नहीं चाहिए और मनोवैज्ञानिक मसलों में आत्म-छलावा बहुत आसान होता है।

जे कृष्णमूर्ति

राजनाथ सिंह | केंद्रीय रक्षा मंत्री

भारत ने विश्व को शस्त्र नहीं, शास्त्र दिए हैं और योग हमारा सबसे प्रभावशाली शास्त्र है, जो न शोर करता है और न दिखावा, बस खामोशी से इस दुनिया को बदल रहा है।

अमेरिका का ईरान पर अनुचित हमला

परमाणु अप्रसार के नाम पर अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला वैधता और नैतिकता के दृष्टिकोण से बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध पहले ही भयानक और विनाशकारी स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसे संवेदनशील समय में अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला किसी भी अंतरराष्ट्रीय मानदंड या नैतिक दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस कदम न केवल पश्चिम एशिया, बल्कि पूरी दुनिया को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा किया है। हर राष्ट्र को अपनी संप्रभुता की रक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। ईरान भी अपने क्षेत्रीय हितों और रणनीतिक समीकरणों के तहत कार्य करता है। लेकिन अमेरिका द्वारा उसकी भूमि पर सैन्य कार्रवाई करना न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि यह उसकी दुनिया की चौकीदारी करने की पुरानी मानसिकता का ही खतरनाक उदाहरण है। अमेरिका का यह हस्तक्षेप उस समय और अधिक आपत्तिजनक हो जाता है, जब वह स्वयं को मानवाधिकार, शांति व लोकतंत्र का झंडाबरदार बताता है। हकीकत यह है कि उसका हर दूसरा सैन्य कदम वैश्विक अशांति को जन्म देता है। चाहे वह अफगानिस्तान हो, इराक, सीरिया या अब ईरान। इजरायल-ईरान संघर्ष की आग में ईंधन डालना न तो शांति का रास्ता है, न स्थायित्व का। इसलिए अमेरिका इस युद्ध को बढ़ावा देने के बजाय, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए, ताकि विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त हो।

अमृतलाल मारू, टिप्पणीकार

ईरान-इजरायल युद्ध में अमेरिका का शामिल होना बिल्कुल अनुचित है। अमेरिका शक्तिशाली देश है और सभी देश उसे अभिभावक के रूप में देखते हैं। एक अभिभावक हमेशा सही राह पर चलने को प्रेरित करता है। अमेरिका को यह सोचना चाहिए कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध कैसे समाप्त हो, न कि खुद युद्ध में शामिल होकर विनाश को बढ़ावा देना चाहिए। युद्ध किसी भी देश के लिए सही नहीं है। इससे सिर्फ विनाश होता है और निर्दोषों के जान-माल का नुकसान होता है। एक घर में अगर लोगों के बीच झगड़े हों, तो घर का मुखिया उन्हें समझाता है और उनके बीच सुलह करवाता है। ठीक उसी प्रकार, अमेरिका से सभी की यही उम्मीद थी। परंतु, यहां तो वह खुद ही युद्ध में शामिल होकर तबाही का मंजर सजा रहा है। मध्य एशिया में जो युद्ध हो रहा है, इसे सिर्फ चंद लोग ही रोक सकते हैं। इन लोगों में पहले नंबर पर खामेनेई हैं और दूसरे नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

अनुलोम-विलोम

ईरान-इजरायल युद्ध

खामेनेई को अब चेत जाना चाहिए

इजरायल पिछले कई महीनों से ईरान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहा था। इस तैयारी में अमेरिका उसके साथ था। यूरोप के कुछ ताकतवर मुल्कों का भी उसे साथ मिला। मगर ईरान पर हमले का समय करीब आया, तो उसी समय पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला करा दिया। गुस्से में भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर दी। अचानक एक ऐसा मोर्चा खुल गया, जिसके लिए टीम अमेरिका तैयार नहीं थी। तुरंत भारत और पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया। मामले को शांत किया गया। यह मेरा अनुमान है। ऐसा इसलिए हुआ होगा, क्योंकि ईरान पर सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। बात आगे बढ़ेगी, तो पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले में होगा। वह अमेरिका के लिए पहले भी जरूरी था और अब तो और भी जरूरी है।

टीम अमेरिका यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि ईरान को मदद पहुंचाने के लिए चीन किसी भी तरह पाकिस्तान की धरती और आसमान का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस लिहाज से मौजूदा समय में अमेरिका और यूरोप के लिए पाकिस्तान, भारत से कहीं अधिक जरूरी है। पाकिस्तान सैन्य प्रमुख को व्हाइट हाउस में दावत भी इसीलिए दी गई और पाकिस्तान को आर्थिक मदद भी इसी वजह से मुहैया कराई गई है। अगर ईरान पर हमले की तैयारी नहीं होती, तो भारत-पाकिस्तान का मामला इतना जल्दी शांत नहीं होता। ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में यूरोप के कई ताकतवर मुल्क अमेरिका और इजरायल के साथ हैं। फ्रांस अपनी नौ-सेना के जहाज इजरायल की रक्षा के लिए पहले ही भेज चुका है। ब्रिटेन भी साथ है। जरूरत पड़ी, तो ये सब मिलकर लड़ेंगे। जब ये मिलकर लड़ेंगे, तब ईरान इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। चीन और रूस भी तेहरान को हथियार भेजने और बेचने से अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे।

ईरानी हुकूमत सन् 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही इजरायल के खिलाफ एक परोक्ष युद्ध लड़ रही थी। फर्क सिर्फ इतना आया है कि यह युद्ध अब इनके दरवाजे पर आ गया है। जब तक इजरायल में बम फट रहे थे, गाजा में बम गिर रहे थे, तब तक इन सबको मजा आ रहा था। अब बम ईरान पर गिर रहे हैं, तो सबको घबराहट हो रही है। चुपचाप तमाशा देख रही इस्लामी दुनिया अब युद्ध के मुहाने पर है। ईरानी हुकूमत ने बिना शर्त बातचीत का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया और खामेनेई ने आत्म-समर्पण नहीं किया, तो ईरान की जमीन पर युद्ध होगा, जो बहुत भयावह होगा। क्या ईरान के लोग इसके लिए तैयार हैं?

समरेंद्र सिंह, टिप्पणीकार

10 करोड़ लोगों को अब तक उद्योग अनुरूप आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा चुका है स्किल इंडिया मिशन के तहत, वर्ष 2015 से अब तक। इसका संचालन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किया जाता है।

आजकल

सरकारी कामकाज में बढ़े हिंदी का उपयोग

हाल में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री और हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से हिंदी देश के बड़े भूभाग में रहने वाले लोगों के बीच सर्वाधिक स्वीकार्य भाषा है। ऐसे में हिंदी को सर्वग्राही बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसे केवल विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में चर्चा-परिचर्चा करने तक सीमित रखना सही नहीं है, बल्कि देश की एक बड़ी जनसंख्या को इस अभियान का हिस्सा बनना होगा

कुंवर प्रांजल सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर,
जाकिर हुसैन कालेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय

अक्षेश राजपूत

हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह एक सेतु है जो विविधताओं से भरे इस देश को भावनात्मक एकता प्रदान करती है। आज हिंदी की व्यापकता का दायरा केवल अनुशासनात्मक ही नहीं रह गया है, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में हिंदी को अनुशासनात्मक ढांचे में कैद करने के बजाय उसे सर्वग्राही बनाने की आवश्यकता है। जिससे बहुभाषीय लोकतंत्र में भाषा के सवाल से जुड़े समानता, ज्ञान और भागीदारी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 43.6 प्रतिशत आबादी ने हिंदी को अपनी मातृभाषा बताया और लगभग 58 प्रतिशत लोग हिंदी को अपनी पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु विडंबना यह है कि करोड़ों भारतीयों की मातृभाषा होने के बावजूद वह ज्ञान और संवाद की मुख्यधारा में अब भी अधूरी उपस्थिति लिए खड़ी है।

स्वाधीनता के बाद से हिंदी का विकास क्रम अन्य भारतीय भाषाओं के विकास क्रम और औपनिवेशिक शासन के दौरान स्वयं हिंदी के विकासक्रम से गुणात्मक रूप से भिन्न रहा है। किसी जमाने में हिंदी एक खास भाषाई संस्कृति से जुड़ी हुई थी, लेकिन देश की राजनीतिक आकांक्षाओं ने स्वातंत्र्योत्तर विकास से उसे काट दिया। इससे हिंदी की विकास यात्रा और उसके सर्वग्राही बनने का फायदा और नुकसान दोनों हुआ। एक तरफ हिंदी अधिक बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अपना ली गई तो वहीं दूसरी तरफ वह अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की राह तलाशने लगी। इसी तलाश में हिंदी ने अवधि, भोजपुरी, ब्रज, मारवाड़ी, हरियाणवी, मैथिली और उर्दू से अपने-अपने बौद्धिक एवं सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत किया। यही कारण भी रहा कि देशी भाषा भाषी वर्ग लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही लगभग सभी राज्यों में अपने संख्या बल को राजनीतिक सत्ता में रूपांतरित कर पाई है। ऐसे में जरूरी है कि हिंदी को सर्वग्राही बनाने के साथ-साथ संवादधर्मी भाषा के रूप में रूपांतरित किया जाए। इसके लिए तीन शर्तें महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं।

हिंदी को ज्ञान की भाषा के साथ जोड़ना : हिंदी को सर्वग्राही बनाने की पहली शर्त है कि इसे ज्ञान की भाषा के साथ जोड़ा जाए। अंग्रेजी भाषा को ही बौद्धिकता का पर्याय मान लिया जाता है जिस कारण ग्रामीण परिवेश से आए विद्यार्थियों को दोयम दर्जे का समझा जाता है। जैसा कि शिक्षा मंत्रालय ने भले ही मातृभाषाओं में शिक्षा देने की बात कही हो, लेकिन जमीनी ढांचे और पाठ्यसामग्री का आज भी घोर अभाव है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का वजूद तभी गहराई पाएगा, जब ज्ञान का सृजन हिंदी में होगा। इससे हिंदी का एक नया मानचित्र तैयार होगा जिसमें क्षेत्रीय भाषा को भी एक मजबूत आधार मिलेगा। हालांकि, समाज के लगातार बढ़ते हुए राजनीतिकरण की प्रक्रिया ने हिंदी को उन मंचों पर आसीन कर दिया है, जहां पहले उनकी आवाज अंग्रेजी के वर्चस्व में दब जाती थी। लेकिन आज लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के पटल पर की जा रही राजनीतिक बहसों में हिंदी ने क्षेत्रीय भाषाओं के साथ गठजोड़ कर लिया है।

वस्तुतः विधायिकाओं में अनुवाद की मशीनी व्यवस्था होती है, परंतु हिंदी भाषियों की बढ़ती संख्या की मूल बातों को समझने के लिए गैर हिंदी भाषी सांसदों के बीच हिंदी सीखने का एहसास बढ़ता जा रहा है। संसदीय परिदृश्य में आया यह भाषाई परिवर्तन जिस तरफ इशारा करता है, वह है भारतीय अभिजनों के दायरे में 'हिंदी मीडियम टाइप' के लोगों की संख्या का बढ़ जाना। इसे एक हालिया प्रकाशित उपन्यास 'हिंदी मीडियम टाइप' में भी रेखांकित किया गया है। इस परिवर्तन को मैकाले के खिलाफ बगावत के रूप में न देखकर इसे मध्य भारत की दावेदारी के रूप में समझा और देखा जाना चाहिए। यह भारत को भावनात्मक एकता में जोड़ने का सांस्कृतिक पक्ष भी है। जिसका एक उदाहरण हर वर्ष की भांति 15 अगस्त, 1996 को दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराए जाने से जुड़ा है। उस समय देश के प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा थे। देवगौड़ा हिंदी न बोल पाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री की हैसियत से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के लिए किए जाने वाले संबोधन के लिए उन्होंने हिंदी को चुना। उनके द्वारा किए गए इस प्रयास को जनमानस के बीच गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। आज हिंदी के बढ़ते सार्वजनिक दायरे में यह प्रयास एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में मौजूद है।

बौद्धिक संपर्क : हिंदी के प्रसार और महत्ता में बढ़ोतरी का एक उल्लेखनीय आयाम यह है कि उसने विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच बौद्धिक संपर्क साध कर हिंदी के दायरे को विस्तृत कर दिया है। इस क्षेत्र को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अनुवाद ने निभाई है। भारतीय भाषाओं में आपस में अनुवाद करने के लिए हिंदी में अनूदित कृति को आधारभूत पाठ्यक्रम बनाने का रुझान अपने चरम पर है। पूरब और दक्षिण की कई महान कृतियों का अनुवाद केवल हिंदी में उपलब्ध है। हिंदी भाषा पर शोध कर रहे एक बौद्धिक का मानना है कि यदि किसी भी कृति का उर्दू से पंजाबी में अनुवाद करना हो या मराठी का तेलुगु में अनुवाद करना हो, या बांग्ला का उर्दू में अनुवाद करना हो, तो यह प्रक्रिया हिंदी के माध्यम से ही हो सकती है। समाज विज्ञान के क्षेत्र में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जा सकती है।

दरअसल, विचार साहित्य का क्षेत्र विकसित करने के लिए हिंदी के पास अच्छी खासी सामग्री है। पिछले लगभग 50 वर्षों में बौद्धिक राजनीतिक साहित्य हिंदी में खूब प्रकाशित हुए। संपूर्ण गांधी वांड्मय, डा. भीमराव आंबेडकर संग्रह, संपूर्ण लोहिया साहित्य, पंडित दीनदयाल संग्रह, धर्म संबंधी साहित्य बड़े पैमाने पर हिंदी के पास विद्यमान है।

राजनीति और समाज : तीसरी शर्त राजनीति और समाज की भूमिका से संबंधित है। हिंदी का समाज के साथ संबंध त्रिकोणीय है जो संवाद, पहचान और पहुंच से मिलकर बना हुआ है। जिसके माध्यम से हिंदी ने सांस्कृतिक उपकरणों को समाज की सामूहिक स्मृतियों को बनाने में मदद की। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी एकजुटता का प्रतीक बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी और बाद में रामधारी सिंह दिनकर जैसे लेखक और कवियों ने सामाजिक प्रश्नों को हिंदी में ही स्वर दिया। हिंदी पत्रकारिता ने भी 1857 की क्रांति से लेकर आज तक सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार और जनआंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। आज हिंदी का सर्वग्राहीकरण तभी संभव है, जब वह भारत के विविध अनुभवों, संघर्षों और विचारों को अपने में समाहित कर लिया जाएगा। इसके लिए लोक अनुभव पर आधारित वैकल्पिक ज्ञान परंपराओं को हिंदी में स्वर देना होगा। इस कड़ी में राजनीति और समाज की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हाल ही में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रशासन में हिंदी के प्रयोग की खुलकर वकालत करते हुए कहा कि चूंकि देश की अधिकांश जनता हिंदी नहीं जानती, इसलिए आवश्यक है कि सरकारी कामकाज हिंदी में किए जाएं। इससे जनमानस को आसानी से समझ में भी आए।

वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदी को राष्ट्रव्यापी संपर्क भाषा बनाने की बात कर चुके हैं। वह कार्यक्रमों में अंग्रेजी बोलने वालों को अक्सर टोकते हैं कि यदि यहां सभी लोग हिंदी आसानी से समझ रहे हैं तो उसी भाषा में बात होनी चाहिए। इसी क्रम में हिंदी के लेखक और अनुवादक अपनी वह पहचान हासिल करने में वृद्धि कर चुके हैं जिन्हें पहले समाज में बौद्धिक पूंजी के रूप में पहचान कम मिलती थी।

प्रकाशक भी समझें अपना उत्तरादायित्व

हिंदी पढ़ने-लिखने वालों की बढ़ती चाहत को 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में आए परिवर्तन के संदर्भ में देखा जा सकता है। हर साल होने वाले 'राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण' बताता है कि हिंदी प्रकाशनों ने प्रसार संख्या में अंग्रेजी प्रकाशनों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज विश्वविद्यालयों में हिंदी की स्थिति वह नहीं रह गई, जब किसी समाज विज्ञान की संगोष्ठी में हिंदी में विचार रखने वाले शोधार्थी और विद्यार्थी को अंग्रेजी सहपाठी और प्रोफेसर इस निगाह से देखते थे मानो कि ज्ञानियों की सभा में किसी अज्ञानी का प्रवेश हो गया हो। निश्चित रूप से यह हिंदी के विस्तार की सार्थकता को प्रोत्साहन प्रदान करता है।

जब हम हिंदी के भविष्य की बात करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विचारों की दुनिया में पुस्तकें ही सबसे सशक्त माध्यम हैं, और उन पुस्तकों को समाज तक पहुंचाने का कार्य प्रकाशक ही करते हैं। इसलिए यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि हिंदी प्रकाशक न केवल एक व्यवसायी हैं, बल्कि वे हिंदी संस्कृति के संवाहक और संरक्षक भी हैं। अक्सर यह देखा गया है कि हिंदी प्रकाशक लोकप्रियता और बिक्री की दृष्टि से निर्णय लेते हैं। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि वे उन लेखकों को मंच दें, जो समाज के जटिल प्रश्नों से जूझ रहे हैं, जो हिंदी को एक गंभीर, विचारशील और बौद्धिक भाषा के रूप में स्थापित कर सकते हैं।

प्रकाशकों को चाहिए कि वे सभी वर्ग को प्रकाशित करें। जब तक हिंदी में हर वर्ग की उपस्थिति नहीं होगी, तब तक उसका विस्तार अधूरा रहेगा। साथ ही, अनुवाद का कार्य भी हिंदी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विश्व साहित्य, अन्य भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियां और अकादमिक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद प्रकाशकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। आज समय की मांग है कि हिंदी प्रकाशक केवल बाजारोन्मुखी न होने के बजाय भाषा के सामाजिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विस्तार के वाहक बनें। तभी हिंदी एक जीवंत, समावेशी और समृद्ध भाषा के रूप में आगे बढ़ सकेगी।

(कुंवर प्रांजल सिंह)

खरी-खरी

भ्रष्टाचार विकास पार्टी

इरन सक्सा

इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना बहुत मुश्किल दिख रहा है। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि काफी हद तक इस पर अंकुश लगाने में कामयाबी मिली है। भ्रष्टाचारियों के लिए यह संकट का समय है। वे लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक व्यवस्था है जो उनके खिलाफ साजिश कर रही है। यही समय है जब छोटे-मोटे भ्रष्टाचारियों को एक होना है। इसके लिए एक पुख्ता संगठन की आवश्यकता है। मैं देश के सभी मूल्यहीन भ्रष्टाचारियों से अपील करता हूं कि वे मेरे झंडे तले एकजुट हो जाएं, ताकि मैं उनके जन्मसिद्ध अधिकार भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर सकूं। इसके लिए मैंने बाकायदा एक राजनीतिक दल का गठन किया है जिसका नाम 'भ्रष्टाचार विकास पार्टी' रखा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचारियों के अधिकार बहाल करने की दिशा में सार्थक कदम उठाएगी। यही समय है जब तमाम भ्रष्टाचारियों को एक होकर सदाचारियों को खदेड़ना है। इस समय एकता का परिचय नहीं दिया तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और यह नस्ल लुप्त हो जाएगी।

दरअसल अभी तक हो यह रहा है कि भ्रष्टाचारी भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में बिखरे पड़े हैं। कुछ बड़े दलों में हैं तो कुछ क्षेत्रीय दलों में। इतना ही नहीं, तमाम विभागों के प्रमुख अधिकारी से लेकर छोटे-मोटे सरकारी कार्यालयों के छोटे से लेकर बड़े कर्मचारियों के रूप में भ्रष्टाचारी विद्यमान हैं, परंतु संगठन के अभाव में उनकी आवाज दबा दी जाती है। हमारी पार्टी में उन तमाम नेताओं का भी हार्दिक स्वागत है, जो भ्रष्टाचार के मामलों में फंसकर अपनी छवि को दाग लगवा चुके हैं। उनको भी मैं इस पार्टी में सम्मिलित होने की दावत देता हूं। देश के सभी बाहुबली और डकैत भी इसमें यथा संभव चंदा देकर अपनी सदस्यता ले सकते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि आजकल भ्रष्टाचार को कायम रखना कितना जटिल हो गया है। इसलिए भ्रष्टाचार को बचाने के लिए हमें भ्रष्टाचार करने में भ्रष्टाचारियों को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इसलिए 'भ्रष्टाचार विकास पार्टी' आपको भ्रष्टाचार करने से रोकने वालों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान करती है।

पोस्ट

डोनाल्ड ट्रंप के लिए शांति के नोबेल की सिफारिश करने वाले पाकिस्तान ने भी ईरान पर उसके हमले की निंदा की है। पाकिस्तान नाम के इस मुल्क की सारी ऊर्जा इसी में खर्च हो रही है कि तारीफ और निंदा करके कहां से कितना उधार उठा लूं।

नितिन ठाकुर @thenitinnotes

जब मैंने पहली बार सुना कि आसिम मुनीर को ट्रंप ने इसलिए भोज पर बुलाया, क्योंकि उन्होंने नोबेल के लिए ट्रंप के नाम की अनुशंसा की। तब मुझे लगा कि यह मजाक या मीम है। बाद में जब इसकी पुष्टि हुई तो यही लगा कि ट्रंप की तुलना में बाइडन कहीं ज्यादा तार्किक थे।

मोनिका वर्मा @TrulyMonica

राजनीति में कभी कोई 'मरता' नहीं है। जनता कभी भी आपको आक्सीजन दे सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली थी। अब आम आदमी पार्टी दो सीटों पर उपचुनाव जीती। भाजपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने भी एक-एक सीट जीती।

आदेश रावल @AadeshRawal

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के भी शामिल होने से विश्व शांति के लिए खतरा और बढ़ गया है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या ईरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष बड़ा संकट खड़ा कर सकता है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

'बढ़िया' उन्नति कर रहा मरघट का व्यापार,
कब्र खुद रहीं हर तरफ धरि कुदाल में धार।
धरि कुदाल में धार चल रहे ड्रोन-मिसाइल,
ना कम है ईरान न कम दिखता इजरायल।
एटम बम को आज खिलौना समझे दुनिया,
बिके कफन-ताबूत आजकल 'बढ़िया-बढ़िया'!

- ओमप्रकाश तिवारी

उतम नाथ पाठक
संपादकीय प्रभारी,
जमशेदपुर

ओडिशा डायरी

रोजगार के नए अवसरों का सृजन

लगभग 24 वर्षों के बीजद के लंबे शासनकाल के बाद, पहली बार पूर्ण बहुमत में ओडिशा में आई भाजपा की सरकार पूर्व की नवीन पटनायक सरकार से बड़ी लकीर खींचना चाहती है। इसे लेकर माझी सरकार को केंद्र की मोदी सरकार कदम-दर-कदम साथ दे रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के विकास के लिए दो विजन डाक्यूमेंट तैयार किए गए हैं। कभी गरीबी और भूखमरी के कगार पर खड़ा ओडिशा अब निवेश के लिए देश-विदेश के उद्योगपतियों की पसंद बन गया है। माझी सरकार विकास की पटरी पर प्रदेश को और तेज दौड़ाना चाहती है। इसके लिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी माझी सरकार के एक साल के कार्यकाल में शपथ ग्रहण से अब तक आधा दर्जन बार ओडिशा आ चुके हैं। यह केंद्र सरकार की ओडिशा को लेकर प्राथमिकता बताने के लिए काफी है।

20 जून को माझी सरकार के एक साल पूरा होने पर भुवनेश्वर पहुंचे प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि ओडिशा आना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'अभी दो दिन पहले कनाडा में जी-7 समिट के लिए वहां गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया कि आप वाशिंगटन भी आइए। मैंने ट्रंप से कहा कि आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींचकर लाया है।'

ओडिशा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा केवल एक राज्य भर नहीं है। आने वाले समय में भारत के विकास का दिव्य सितारा है। उन्होंने भुवनेश्वर में लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने ओडिशा के विकास के लिए बनाए गए दो विजन दस्तावेज विकास ओडिशा 2036 और समृद्ध ओडिशा 2047 का अनावरण किया। इन दोनों दस्तावेजों को नीति आयोग के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसमें हर क्षेत्रवार लक्ष्य तय किए गए हैं। भुवनेश्वर से पारादीप तक मेट्रो जोन विकसित करना, लाजिस्टिक और पोर्ट हब बनाना, आधारभूत ढांचे पर बड़ा निवेश करना, शहरों को पूर्ण विकसित कर स्मार्ट सिटी बनाना आदि शामिल है।

हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा के प्रमुख नेता। फाइल

विजन डाक्यूमेंट के अनुसार सबसे बड़ा लक्ष्य ओडिशा की अर्थव्यवस्था को 2036 तक 500 अरब डालर तक पहुंचाना है। प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर अभी 7.2 प्रतिशत है। लौह अयस्क, क्रोमाइट, बाक्साइट, मैंगनीज के साथ तकरीबन साढ़े चार सौ किलोमीटर से अधिक लंबा समुद्री तट और मजबूत रेल एवं सड़क नेटवर्क है। सरकार का मानना है कि उद्योग, कृषि और तकनीक में निवेश से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। वहीं बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने पर सबसे अधिक जोर है। प्रदेश में सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई अड्डों का अधिक से अधिक विस्तार किया जाएगा। इसी दौरे में ही प्रधानमंत्री ने सोनपुर-पुरुनाकटक रेलवे लाइन, सरला-नर्सीन और झारसुगुड़ा-जामगा रेल लाइन का शिलान्यास व शुभारंभ किया। भुवनेश्वर में 100 इलेक्ट्रिक बसों के साथ राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन प्रणाली शुरू की गई। पुरी में केबल लैंडिंग स्टेशन और कोरापुट-केंदुझर में डाटा सेंटर बनाया जाएगा। व्यापार, पर्यटन और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम होगा।

विजन डाक्यूमेंट में उद्योग व रोजगार के नए अवसरों को तैयार करने पर जोर दिया गया है। स्टार्टअप, छोटे उद्योग और बड़े निवेश को बढ़ावा देने की योजना पर काम किया जा रहा है। दिसंबर, 2025 तक ईफो वैली में पहली सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाई शुरू हो जाएगी, जो मेक इन ओडिशा पहल का प्रमुख हिस्सा है। इसी तरह ग्रीन एनर्जी और आइटी क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इससे लाखों युवाओं को रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। सांस्कृतिक रूप से भी ओडिशा को समृद्ध बनाने की योजना है, इसमें बारापुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना के तहत ओडिशा के प्रमुख साहित्यकार, कवि व प्रसिद्ध हस्तियों के जन्मस्थानों में संग्रहालय, पुस्तकालयों में बदला जाएगा। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और अन्य ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को और आकर्षक बनाया जाएगा। इससे पर्यटन के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दरअसल विकास के कार्यों को लेकर माझी सरकार जिस तरह संकल्पित दिख रही है और केंद्र का भी उसमें सहयोग मिल रहा है, इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में ओडिशा विकासशील राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। दरअसल भाजपा सरकार 2029 के विधानसभा चुनाव में दोबारा पूर्ण बहुमत से वापसी के प्रयास में अभी से जुटी है।

मंथन

उद्योग अनुरूप कौशल विकास

शिक्षा प्राप्ति के पश्चात रोजगार की चाहत रखने वालों में बड़ी संख्या में लोगों के पास उद्योग अनुरूप कौशल का अभाव होता है। कौशल विकास से इस समस्या को दूर किया जा रहा है

डा. शशांक द्विवेदी
परियोजना प्रबंधक,
टीएसएससी,
कौशल विकास एवं
उद्यमिता मंत्रालय

भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश एक ऐसी ताकत है, जो यदि सही दिशा में प्रशिक्षित हो, तो देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान दिला सकता है। लेकिन इस ताकत को कुशलता (स्किल) में तब्दील करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। यही कारण है कि भारत में स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास को आज एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जा रहा है। चिंताजनक यह है कि देश में हर साल करोड़ों युवा शिक्षित तो होते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी होती है, जिनके पास रोजगार योग्य कौशल नहीं होते। दूसरी ओर, उद्योगों को ऐसे कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है, जो तकनीकी दक्षता के साथ उत्पादन और सेवा क्षेत्र की मांगों को पूरा कर सकें। इस गैप को भरने के लिए कौशल विकास की योजनाओं की अत्यधिक आवश्यकता है।

आज भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को तभी सही दिशा में उपयोग कर सकता है जब शैक्षणिक संस्थानों से निकलने वाले छात्रों के कौशल और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार 'स्किल इंडिया' अभियान के तहत प्रभावी दिशा में काम कर रही है।

आज जब देश 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की ओर तेजी से अग्रसर है, तब युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में दूरसंचार जैसे तेजी से उभरते और बदलते क्षेत्र में अकादमिक जगत और उद्योग के बीच की दूरी पाटने का काम टेलीकाम सेक्टर स्किल काउंसिल (टीएसएससी) कर रहा है।

टीएसएससी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसडीसी) के अंतर्गत काम करने वाला एक प्रमुख निकाय है, जो युवाओं को दूरसंचार क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करता है। इसकी पहल पर अब कई विश्वविद्यालय और कालेज अपने पाठ्यक्रमों में इंडस्ट्री आधारित स्किल ट्रेनिंग जोड़ रहे हैं, जिससे छात्रों को डिग्री के साथ-साथ नौकरी लायक कौशल भी मिल रहा है। टीएसएससी न केवल प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करता है, बल्कि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का भी निर्धारण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

अकादमिक संस्थानों से भागीदारी : टीएसएससी ने देशभर के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रमों को उद्योग-संबंधित बनाना है, ताकि छात्रों को समय रहते आवश्यक तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सके। टीएसएससी, विश्वविद्यालयों और कालेजों के साथ मिलकर उनके पाठ्यक्रमों में तकनीकी कौशल से संबंधित माड्यूल्स को शामिल करता है। इससे छात्रों को डिग्री के साथ स्किल प्रमाणपत्र भी मिलता है। छात्रों को दूरसंचार कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे वे वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकें।

उद्योग जगत की सहभागिता : टीएसएससी उद्योग जगत से नियमित संवाद करता है और उनकी आवश्यकताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित करता है। टीएसएससी के प्रशिक्षण प्राप्त छात्र अपेक्षाकृत कम समय में रोजगार प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास वह कौशल होता है जिसकी उद्योग में मांग है। उद्योगों को प्रशिक्षित और तत्पर कार्यबल मिलता है जिससे उनकी उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होती है। जब शिक्षा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप होती है, तब उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता दोनों बढ़ती हैं। हुनरमंद युवाओं के बीच नवाचार की भावना जागृत होती है जिससे वे नए स्टार्टअप्स की ओर भी अग्रसर होते हैं।

रोजगार की राह आसान : टीएसएससी के माध्यम से प्रशिक्षित छात्र अब पारंपरिक नौकरियों के साथ-साथ स्टार्टअप और स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, दोनों के युवाओं को समान अवसर मिल रहे हैं। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को उद्योग उन्मुख बनाना, ग्रामीण युवाओं तक प्रशिक्षण पहुंचाना और शिक्षकों को नवीनतम तकनीकी अपडेट देना कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर टीएसएससी निरंतर कार्य कर रहा है।

चुनौतियां : इस दिशा में कुछ चुनौतियां भी कायम हैं। जैसे ग्रामीण इलाकों में संसाधनों की कमी और छात्रों में जागरूकता का अभाव। लेकिन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सीएसआर फंडिंग और डिजिटल माध्यमों से इन समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है। टीएसएससी के इस माडल को भारत में शिक्षा और उद्योग को जोड़ने की दिशा में प्रभावी उपाय के रूप में देखा जा रहा है। इससे देश के रोजगार परिदृश्य में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है।

****

www.jagran.com | राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 24 जून 2025

दैनिक जागरण

अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं

संकट में विश्व

अमेरिका की ओर से ईरान के तीन परमाणु संयंत्रों को नष्ट किए जाने के बाद इजरायल ने भी इनमें से ही एक परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया। अमेरिका, इजरायल, यूरोपीय देशों और ईरान के हमदर्द-दोस्त समझे जाने वाले रूस और चीन के बयानों को देखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि ईरान का संकट बढ़ रहा है। इसी के साथ विश्व का भी संकट बढ़ रहा है, क्योंकि वे स्रोत और मार्ग बाधित हो सकते हैं, जो ऊर्जा उत्पादन एवं आपूर्ति के माध्यम हैं। ईरान भी ऊर्जा उत्पादन एवं आपूर्ति का एक केंद्र है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों से पूरी करता है। भारत ईरान में बंदरगाह भी तैयार कर रहा है। ईरान कहे और करे कुछ भी, वह असहाय सा दिख रहा है। चूंकि भारत के इजरायल और ईरान, दोनों से अच्छे संबंध हैं, इसलिए उसने सैन्य टकराव टालने पर जोर देने और तटस्थता का परिचय देना तय किया। फिलहाल यही उचित भी है। भारत को विश्व शांति के साथ अपने हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। इसलिए और भी, क्योंकि खुद को युद्ध विरोधी बताने और नोबेल शांति सम्मान की ललक रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के पक्ष में खड़े होकर ईरान पर परमाणु हथियार बनाने की जिद पकड़ने एवं आतंक का सबसे बड़ा समर्थक होने का दोष मढ़कर उस पर तो हमला बोला, लेकिन पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। यह आतंक के प्रति दोहरी नीति और भारत के हितों की अनदेखी है।

जैसे ईरानी सत्ता परमाणु हथियार हासिल करने के साथ हमास, हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों का साथ देती है, वैसे ही पाकिस्तान भी लश्कर, जैश आदि आतंकी गुटों को पालता है। यदि हमास, हिजबुल्ला इजरायल संग अमेरिका के लिए भी खतरा हैं, वैसे ही पाकिस्तानी सेना की ओर से पाले जा रहे लश्कर, जैश भारत के लिए। इससे ट्रंप परिचित भी हैं, क्योंकि ये आतंकी संगठन अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से भी प्रतिबंधित हैं। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप पाकिस्तान को धोखेबाज और आतंकियों को पालने वाला बता चुके हैं। आखिर उन्हें पाकिस्तान आतंक का दूसरा, तीसरा सबसे बड़ा समर्थक क्यों नहीं दिखता? यह देखने-समझने के बजाय उन्होंने हाल में पाकिस्तान के जिहादी सोच वाले सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका निमंत्रित किया और उनकी तारीफ भी की। क्या इसलिए कि अपने निजी स्वार्थ साध सकें या फिर पाकिस्तान को झांसा दे सकें? जो भी हो, लगता नहीं कि रूस या चीन जैसे देश ईरान के पक्ष में बयान देने के अलावा और कुछ कर सकेंगे। चीन की अपनी सीमाएं हैं और रूस पहले से ही यूक्रेन में उलझा है। यदि पश्चिम एशिया के हालात और बिगड़े तो विश्व शांति के साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरे बढ़ सकते हैं।

परीक्षा की अग्निपरीक्षा

प्रतियोगी परीक्षा के लिए युवा लंबे समय से तैयारी करते हैं। हर किसी को यही उम्मीद रहती है कि उन्हें भी नौकरी का मौका मिलेगा। इस समय आलम यह है कि एक-एक पद के लिए हजारों दावेदार होते हैं। इसी से प्रतिस्पर्धा का स्तर पता चल जाता है। इसी से यह भी पता चल जाता है कि युवा कितनी मेहनत कर ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे। कई तरह की बाधाओं को पार करने के बाद पहुंचे अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलता तो निराशा और बढ़ जाती है। रविवार को हिमाचल प्रदेश में जूनियर आफिस असिस्टेंट (आइटी) की परीक्षा देने से सैकड़ों अभ्यर्थी वंचित रहे। कुछ युवा जाम में फंसे तो कई स्थानों पर वर्षा ने कदम रोके। देरी से पहुंचने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिला। यह सही है कि तय समय पर न पहुंचने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। अभ्यर्थियों की समस्या को जानने के बाद परीक्षा कराने वाली संस्था को नियमों में कुछ ढील देने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। इस तरह की परिस्थितियां कभी-कभार ही सामने आती हैं। यह भी उचित नहीं है कि परीक्षा केंद्र तक देरी से पहुंचने के लिए व्यवस्था को दोष दें। परीक्षा केंद्र की तिथि, स्थान और समय की जानकारी पूर्व में ही दी जाती है। आशा है कि सरकार इस समस्या को समझेगी और कोई सर्वमान्य हल निकालने के लिए प्रयास करेगी।

वर्षा एवं यातायात जाम के कारण परीक्षा से वंचित रहे अभ्यर्थियों को राहत देने पर विचार करना चाहिए

जब जेल जैसा बन गया था देश

केसी त्यागी

आपातकाल के तहत अदालत जाने के अधिकार के साथ देश के नागरिकों के कई मौलिक अधिकार भी निलंबित कर दिए गए थे। इससे दमन और बढ़ा

अशोक राजपूत

आज से 50 वर्ष पहले देश पर थोपा गया आपातकाल एक ऐसा कालखंड है, जो गांधी, नेहरू, पटेल आदि के परिश्रम से बनी कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी के पदमोह का शिकार बना। उन्होंने तानाशाही, ज्यादती, निरंकुशता के बलबूते लोकतंत्र एवं स्वाधीनता पर बेरहमी से प्रहार किया। यह राजनीतिक अपराध था। इंदिरा गांधी की ओर से थोपे गए आपातकाल के अध्याय की शुरुआत 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा के निर्णय से प्रारंभ होती है। 1971 के लोकसभा चुनावों में रायबरेली में इंदिरा का मुकाबला विपक्षी समाजवादी नेता राजनारायण से था। इंदिरा गांधी विजयी होती हैं, पर राजनारायण उनकी जीत को अदालत में चुनौती देते हैं। उन्होंने उन पर अपने निजी सचिव एवं सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर को चुनाव एजेंट बनाने, स्वामी अद्वैतानंद को 50 हजार रुपये घूस देकर निर्दलीय प्रत्याशी बनाने, वायुसेना विमानों का इस्तेमाल करने, चुनाव में डीएम और एसपी की अनुचित मदद लेने, वोटरों को शराब, कंबल बांटने आदि आरोप लगाए। जस्टिस सिन्हा ने श्रीमती गांधी का चुनाव रद कर छह वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया। उनके फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी और उन्हें पदोन्नति का भी प्रलोभन दिया गया था। वे टस से मस नहीं हुए।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद नैतिकता का तकाजा था कि इंदिरा इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करतीं, पर 12 जून को ही भीड़ ने उनके आवास के समक्ष जस्टिस सिन्हा को सीआइए एजेंट बताकर नारेबाजी की। तब गुजरात और बिहार में कांग्रेस सरकारों के खिलाफ जारी आंदोलन को जेपी दिशा दे रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आने पर इंदिरा के त्यागपत्र की मांग लेकर विपक्षी दल लामबंद होने लगे और 25 जून को रामलीला मैदान, दिल्ली में सभा रखी गई। यह सभा 20 को होनी थी, पर जेपी के दिल्ली आने के पहले ही यहां आने वाली उड़ानें अचानक रद कर दी गईं। अंततः सभा 25 जून को हुई। मैं लोकदल के प्रतिनिधि के रूप में वहां था। मंच का संचालन जनसंघ, जो बाद में भाजपा बनी, नेता मदनलाल खुराना कर रहे थे। जेपी ने इंदिरा सरकार को अवैध बताया और उनके इस्तीफे की मांग की तथा सरकारी कर्मियों एवं पुलिस वालों को 'असंवैधानिक सरकार' के आदेश न मानने को कहा। उन दिनों इंदिरा के बेटे संजय गांधी की सक्रियता बढ़ गई थी। वे आरके धवन, चौधरी बंसीलाल आदि से मिलकर विरोधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पर जोर दे रहे थे। कांग्रेस में एक गुट का नेतृत्व युवा नेता चंद्रशेखर कर रहे थे, जो जेपी से संवाद के समर्थक थे। उनके प्रयासों से जेपी की दो मुलाकातें श्रीमती गांधी से हुईं, पर वे बेनतीजा रहीं।

इंदिरा प्रेस के स्वतंत्र रुख से खफा थीं। 25 जून की रात 11:45 पर आपातकाल की घोषणा वाले अध्यादेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन के हस्ताक्षर कराए गए और अगली सुबह 6 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर उस पर मुहर लगाई गई। इंदिरा ने सुबह रेडियो संदेश दिया, 'भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने की जरूरत नहीं है...।' विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला 25 जून की मध्यरात्रि से कायम हो गया था। इन नेताओं की लिस्ट संजय गांधी और साथियों ने बनाई। तब अदालतों को भी निर्देश था कि बंदियों को जमानत न दी जाए। आपातकाल के तहत अदालत जाने के अधिकार के साथ नागरिकों के कई मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। 25 जून की रात या फिर अगले दिन गिरफ्तार होने वालों में जेपी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, बीजू पटनायक, पीलू मोदी और राजनारायण आदि थे। यह सिलसिला कायम रहा। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अखबारों के कार्यालयों की बिजली काट दी गई। 26 जून को दिल्ली से केवल वही अखबार दिखे, जिनके प्रेस बहादुरशाह जफर मार्ग पर नहीं थे। तमाम लोग 26 जून के बजाय 27 जून को जान पाए कि आपातकाल लग गया है। आपातकाल में सेंसरशिप के चलते कई पत्रकार गिरफ्तार हुए। सरकार विरोधी समाचार छपने बंद हो गए।

25-26 जून की रात जो नेता गिरफ्तारी से बच निकले, उनमें जार्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर, नानाजी देशमुख आदि थे। चरण सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा हलचल न थी। लोहिया ने समाजवादियों को लड़ना सिखाया था, पर चरण सिंह स्वतंत्र भारत में किसी आंदोलन के पक्षधर नहीं थे। आरिफ मोहम्मद खान(वर्तमान में बिहार के राज्यपाल, राजेंद्र चौधरी (सपा नेता) आदि के साथ मैं भूमिगत होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर रहा था। दो साथियों के साथ हमने एक पत्रिका 'प्रतिरोध' शुरू की। मैं और मेरे साथी पश्चिमी यूपी, हरियाणा, दिल्ली में इसे वितरित करते, पर पुलिस पीछे पड़ी थी।

दिसंबर में चरण सिंह के जन्मदिन पर मैं कई साथियों के साथ गाजियाबाद के घंटाघर से गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र चौधरी, सत्यपाल मलिक (पूर्व राज्यपाल) आदि भी गिरफ्तार हुए। कोर्ट-कचहरी का संचालन थानों से हो रहा था। हमें मेरठ जेल भेजा गया। प्रतिबंधित संगठनों के लोग भी जेल भेजे गए। उनकी गिरफ्तारी 'सत्ता पलटने के षड्यंत्र' में हुई। आरएसएस के गिरफ्तार पदाधिकारियों में रामलाल, राकेश जैन, दर्शन लाल अरोड़ा आदि थे। जेल में पहला दिन अन्य नेताओं से परिचय में गुजरा। जेल प्रशासन का रवैया बड़ा नकारात्मक था। हमें अक्सर 'तन्हाई' में भेजा जाता। पता चला कि ब्रिटिश शासन का जेल मैन्युअल अब भी चल रहा। जेल में हमें बड़े नेताओं के बारे में अफवाह भरे समाचार मिलते। जेल विचारों की भिन्नता कैसे भेदती है, इसकी मिसाल दिखी। आरएसएस और जमाते इस्लामी के लोग एक साथ खाना खाते और इकट्ठे त्योहार मनाते। मैं और कुछ साथी कई महीनों बाद 1976 में रिहा हो सके। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा, संजय समेत कांग्रेस पराजित हुईं। 25 जून 1975 को थोपा गया आपातकाल 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ।

(लेखक पूर्व सांसद हैं और आपातकाल में जेल में रहे)
response@jagran.com

नई ऊंचाई पर भारत-आस्ट्रेलिया संबंध

फ्रांसेस एडमसन

रणनीतिक स्पर्धा के कारण विश्व में बढ़े तनाव के इस दौर में एक स्थिर और समृद्ध क्षेत्र बनाने की जरूरत ज्यादा है

मेरी भारत यात्रा के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय है। आस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते आज नई बुलंदियों की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे रिश्ते सिर्फ व्यापार और निवेश तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हमारे बीच उस गहरे जुड़ाव को भी रेखांकित करते हैं, जो दोनों देशों के लोगों के बीच वर्षों से कायम है। मेरा अनुभव है कि दो देशों के बीच रिश्तों के लिए वक्त, धैर्य और एक-दूसरे को समझने की इच्छा भी चाहिए होती है। हमें यह भी देखना होता है कि मौजूदा परिस्थितियां किस तरह हमारे सोचने के तरीके और प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में आस्ट्रेलिया और विशेष रूप से दक्षिण आस्ट्रेलिया राज्य सरकार ने भारत के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। गत वर्ष भारत में दक्षिण आस्ट्रेलिया सरकार के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति इसका प्रमाण है कि भारत की हमारे लिए कितनी ज्यादा अहमियत है। इस वर्ष के आरंभ में हमारे व्यापार और निवेश मंत्री जो स्जाकस और (प्रीमियर) पीटर मालिनौस्कस की भारत यात्रा इसका उदाहरण है। हम भारत के साथ मिलकर ऐसे कदम उठाना चाहते हैं, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हों। शिक्षा में साझेदारी, हरित अर्थव्यवस्था में निवेश, पानी के बेहतर प्रबंधन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान या फिर हवाई, कृषि-खाद्य और पर्यटन की बात हो, आस्ट्रेलिया और खासकर दक्षिण आस्ट्रेलिया प्रांत को न सिर्फ भारत, बल्कि पूरा दक्षिण एशिया भरोसेमंद साझेदार मान सकता है।

दीर्घकालिक निवेश के लिए भी दक्षिण आस्ट्रेलिया एक विश्वसनीय और लाभकारी साझेदार है। हम अपने यहां शांति और स्थिरता को बनाए रखने के साथ गर्म होती जलवायु की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हरित ऊर्जा, निर्माण और कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में नए समाधानों की तलाश में जुटे हैं। हमारे यहां भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में हैं, जो हमारे समाज की विविधता को और अधिक बढ़ाते हैं। ये लोग हमारे रिश्तों की मजबूत नींव हैं। शिक्षा के जरिये भी हमारे रिश्ते और गहरे हो रहे हैं, क्योंकि भारत आस्ट्रेलिया के इस हिस्से में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है। मेरी हालिया

जी-20 सम्मेलन में मोदी संग आस्ट्रेलिया के पीएम। फाइल

यात्रा का एक लक्ष्य शिक्षा क्षेत्र से भारत के जुड़ाव को और मजबूत बनाना भी है। आस्ट्रेलिया और भारत की अर्थव्यवस्थाएं कई मामलों में एक-दूसरे की पूरक हैं, खासकर अंतरिक्ष, सूचना तकनीक, एआइ और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में। ये क्षेत्र न सिर्फ भारतीय युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि दोनों देशों में नौकरियों और नए आविष्कारों के दरवाजे भी खोल रहे हैं।

हाल में आस्ट्रेलिया के उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स नई दिल्ली में थे। उन्होंने आस्ट्रेलिया-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पांचवीं सालगिरह मनाई, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमारी साझेदारी की नींव है। 2022 के आस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने दोनों देशों के बीच व्यापार को नई रफ्तार दी है। आस्ट्रेलिया और भारत अब इसे व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी से जुड़े करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिन्हें संयुक्त रूप से विकसित किया जा सकता है। आस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष नई और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान का समर्थन करता है।

हमारी अर्थव्यवस्थाओं की परस्पर पूरकता आस्ट्रेलिया और भारत को एक-दूसरे का स्वाभाविक साझेदार बनाती है। आस्ट्रेलिया द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक संसाधन हैं, जो दक्षिण आस्ट्रेलिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन दिनों दक्षिण आस्ट्रेलिया प्रांत की अर्थव्यवस्था भी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। हमारे यहां स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, कृषि और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर आधारित उद्योगों में काफी प्रगति हुई है। आस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी और आस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट आफ मशीन लर्निंग जैसे विश्वस्तरीय संस्थान हमारे यहां हैं। हमने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नवाचार परिसर स्थापित किए हैं, जो कई विश्वस्तरीय कंपनियों और स्टार्टअप का घर हैं। ये सभी विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षा परिसरों से कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित हैं। उनकी यह नजदीकी महज एक सुविधा नहीं है, बल्कि यह छात्रों को अध्ययन के दौरान विश्वस्तरीय कंपनियों के साथ व्यावहारिक अनुभव और संपर्क प्राप्त करने और भविष्य के नियोक्ताओं के साथ जुड़ने में भी सक्षम बनाती है। विश्वविद्यालय भागीदारी, खाद्य एवं वाइन मिशन, कृषि-प्रौद्योगिकी और सतत विकास में सहयोगी उपक्रमों के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहां हमारी पारस्परिक समृद्धि हमारे साझा मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित हो। आज जब दुनिया में रणनीतिक स्पर्धा के कारण तनाव और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, तब अपने साझेदारों के साथ मिलकर एक शांत, स्थिर और समृद्ध क्षेत्र बनाने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।

(आस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री रहीं लेखिका दक्षिण आस्ट्रेलिया प्रांत की गवर्नर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

स्वाभिमान

मनुष्य की असली पहचान उसके आत्म में निहित उस तेजस्विता से होती है, जिसे आत्मसम्मान कहा जाता है। यह केवल स्वाभिमान का भाव नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है, जहां व्यक्ति स्वयं को तुच्छ नहीं समझता, न ही किसी के चरणों में गिरकर कृपादृष्टि की भीख मांगता है। आत्मसम्मान वह अदृश्य किरण है, जो व्यक्ति को भीतर से संबल देती है, उसे संघर्षों के बीच भी अकुंठ और अडिग बनाए रखती है। आत्मसम्मान आत्ममूल्य की वह भावना है, जो न तो अभिमान है, न ही दंभ। यह एक संतुलित भाव है, जिसमें व्यक्ति अपने गुणों, मर्यादाओं और सीमाओं को समझते हुए स्वयं को अपमानित नहीं होने देता। यह भाव जन्म नहीं लेता, उसे अर्जित करना होता है। जीवन की अनेक परिस्थितियां, अपमान के अनगिन अवसर और भीतर पलते आत्मसंदेह, इन सबसे लड़ते हुए जो व्यक्ति स्वयं को दृढ़ बनाए रखता है, वही आत्मसम्मान का वास्तविक अधिकारी होता है।

आत्मसम्मान वह दीपक है, जो अपने भीतर जलता है। यह आत्मा की उस शुचिता का प्रतीक है जहां व्यक्ति किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है। स्त्री हो या पुरुष, आत्मसम्मान सभी के लिए उतना ही आवश्यक है, जितनी सांसें। एक बालक का अपने अधिकारों के प्रति सजग होना, एक स्त्री का अपनी गरिमा के लिए संघर्ष करना, एक मजदूर का अपने परिश्रम की उचित कीमत मांगना, ये सभी आत्मसम्मान के ही रूप हैं।

आत्मसम्मान एक आचरण है, जो विचारों से होता हुआ कर्म में उतरता है। जब व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देता है, तब वह भीड़ से अलग दिखता है और संतोष का पात्र बनता है, क्योंकि वह अपने आत्म के निकट होता है। अतः आत्मसम्मान को बचाकर रखना आज के युग में स्वयं को बचाए रखने के समान है। ऊंचे ललाट के साथ जीने की आकांक्षा ही आत्मसम्मान है।

कुमार नरेंद्र

डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा

सुनील मिश्रा

सरकार ने ई-कामर्स कंपनियों को अपने प्लेटफार्म से ग्राहकों को गुमराह करने वाले विज्ञापन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है

केंद्र सरकार ने सभी ई-कामर्स कंपनियों को तीन महीने के भीतर अपने प्लेटफार्म (वेबसाइट, मोबाइल एप्स) से डार्क पैटर्न हटाने और ग्राहकों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। वर्ष 2023 में सरकार ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और आनलाइन खरीदारी में अनुचित व्यवहार पर नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, ताकि डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। इसके बावजूद कई ई-कामर्स कंपनियां आनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों को झांसा देने के लिए नए-नए तरीके अपना रही हैं। डार्क पैटर्न उन डिजिटल तकनीकों और यूजर इंटरफेस डिजाइनों को कहा जाता है, जो उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ होते हैं। इनका इस्तेमाल उपभोक्ताओं को भ्रमित करके खरीदारी, सब्सक्रिप्शन या अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रेरित करने में किया जाता है। आफर सीमित समय के लिए है, अभी नहीं खरीदें तो चूक जाएंगे, फेक रिव्यू, जल्दी करें छूट खत्म होने वाली है, जैसे संदेशों को दिखाकर कंपनियां ग्राहकों को त्वरित निर्णय लेने के लिए मजबूर करती हैं।

कई कंपनियां उपभोक्ताओं के सामने झूठी जरूरत का माहौल बनाने, उनकी आनलाइन शापिंग कार्ट में अतिरिक्त उत्पाद जोड़ देने या डोनेशन करने और कोई उत्पाद एवं सेवा लेने के लिए दबाव बनाने की कंफर्म शेमिंग जैसी ट्रिक भी अपना रही हैं। इसके चलते ग्राहक न चाहते हुए भी ऐसी चीजें या सेवाएं खरीद लेते हैं, जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती। कंफर्म शेमिंग भी एक डार्क पैटर्न है, जिसमें प्लेटफार्म ग्राहक को गलत विकल्प चुनने के लिए गुस्सा या शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं, जिससे वे दबाव में आकर उस उत्पाद को लेने का निर्णय लेते हैं, जिसे वह नहीं लेना चाहते। यही नहीं कई प्लेटफार्म आनलाइन खरीदारी करने वालों को बिना पूरी जानकारी दिए सब्सक्रिप्शन ट्रैप में फंसा लेते हैं, जिससे वे अनचाहे खर्चों का शिकार हो जाते हैं। ड्रिप प्राइसिंग तकनीक के जरिए ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाता है। ड्रिप प्राइसिंग में शुरुआत में किसी उत्पाद की कुल लागत का केवल एक हिस्सा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन जैसे-जैसे ग्राहक खरीद प्रक्रिया के आखिरी चरण में आता है, उसे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।

आनलाइन खरीदारी आम नागरिक की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, लेकिन इसका दायरा बढ़ने के साथ ग्राहकों के सामने धोखाधड़ी और गुणवत्ता को लेकर कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में आनलाइन खरीदारी करते समय ग्राहकों को जागरूक रहना चाहिए, ताकि वे धोखाधड़ी से बच सकें। कोई भी आफर या सदस्यता लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें। उपभोक्ता संरक्षण कानून और आनलाइन खरीदारी से जुड़े अधिकारों के बारे में जानकारी रखें।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

समझनी होगी अमेरिकी मानसिकता

'अमेरिका की दबंग कूटनीति का दौर' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में शिवकांत शर्मा ने पश्चिम एशिया के वर्तमान घटनाक्रम और उसमें अमेरिका की कूटनीति का अच्छे से विश्लेषण किया है। वैश्वीकरण के इस दौर में देश अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसे में युद्ध कहीं भी हो उसका दुष्प्रभाव समूचे विश्व पर पड़ता है जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अविकसित और विकासशील देश होते हैं। लेखक का यह अनुमान कि इजरायली-अमेरिकी हमलों से ईरान में जगे राष्ट्रवाद की भावना के सहारे वहां के शीर्ष नेतृत्व का सत्ता में बने रहना कठिन नहीं होगा, बात सही है, पर अतीत में जिस तरह अमेरिका और इजरायल ने पश्चिम एशिया के देशों के शीर्ष नेतृत्व को बदला है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व का भी सत्ता में बने रहना वहां की जनता से ज्यादा अमेरिका और इजरायल पर निर्भर करता है। एक प्रश्न कि जैसी तत्परता अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने में दिखा रहा है, वैसी तत्परता उसने पाकिस्तान को परमाणु ताकत बनने से रोकने में क्यों नहीं दिखाई? इसकी कई वजहें हो सकती हैं। पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिका का पिछलग्गू देश रहा है तथा उसकी दयादृष्टि पर निर्भर रहता है। इसलिए अमेरिका को लगता है कि उसके लिए पाकिस्तान उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी बड़ी चुनौती ईरान है। अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति नरमी न बरते जाने पर वह पूरी तरह से चीन की गोद में जाकर बैठ जाता, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। अमेरिका पूरे विश्व में एकमात्र महाशक्ति बनकर वैश्विक पटल पर नेतृत्व करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि भारत जैसा कोई देश निकट भविष्य में महाशक्ति बनकर उभरे। इसके लिए भी वह पाकिस्तान को थोड़ा ताकतवर बनाकर अपना हित साधना चाहता है।

क्षितिज उपाध्याय, जलालपुर, जौनपुर

दोहरा रवैया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए कि ईरान आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का नंबर एक देश है और जो असल में ईरान से भी बड़ा आतंकी देश पाकिस्तान है, उसके जिहादी किस्म के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर की खातिरदारी की। सिर्फ ट्रंप का ही नहीं, अमेरिका का भारत के प्रति शुरू से आज तक दोहरा रवैया रहा है। ट्रंप बार-बार पाकिस्तान और भारत में सीजफायर करवाने का श्रेय ले रहे थे। उनके, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, और भारत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के झूठे दावों की पोल खुद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने यह कह कर खोल दी कि पाकिस्तान ने अमेरिका, साऊदी अरब से बात करने के बाद भारत से सीजफायर की अपील की, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। वहीं एनआइए ने आतंकियों को आश्रय देने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे। इसके बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि ईरान नहीं, आतंक का समर्थन करने वाला नंबर एक देश पाकिस्तान है।

सीपी बंसल, दिल्ली

इजरायल-अमेरिका की दोस्ती

इजरायल और अमेरिका की दोस्ती का सफर 28 मार्च 1949 से शुरू हुआ। तब से इजरायल अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी बना हुआ है। इजरायल और अमेरिका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ-साथ आपसी हितों से भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अमेरिका-इजरायल के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हैं, जो सालाना तीन बिलियन डालर से अधिक विदेशी सैन्य वित्तपोषण पर आधारित है। वित्तीय सहायता के अलावा, अमेरिका इजरायल के साथ उच्च स्तर के आदान-प्रदान में भाग लेता है, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य अनुसंधान और हथियार विकास शामिल हैं। संयुक्त आतंकवाद निरोधी समूह और अर्ध-वार्षिक रणनीतिक वार्ता के माध्यम से, अमेरिका और इजरायल ने आतंकवाद से लड़ने में अपने सहयोग को भी बढ़ाया है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHI/2017/74721

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

भारत की साफ्ट पावर

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भारत की 'साफ्ट पावर' के रूप में सामने आया है। दुनिया को 'हीलिंग' की आवश्यकता है और भारत ने योग के माध्यम से हृदय और आत्मा को इसे प्रदान किया है। इजरायल-ईरान युद्ध भड़कने तथा यूक्रेन युद्ध लगातार जारी रहने की स्थिति में 21 जून-अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एक राहत भरे क्षण के रूप में सामने आया जब दुनिया ने एकसाथ आ कर इस वैश्विक आंदोलन का उत्सव मनाया। इसकी जड़ें भारत में हैं और यह अब होलिस्टिक बेहतरी, शांति और सामूहिक चेतना का प्रतीक बन गया है। भारत अपने प्राचीन विवेक तथा विकसित होते 'वेलनेस इकोसिस्टम' से हीलिंग का वैश्विक केन्द्र बन कर उभर रहा है। योग भारत का दुनिया को असीम उपहार है जो दुनिया के सामने भारत की 'साफ्ट पावर' की स्वीकृति के रूप में उभर रहा है। योग न केवल अपनी भौतिक व चिकित्सकीय प्रासंगिकता, बल्कि आध्यात्मिक व दार्शनिक गहराई के लिए लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस पर याद दिलाया है कि भारत द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्रसंघ में 175 देशों का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ था। यह भारत के सांस्कृतिक एवं नैतिक नेतृत्व में दुनिया के विश्वास की याद दिलाता है। इस वर्ष की थीम 'एक धरती, एक स्वास्थ्य के लिए योग' है जो इस गहरी सच्चाई की ओर संकेत करती है कि व्यक्तियों की बेहतरी अभिन्न रूप से पृथ्वी ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ी है। योग शरीर और मन के बीच, मनुष्य एवं प्रकृति के बीच तथा स्वयं एवं समाज के बीच सामंजस्य की शिक्षा देता है।

टकराव, जलवायु संकट तथा बढ़ती मानसिक चिन्ताओं के बीच योग एक शांति का क्षण तथा गहरी सांस लेकर जीवन की आवश्यकता से जुड़ने और पुन: आंकलन का अवसर देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि योग हमें 'मैं' से 'हम' की ओर ले जाता है। यह एकता का ऐसा दर्शन है जो सीमाओं, विश्वासों और विचारधाराओं की सीमायें पार करता है। योग के माध्यम से भारत की 'साफ्ट पावर' का प्रभाव बढ़ रहा है। इससे वह दबाव के बजाय संस्कृति, मूल्यों और विचारों के माध्यम से प्रेरित करने और नेतृत्व करने में सक्षम होता है। योग अब पहाड़ों, नौसेना के जहाजों, जेलों और योग पाठों को ब्रेल लिपि में पढ़ने वाले दृष्टि दिव्यांग लोगों द्वारा किया जाता है। सिडनी के ओपेरा हाउस से लेकर एवरेस्ट के शिखर तक इसका संदेश समान है कि योग सारी मानवता का है। सत्ता की राजनीति से विभाजित दुनिया में भारत की अहिंसा, बेहतरी और आंतरिक परिवर्तन की विरासत नेतृत्व के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह गतिशीलता बनाए रखने के लिए भारत को प्रतीकात्मकता से आगे बढ़ते हुए वेलनेस के स्थाई वैश्विक इकोसिस्टम में निवेश करना चाहिए। इसमें विदेशों में सांस्कृतिक मिशनों के माध्यम से 'वेलनेस राजनय' को बढ़ावा देना, योग व आयुर्वेद के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केन्द्रों के निर्माण, इन तक सबकी पहुंच के लिए डिजिटल प्लेटफार्म बनाने तथा परंपरागत व्यवहारों के लिए वैश्विक स्तर पर स्वीकृत प्रमाणन व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। भारत को पर्यटन, स्वास्थ्यरक्षा और सांस्कृतिक पहलों को एकीकृत पहचान में समाहित कर देश को 'हीलिंग केन्द्र' के रूप में पेश करना चाहिए। भारत की आध्यात्मिक परंपरायें वैश्विक स्तर पर व्याप्त जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ विकास तथा मानसिक बेहतरी की समस्याओं का सामना कर सकती हैं। योग दिवस का आयोजन केवल 'आसनों' तथा बड़े आयोजनों तक सीमित नहीं है। इससे एक सभ्यतामूलक शक्ति के रूप में भारत की पहचान मजबूत होती है जिसकी जड़ें सद्भावना, संतुलन और विश्व बंधुत्व की भावना में निहित हैं। वर्तमान समय में अनेक आधारों पर विभाजित दुनिया 'हीलिंग' की ओर देख रही है और इस दृष्टिकोण से योग एक अनादि व शाश्वत मार्ग के रूप में उसके सामने आने है। योग की आत्मा एकता की भावना है जो अराजकता एवं अव्यवस्था में शांति प्रदान करती है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की दुनिया भर में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए हमें योग के और प्रसार पर जोर देना चाहिए।

नीति आयोग की विवादास्पद संस्तुति

नीति आयोग ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में जेनेटिकली परिवर्तित-जीएम कृषि आयातों को समर्थन की संस्तुति की है। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा तथा कृषि संप्रभुता प्रभावित हो सकती है।

अश्विनी महाजन
(लेखक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं)

कुछ दिन पहले एक वर्किंग पेपर में नीति आयोग ने भारत सरकार को संस्तुति की कि हाल में प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में जेनेटिकली परिवर्तित-जीएम कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें नीति आयोग ने खासतौर से मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों की बात की है। वर्किंग पेपर में सुझाव दिया गया है कि सरकार को उन कृषि उत्पादों का आयात भी खोलना चाहिए जिनका भारत में उत्पादन नहीं होता है या यह इतना कम है कि आयात का किसानों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस संबंध में वार्किंग पेपर में चावल, कालीमिर्च, सोयाबीन तेल, झींगा, चाय, काफी, डेरी उत्पादों, पोल्ट्री, सेब, बादाम, पिस्ता, आदि के उदाहरण भी दिए हैं जिनके आयात को खोलने की संस्तुति की गई है। वर्किंग पेपर में नीति आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के बाद किसान संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है जिनमें भारतीय किसान संघ-बीकेएस भी शामिल है।

इस संबंध में नीति आयोग की आलोचना करते हुए कहा गया है कि ये सुझाव सामान्य रूप से देश तथा खासतौर से किसानों के हित में नहीं हैं। बीकेएस ने कहा है कि ये सुझाव देश और किसानों के हित के खिलाफ हैं। उसने यह भी कहा है कि नीति आयोग ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं जो एक अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी ओर ये खबरें भी हैं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं में गतिरोध आ गया है क्योंकि सरकार बाजारों को अमेरिका के जीएम व अन्य कृषि उत्पादों के लिए खोलने पर तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में नीति आयोग के पेपर में सरकार का दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किया गया है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि नीति आयोग सरकार की जीएम-विरोधी स्थिति को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। ये दोनों स्थितियां देश के लिए अच्छी नहीं हैं। पहले भी नीति आयोग ने जीएम का समर्थन किया है। पहले भी नीति आयोग ने उपाध्यक्ष प्रो. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में जीएम फसलों के समर्थन में एक रिपोर्ट जारी की थी। उस समय भी इसका भारी विरोध हुआ था।

देश में लंबे समय से जीएम फसलों का विरोध हो रहा है। जीएम के पैरोकार लगातार जीएम के पक्ष में प्रयास करते रहे हैं, लेकिन जीएम के भारी विरोध तथा उनके पक्ष में मजबूत तर्कों के कारण जीएम समर्थक सफल नहीं हो पाए हैं। जीएम के विरोध के अनेक कारण हैं। पहला कारण यह है कि अधिकांश जीएम फसलें हर्बीसाइड या खरपतवार रोधी हैं। इसका अर्थ है कि इन फसलों के उगाने पर आसपास के सभी खरपतवार निर्धारित हर्बीसाइडों द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं और इनका जीएम फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

'इंटरनेशनल एजेंसी फार रिसर्च आन कैंसर'-आईएआरसी ने ग्लाईफास्फेट को 'मनुष्यों के लिए संभवत: कैंसरकारक' के रूप में किया है। जब ऐसे हर्बीसाइडों का प्रयोग जीएम फसलों को सुरक्षा देने के लिए किया जाता है तो उनके कुछ अवशेष कृषि उत्पादों तथा मृदा में बने रहते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में प्रति लाख जनसंख्या में 350 कैंसर रोगी हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा प्रति लाख केवल 100 है। इसका एक कारण अमेरिका में जीएम फसलों पर अत्यधिक हर्बीसाइडों का प्रयोग हो सकता है। हालांकि, भारत में जीएम खाद्य उत्पादों के प्रयोग और आयात पर प्रतिबंध है, पर खाने वाले तेलों की कमी के कारण अमेरिका तथा अन्य देशों से खाद्य तेलों का आयात करना पड़ा जिसमें से अनजाने की कुछ खाद्य तेल जीएम खाद्य तेलों का हो सकता है। भारत सरकार ने पहले ही यह स्थिति स्वीकार कर ली है। इसके कारण भारत में कैंसर के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2000 में जहां केवल 8 लाख कैंसर रोगी थे, 2024 में उनकी संख्या बढ़ कर 15 लाख हो गई। इसका एक कारण जीएम खाद्य तेलों का उपभोग हो सकता है। जीएम फसलों के आयात के विरोध का दूसरा कारण यह है कि देश के कानून के अनुसार इसके विधिक आयात की अनुमति नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमारे नियमों का सम्मान करते हुए दूसरे साझीदार देशों रा इस संबंध में कोई विवाद नहीं पैदा किया जा सकता है। डब्लूटीओ नियमों के अंतर्गत हर देश को दूसरे देशों से आने वाली वस्तुओं को प्रतिबंधित करने का अधिकार है क्योंकि यह उसके नागरिकों की स्वास्थ्यरक्षा अधिकार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत अमेरिका से आने वाले जीएम उत्पादों का भारत में प्रवेश रोका जा सकता है।

कुछ किसान पहले ही अपने उत्पादों के लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण वित्तीय घाटे का शिकार हैं। यदि सस्ते जीएम उत्पादों के आयात की अनुमति दी गई तो हमारे किसानों को नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में यदिकिसान खेती करना छोड़ दें तो भारत की खाद्य सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाएगी। तीसरा, जीएम उत्पादों की बिक्री खाद्य सुरक्षा नियमों के अंतर्गत संभव नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण-एफएसएसएआई द्वारा बनाए नियमों में अनिवार्य किया गया है कि खाद्य उत्पादों में एक सीमा से अधिक जीएम तत्व नहीं हो सकते हैं।

ऐसी स्थिति में जीएम उत्पादों के देश में आयात के बाद वे भारत में खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन जांएगे। यह न केवल देश के नियमों को तोड़ना, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करना होगा। इसके साथ ही देश में जीएम उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध का चौथा कारण यह है कि नीति आयोग ने जिन जीएम उत्पादों के आयात की संस्तुति की है उनका उपयोग आमतौर से अमेरिकन जनता नहीं करती है। अमेरिका में कार्न और सोया का प्रयोग पशु आहार या एथेनाल बनाने के काम में होता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में 40-50 प्रतिशत जीएम कार्न का प्रयोग पशु आहार के रूप में और 30-40 प्रतिशत एथेनाल बनाने के काम में होता है। इस प्रकार इसके केवल 10 प्रतिशत का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में होता है। इसी प्रकार सोया का प्रयोग भी अधिकांशत: पशु आहार के रूप में होता है। ऐसे जीएम उत्पादों का भारत की खाद्य श्रृंखला में प्रवेश न केवल देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बल्कि देश की जनता का अपमान होगा।

हालांकि, नीति आयोग लगातार जीएम उत्पादों की पैरोकारी कर रहा है, पर किसानों तथा देश में जागरूक वैज्ञानिकों के विरोध व इस संबंध में न्यायिक अनुमति के विरोध में वे सफल नहीं हो सके हैं। ऐसी स्थिति में जब अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, भारत में जीएम खाद्य पर प्रतिबंध का प्रयोग एक कवच के रूप में किसानों और डेरी के हित में किया जा सकता है। ऐसे में नीति आयोग की संस्तुति किसानों तथा देश की जनता के स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा के प्रति उनकी लापरवाही का प्रतीक है।

हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भारत लगभग 50 बिलियन डालर के कृषि उत्पादों का निर्यात अमेरिका को करता है और भारतीय खाद्य का एक आकर्षण उसका गैर-जीएम होना है। जैसे ही जीएम हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल होगा, हम अपने निर्यात का बड़ा हिस्सा खो देंगे क्योंकि मध्यपूर्व देशों, यूरोप तथा अनेक अन्य देश जीएम खाद्य पदार्थों की अनुमति नहीं देते हैं।

शायद नीति आयोग ने इस महत्वपूर्ण जोखिम पर गौर नहीं किया है जो भारत में जीएम आयात व उसके उत्पादन से जुड़ी है। भारत सरकार को नीति आयोग की इन संस्तुतियों को अनदेखा कर जीएम खाद्य पर प्रतिबंध को अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में एक तर्क की तरह प्रयोग कर कवच बनाना चाहिए। इससे हमारे किसानों, डेरी, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षा मिलेगी। लगता है कि देश के अधिकांश किसान संगठनों के विरोध के बावजूद जीएम समर्थक देश में किसी भी कीमत पर जीएम आयात की अनुमति दिलाना चाहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जैसे ही देश में एक बार जीएम आयात की अनुमति दी जाएगी, यह कृषि में जीएमओ के प्रवेश का आधार बन जाएगा। हमें ऐसे प्रयासों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है।

भारत की कूटनीतिक क्षमता की परीक्षा

"भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को तेज़ करने से एक प्रमुख व्यापार और ऊर्जा पुल के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी।"

मोनिका बी सूद
(लेखिका, भूराजनीतिक रणनीतिकार हैं)

इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष दशकों में दो मध्य पूर्वी देशों के बीच सबसे तीव्र प्रत्यक्ष सैन्य टकराव का प्रतीक है। 13 जून 2025 को, इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जिसमें नतांज, तबरीज और तेहरान के पास के क्षेत्रों में ईरान के परमाणु और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए 200 से अधिक विमान तैनात किए गए। कथित तौर पर हमलों ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को कई वर्षों तक पीछे धकेल दिया।

त्वरित जवाबी कार्रवाई में, ईरान ने इजरायली नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन झुंडों की लहरें लॉन्च कीं, जिससे हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर निकासी हुई। इजरायल की रणनीतिक गणना पूर्व-उत्पीड़न और निवारण पर केंद्रित है। तेहरान के दशक भर के परमाणु हथियारों की खोज का सामना करते हुए, इजरायल ने लंबे समय तक चलने वाले जमीनी अभियान के बजाय सटीक हवाई हमलों का विकल्प चुना इसके विपरीत, ईरान ने विषम युद्ध पर भरोसा किया है: इजरायल के शहरी केंद्रों पर 100 से अधिक मिसाइलों को लॉन्च करना, सीरिया, लेबनान और इराक में अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को जुटाना और अपने गतिज संचालन को पूरक बनाने के लिए साइबर हमले करना। घरेलू स्तर पर, ईरान में आर्थिक उथल-पुथल और बढ़ता सार्वजनिक असंतोष सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई पर कूटनीतिक बैक चैनल तलाशने का दबाव बना रहा है, भले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से जवाबी कार्रवाई की कसम खाई हो।

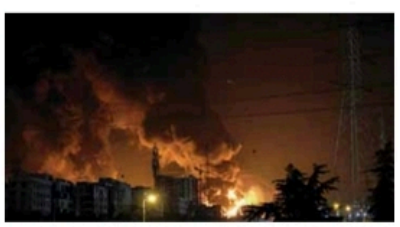

इजरायल-ईरान टकराव ने वैश्विक तेल बाजारों को हिला दिया है। जून की शुरुआत में, ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 10 डॉलर प्रति बैरल बढ़ गई, जो होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के डर के बीच 78 डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो एक महत्वपूर्ण

चोकपॉइंट है जहां से दुनिया के समुद्री तेल का पांचवां हिस्सा बहता है भारत, जो अपने कच्चे तेल का 80 से 85 प्रतिशत आयात करता है, के लिए इस तरह के मूल्य झटकों के तत्काल परिणाम होते हैं। 13 जून को, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप किया क्योंकि रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो महीने के निचले स्तर 86.20 रुपये पर आ गया था। ईंधन की बढ़ती लागत से व्यापार घाटा बढ़ने, घरेलू क्रय शक्ति कम होने और मुद्रास्फीति के दबाव को फिर से बढ़ने का खतरा है। फिर भी, वित्त वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित 7.5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि बाहरी झटकों को अवशोषित करने के लिए कुछ राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार की सक्रिय ईंधन हेजिंग रणनीति और विविध आपूर्तिकर्ता आधार आपूर्ति अस्थिरता के खिलाफ महत्वपूर्ण बफर प्रदान करते हैं। भारत ईरान और इजराइल दोनों के साथ मजबूत संबंध रखता है। तेहरान ऊर्जा और क्षेत्रीय संपर्क में एक रणनीतिक साझेदार बना हुआ है, विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह परियोजना के माध्यम से, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद मध्य एशिया तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही, भारत-इजराइल संबंध भी प्रगाढ़ हुए हैं, द्विपक्षीय व्यापार 7 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, रक्षा सहयोग गहरा हुआ है, तथा आतंकवाद निरोध पर खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान तीव्र हुआ है।

इस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ व्यापक रणनीतिक गठबंधन को बनाए रखते हुए किसी भी पक्ष को अलग-थलग करने से बचने के लिए कुशल कूटनीति की आवश्यकता है। भारत की दोहरी भागीदारी रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय कूटनीति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। तत्काल संकट प्रबंधन से परे, भारत के पास एक सक्रिय राजनयिक भूमिका निभाने का अवसर है।

अपनी आगामी जी20 अध्यक्षता और क्वाड के भीतर नेतृत्व का लाभ उठाते हुए, भारत एक पश्चिम एशिया स्थिरता वार्ता शुरू कर सकता है - एक तटस्थ मंच के तहत अरब लीग, यूरोपीय संघ, ईरान और इजराइल को शामिल करते हुए एक ट्रैक टू शांति प्रक्रिया। इसके साथ ही, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को तेज करने से एक प्रमुख व्यापार और ऊर्जा पुल के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों के साथ हरित हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा में साझेदारी को गहरा करने से तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता एजेंडे का समर्थन भी होगा। इजरायल-ईरान संघर्ष अनियंत्रित परमाणु प्रसार और छद्म युद्ध के खतरों को दर्शाता है। भारत के लिए, यह कूटनीतिक चपलता, ऊर्जा लचीलापन और आर्थिक दूरदर्शिता की परीक्षा है, साथ ही पश्चिम एशिया में एक बहुध्रुवीय, नियम-आधारित व्यवस्था को आकार देने में नेतृत्व का दावा करने का मौका भी है।

बहुपक्षवाद की वकालत करके, रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करके और अपने ऊर्जा संक्रमण को तेज करके, भारत न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है, बल्कि दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक को स्थिर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आप की बात

खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक

एक अध्ययन ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। उन्होंने पाया कि कांच की बोतलों में प्लास्टिक या धातु के डिब्बों की तुलना में 50 गुना अधिक माइक्रोप्लास्टिक कण मौजूद हैं। अधिकतर कण बोतलों के धातु ढक्कनों के बाहरी पेंट से मिलते-जुलते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पैकेजिंग सामग्री हमारी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिमी से भी छोटे होते हैं और अब समुद्र की गहराइयों से लेकर एवरेस्ट की चोटी तक और मानव मस्तिष्क, प्लेसेंटा, रक्त व अन्य अंगों में भी पाए जा चुके हैं। डिब्बाबंद खाद्य और पेय पदार्थों में इसके साथ ही प्रिजर्वेटिव्स और विषैले रसायन भी मौजूद होते हैं जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए अब ताजे खाद्य पदार्थों और घरेलू पेय को प्राथमिकता देना जरूरी हो गया है। प्राकृतिक रूप से तैयार नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजा फल हमारी सेहत के लिए कहीं बेहतर हैं। सिर्फ स्वाद या सुविधा के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घकालिक जीवनशैली की दृष्टि से भी हमें पैकेज्ड फूड और ड्रिंक्स को अलविदा कह देना चाहिए। ऐसी स्वस्थ जीवनशैली के लिए देश-दुनिया के स्तर पर सबको शामिल करने वाले व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है जिसमें उद्योग भी सहभागी बनें।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

अमेरिका का हमला

ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होते हुए अमेरिका ने फोर्दो परमाणु संवर्धन संयंत्र को बर्बाद करने के लिए अपने बहुचर्चित बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। आज अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश है जो इस भारी बम को अत्याधुनिक स्टील्थ बी-2 बमवर्षक से गिराने में सक्षम है। इन बमों को पहाड़ की गहराई में बने फोर्दो परमाणु केन्द्र को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने का सबसे अच्छा उपाय माना गया है। बंकर बस्टर बम दो सौ फुट तक जमीन में घुसकर किसी भी बंकर को उड़ा सकता है। कुछ देश तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता भले ही अमेरिका की सैनिक कार्रवाई की निन्दा करें, पर इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि ईरान द्वारा बनाए जाने वाले नाभिकीय बमों से न केवल इजरायल के अस्तित्व को खतरा था, बल्कि यह खतरा अमेरिका के साथ दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भी था। ईरानी तानाशाह जिस प्रकार दुनिया पर इस्लामी वर्चस्व स्थापित करने का सपना देख रहे थे तथा अनेक प्रकार के आतंकियों को पाल-पोस रहे थे, उसे किसी भी सभ्य व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए घातक ही कहा जा सकता है। ईरान की जनता व खासकर महिलायें उनके उत्पीड़न से त्रस्त हैं।

- **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

कमजोर वैश्विक संस्थायें

वैश्विक नियामक संस्थाएं, जैसे संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरपोल एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने उदय काल से ही निष्क्रिय साबित हुई हैं। दुनिया के इन संगठनों पर विश्व की उन्हीं महाशक्तियों का प्रमुख रूप से कब्जा रहा है जो अपने मनमाने आचरण एवं क्रियाकलाप से विश्व अर्थव्यवस्था एवं सामरिक परिस्थितियों को प्रभावित करते रहे हैं। आज दुनिया में कई देशों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। इन युद्धों को और व्यापक न होने देने तथा विश्व शांति बनाए रखने की दिशा में संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयास हकीकत में नजर नहीं आते हैं। दुनिया के स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सामरिक एवं सद्भावनापूर्ण पूर्ण संतुलन कायम रखने के लिए इन संस्थाओं का सुदृढ़ होना आवश्यक है। वैश्विक नियामक संस्थाओं में सभी प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इन संस्थाओं को इतना शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए कि दुनिया का प्रत्येक देश इनके निर्देशों को मानने के लिए बाध्य हो। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्रसंघ व खासकर सुरक्षा परिषद में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग कर रहा है। समय आ गया है कि दुनिया के सभी देश विश्व संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करें।

-**ललित महालकरी**, इंदौर

पुलिस के पूर्वाग्रह

एक तरफ मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर बड़ी दलीलें दी जाती है तो दूसरी तरफ बर्बरतापूर्ण कारवाई की घटनाएं इनके हनन की ओर गंभीर संकेत देती है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के कुंदी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत की भयावह याद ताजा कर देता है। दोनों मामलों में गिरफ्तारी के दौरान घुटने से गर्दन दबाने की क्रूर तकनीक सामने आई जिससे यह सवाल उठता है कि क्या कुछ पुलिस बल अब भी नस्ली प्रवृत्ति या पूर्वाग्रह के आधार पर कार्य कर रहे हैं। कुंदी की पत्नी का दावा कि वह हिंसक नहीं थे लेकिन पुलिस ने बताया कि उन्होंने विरोध किया। इन दोनों बयानों के बीच का अंतर न्यायिक जांच की मांग करता है। चाहे कोई व्यक्ति नशे में हो या न हो, उसे जीवन और सम्मान का अधिकार है। इन घटनाओं को देखते हुए जरूरी है कि हर देश के पुलिस प्रशिक्षण में मानवीय दृष्टिकोण को प्रमुखता दी जाए और ऐसे विवादास्पद तरीकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। कानून-व्यवस्था के नाम पर की गई अमानवीयता को सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं दिया जा सकता।

अमृतलाल मारू, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 24 जून 2025

पाक फिर बेनक़ाब

NIA की जांच ने पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोल दी है कि पहलगाम आतंकी हमले में उसका हाथ नहीं था। अब तो इस बात के सबूत हैं कि सीमा पार इस हमले की साजिश ही नहीं रची गई, आतंकवादी भी वहां से आए थे और उन्हें पाकिस्तानी इस्टैब्लिशमेंट का पूरा सपोर्ट था। इस खुलासे से पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का पक्ष मजबूत हुआ है।

आतंकियों के साथ पाक । राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उन दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को पनाह दी थी। इनमें से एक आतंकी की पहचान हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान के रूप में हुई है, जो पाकिस्तानी सेना में पैरा कमांडो रह चुका है। माना जा रहा है कि सेना ने मूसा को इस आतंकी मिशन के लिए ही लश्कर को दिया था। इससे एक बार फिर यह साबित होता है कि आतंकवाद पाकिस्तानी सेना की रणनीति का एक हिस्सा है और वह आतंकियों के साथ मिलकर काम करती है।

पहलगाम की साजिश रची

कार्रवाई सही साबित हुई । भारत का शुरू से कहना रहा है कि पहलगाम में पाकिस्तान शामिल है। उसके सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर यह घिनौनी वारदात हुई। यह खुलासा भारत के उन कदमों को सही ठहराता है, जो उसने पहलगाम के बाद उठाए थे - सीमा पार मौजूद आतंकी ढांचों को ध्वस्त करना और सिंधु जल समझौते का निलंबन।

दबाव बनाए भारत । टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली एजेंसी FATF ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि इतना बड़ा आतंकी हमला आर्थिक मदद के बिना संभव नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भारत अपनी बात मजबूती से रख सकता है। साथ ही, इससे पाकिस्तान पर लश्कर प्रमुख हाफिज सईद समेत उन आतंकियों पर कार्रवाई करने का भी दबाव बनाया जा सकता है, जिसे उसने अपने यहां छिपा रखा है।

चौतरफा घेरने का मौका । संसद पर हमला हो, मुंबई अटैक या फिर पठानकोट - हर बार पाकिस्तान की संलिप्तता सामने आई और इसके बावजूद उसने अपना टेरर अजेंडा नहीं छोड़ा। ऐसे में यह उम्मीद नहीं कर सकते कि पहलगाम मामले में वह सच को सहजता से स्वीकार कर लेगा या अपनी आदत बदल देगा। हां, इस मौके का इस्तेमाल उसे घेरने और अमेरिका जैसे देशों की आंखें खोलने के लिए कर सकते हैं, जिन्हें अब भी पाकिस्तान पर भरोसा है।

धूप-छांव

ये मद्धम आवाज़ें

प्रणव प्रियदर्शी

बड़ी-बड़ी बातों के बीच छोटी-छोटी बातें अक्सर खो जाती हैं। चाहे मसला घर-परिवार का हो या देश-दुनिया का। सबका ध्यान बड़ी-बड़ी बातों की ओर रहता है, जिनके नतीजे भी बड़े होने वाले होते हैं। अब अगर पति-पत्नी में टकराव चरम पर पहुंचता दिख रहा हो, तो घर के तमाम बड़े-बूढ़ों और दोस्त-मित्र-रिश्तेदारों का ध्यान तो इसी पर रहेगा कि कैसे इस अलगाव को रोका जाए या अलगाव अपरिहार्य है तो कैसे इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाए ताकि कड़वाहट हद से ज्यादा न बढ़े। बाल मन की दुविधा, उलझन और आशंकाओं की ओर, उसके आकाश जैसे अकेलेपन की ओर ध्यान देने की फुरसत भला किसे होगी। ऐसे ही जब दो देशों में लड़ाई छिड़ गई हो, बमों और मिसाइलों के जरिए एक-दूसरे की अक्ल ठिकाने लगाने की कोशिशें हर तरफ हावी हों तो बमों की आवाज से सहमते किसी चिड़िया के बच्चों की फिक्र भला कौन करे।

समाज का इकलौता ऐसा हिस्सा है कवियों, लेखकों और साहित्यकारों का। चूंकि उनकी चिंता के केंद्र में हमेशा संवेदना होती है, इसलिए वे इंसाफ से खुद को स्थायी तौर पर अलग नहीं कर सकते। जहां राजनीति का ध्यान सत्ता के बनते-बिगड़ते समीकरणों पर होता है, कूटनीति इन समीकरणों से प्रभावित होते हितों पर अपनी नजर टिकाए होती है, वहीं संवेदनशील मन इन्हीं छोटी-छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित किए रहता है और इसके लिए जान देने तक से नहीं हिचकता। सारे समझदार एक तरफ और ऐसा संवेदनशील मन एक तरफ। वह इस बात की चिंता नहीं करता कि बच्चे की मासूम आशंकाओं की फिक्र उसे एक-दूसरे के दुश्मन हो चुके माता और पिता की नजरों में ऐसा विलेन बना सकता है जो बच्चे की भावनाओं का इस्तेमाल कर दूसरे पक्ष का हित पूरा करना चाहता है। न ही वह इस बात की परवाह करता है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें उसके देश पर चढ़ बैठी हैं तब जनता के दुख-दर्द की बात करना उसे देशद्रोही बनाकर सीधे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। इस आग्रह से वह इत्तफाक नहीं रखता कि कि यह समय तानाशाही क्रूरता का बचाव करने, उसके साथ खड़े होने का है।

आप ईरान की लेखक बिरादरी के ताजा आह्वान में जनजीवन के सत्य, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और व्यापक मानवीय मूल्य- इन तीनों के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता की झलक देख सकते हैं। जरूरी है कि हम बड़ी-बड़ी बातों के दबाव में ऐसी मद्धम आवाजों को अनदेखा न करें।

बोल वचन

कटहल का कोआ

राहुल पाण्डेय

जून का महीना है, आम इसका राजा है। लेकिन इसी मौसम में पेड़ों से कटहल भी उतरता है। जितना बड़ा साम्राज्य आम का है, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण, कटहल का रकबा उससे कुछ कम नहीं है। आम की गुठली लगभग बेकार ही जाती है, कटहल की नहीं। अभी सहेजी

AI image

कटहल की गुठली सर्दियों में आग जलाकर भूनी जाती है, धनिये-मिर्च की चटनी के साथ खाई जाती है। लेकिन इस गुठली से पहले आता है कोआ। कोआ यानी पके कटहल का पीला, मीठा और मुलायम हिस्सा। महुए की तरह इसकी सुगंध भी मादक होती है। लेकिन कोआ सिर्फ कटहल का ही नहीं होता है। अवध में कटहल के अलावा सांप के छोटे बच्चे यानी संपोले को भी कोआ कहते हैं। अंगिका में कोना भी कोआ है तो सुरंग या छेद को भी कोआ कहते हैं। बज्जिका में कोआ ताड़ का भी होता है तो आंख का सफेद हिस्सा भी। ब्रज में यह रेशम के कीड़ों का घर है, तो टसर/तसर नाम का रेशम कीट भी। महुए का फूल है तो धुने हुए ऊन की पोनी भी है। कहीं-कहीं कोआ काक के लिए भी प्रयोग हुआ है, यानी कौए के लिए। मगही में कोआ लकड़ी की इंगुरौटी है, यानी सिंदूर रखने की काठ की डिबिया। संस्कृत से लोक में आए कोआ के इतने अर्थों के लिए जाहिर है कि अंग्रेजी को थोड़ा कटहल बनना होगा, कटहल बनकर पकना होगा।

बड़ी ताक़तों के बीच परमाणु युद्ध का डर काम करता है पर हूती, हमास और हिज़बुल्लाह का भरोसा नहीं

क्या न्यूक्लियर डिटरेंस अब भी प्रभावी है

चित्रापु उदय भास्कर

ईरान पर शनिवार को हमला करने के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि उसकी परमाणु संवर्धन क्षमताएं पूरी तरह से नष्ट कर दी गई हैं। इससे पहले इस्राइल ने ईरान पर यह कहते हुए 13 जून को हमला किया कि उसने IAEA सुरक्षा समझौते का पालन नहीं किया। विडंबना यह है कि इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल करने के करीब है। न्यूक्लियर डिटरेंस भले ही अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों के बीच एक हद तक असरदार बनी हुई है, लेकिन यूरोप और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध दिखाते हैं कि अब इस मामले में नई चुनौतियां आ चुकी हैं।

अलग-अलग असर । पश्चिम एशिया की बात करें तो इस्राइल के पास परमाणु हथियार होने की बात भले ही आधिकारिक रूप से न मानी गई हो, लेकिन दुनिया को मालूम है कि वह परमाणु ताकत है। शायद यही वजह है कि ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों का खुलकर इस्तेमाल नहीं किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो परमाणु धमकी अब भी असरदार है- लेकिन इसकी ताकत अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह से असर दिखा रही है। यह भी याद रखना जरूरी है कि हूती, हमास और हिजबुल्लाह जैसे गैर-सरकारी समूहों पर ये परमाणु धमकियां वैसा असर नहीं करतीं जैसा किसी देश पर करती हैं।

तनाव और खतरे । यूक्रेन पर रूस के फरवरी 2022 में हुए हमले के बाद से दुनिया में तनाव और परमाणु खतरों में साफ बढ़ोतरी देखी गई है। रूस ने बार-बार परमाणु धमकियां दी हैं- खासकर अमेरिका और नैटो को चेतावनी देने के रूप में कि वे यूक्रेन को ज्यादा सैन्य मदद न दें। रूसी नेता अब यह भी संकेत दे चुके हैं कि रणनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिए वे छोटे स्तर के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं- जैसे यूक्रेन को किसी क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर करना। यूक्रेन द्वारा रूस के परमाणु बमवर्षक विमानों वाले एयरबेस पर हमले भी सामने आए हैं, जिन्हें रूस ने बदले का कारण बताया है।

संतुलन के तरीके । ऐसे खतरों को कम करने के लिए सरकारें और सेनाएं कई तरीके अपनाती हैं- जैसे जापान के लिए अमेरिका की 'न्यूक्लियर अंब्रेला' नीति। सेनाएं युद्धाभ्यास भी करती हैं, जैसा रूस ने 2022 में किया था, ताकि विरोधी को यह संदेश मिल सके कि वे पूरी तैयारी में हैं। शांत कूटनीतिक बातचीत भी अक्सर होती है ताकि कोई गलतफहमी परमाणु युद्ध जैसी भयानक स्थिति में न बदल जाए। खुफिया निगरानी और रणनीतिक संवाद भी इस जोखिम को कम करने के अहम तरीके हैं।

युद्ध बढ़ने का खतरा । नए हथियार जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल और AI के आने से परमाणु युद्ध की आशंका और बढ़ गई है। हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बच निकलती हैं क्योंकि इनकी रफ्तार ध्वनि से पांच गुना (Mach 5) ज्यादा होती है। साथ ही यह पहचानना भी मुश्किल होता है कि मिसाइल में परमाणु वॉरहेड है या नहीं। इससे गलतफहमी और गलत कदम उठने का खतरा बढ़ जाता है। 19 जून को ईरान और इस्राइल के युद्ध के दौरान ईरान द्वारा इस्राइल पर दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइल कथित रूप से एक अस्पताल को लगी। इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे युद्ध का टर्निंग पॉइंट बताया। यह दिखाता है कि ऐसे हथियार हालात को और बिगाड़ सकते हैं।

नकली सच । इसके साथ ही अगर AI को विनाशकारी हथियारों (WMDs) के साथ जोड़ा जाए तो हालात और उलझ सकते हैं। AI एक ऐसा नकली 'रणनीतिक सच' दिखा सकता है जो किसी डरे हुए विरोधी को कार्रवाई के लिए उकसा दे। यह किसी परमाणु ठिकाने पर नकली मिसाइल हमला दिखा सकता है, जिससे सामने वाला देश घबराकर गलत फैसला ले सकता है।

परमाणु युद्ध का खतरा

- यूक्रेन युद्ध के बाद परमाणु हमलों के खतरे में हुई बढ़ोतरी
- AI के आने से गलतफहमी के चलते परमाणु हमलों का डर बढ़ा
- हाइपरसोनिक हथियारों के प्रयोग से बढ़ा कन्फ्यूजन

सहमति और नियम । आज यूरोप और पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहे हैं, उसमें चिंता की बात यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों में अब वह सहमति नहीं बची है जो शीत युद्ध में परमाणु हथियारों पर बनी थी। पहला सिद्धांत यह था कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ 'डर पैदा करने' के लिए होगा, कभी भी जमीन कब्जाने जैसे उद्देश्यों के लिए नहीं। दूसरा नियम था कि किसी भी परमाणु ठिकाने या नागरिक रिएक्टर पर हमला नहीं किया जाएगा।

टूटती मर्यादाएं । इन दोनों मर्यादाओं का उल्लंघन यूक्रेन युद्ध और इस्राइल-ईरान संघर्ष में हो रहा है। अगर ईरान के किसी परमाणु ठिकाने पर हमला होता है और वहां रेडियोधर्मी सामग्री होती है - तो इसका असर सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहेगा। यह आने वाले दशकों तक आसपास के पूरे क्षेत्र में लोगों की सेहत के लिए गंभीर संकट बन जाएगा। परमाणु विकिरण सीमाएं नहीं पहचानता। परमाणु शक्ति तबाही ला सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह नैतिक जिम्मेदारी आज भी बड़ी ताकतों पर है - लेकिन अफसोस, वे अब इस जिम्मेदारी पर खरी नहीं उतर रही हैं।

(लेखक रिटायर्ड नौसेना अधिकारी हैं)

ताऊ ने नचनिया को घूरा, मुंशी से बर्दाश्त न हुआ

आलोक सिंह भदौरिया

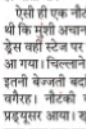

भारत एक कृषि प्रधान देश है, बचपन में पढ़ा था। लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ। बचपन से लेकर आज तक यही लगा कि हम लोग नाटक प्रधान देश हैं। केवल नाटक प्रधान ही नहीं वीर रस प्रधान भी हैं। इतना वीर रस प्रधान हैं कि प्रधानी का चुनाव तक बिना वीर रस के कंप्लीट नहीं होता।

आज से 50-60 साल पहले गांवों में नाटक, नौटंकी आता था। शादी ब्याह के सीजन में, फसल कटे तो उसके बाद, फसल बिके तो उसके बाद, तीज-त्योहार, चैत, सावन, कातिक मतलब हर सीजन में नाटक नौटंकी। उस नौटंकी में मेन होता था एक मुंशी, मुंशी मतलब आज का कॉमेडियन। गांव भर की जनता की आंख का तारा। उसकी एक-एक हरकत पर पब्लिक 'मैं वारी वारी जाऊं' हो जाती थी।

ऐसी ही एक नौटंकी में नाच हो रहा था, महफिल जमी थी कि मुंशी अचानक उखड़ गया। नौटंकी की चमकदार ड्रेस वहीं स्टेज पर उतार दी। एकदम लंगोट, बनियान में आ गया। चिल्लाने लगा, मैं जा रहा हूं, मुझसे नहीं होगा, इतनी बेज्जती बर्दाश्त नहीं, मेरा हिसाब कर दो वगैरह वगैरह। नौटंकी का मालिक मतलब आजकल का प्रड्यूसर आया। खूब हाथ-पैर जोड़े, पब्लिक भी सन्न। मस्त मजा चल रहा था, इसे क्या हो गया?

लेकिन मुंशी टस से मस न हो। माने ही न, पहले आधा गांव जुटा था, हल्ला सुनकर पूरा गांव जुट गया। जिसके

AI image

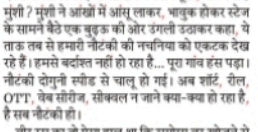

ऐवें कुछ भी

दरवाजे नौटंकी आई थी आखिर में उसने पूछा, बात क्या है मुंशी? मुंशी ने आंखों में आंसू लाकर, भावुक होकर स्टेज के सामने बैठे एक बुढ़ऊ की ओर उंगली उठाकर कहा, ये ताऊ तब से हमारी नौटंकी की नचनिया को एकटक देख रहे हैं। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है... पूरा गांव हंस पड़ा। नौटंकी दोगुनी स्पीड से चालू हो गई। अब शॉर्ट, रील, OTT, वेब सीरीज, सीक्वल न जाने क्या-क्या हो रहा है, है सब नौटंकी ही।

वीर रस का तो ऐसा हाल था कि सुयोग्य वर खोजने से पहले वधू पक्ष अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करता था। पड़ोसी राज्यों से संधि करता था कि फेरों से लेकर एटहोम तक अगर बवाल होता है तो हमारी तरफ से युद्ध कीजिएगा। वीर भोग्या वसुंधरा को चरितार्थ करने वाले बुंदेलखंड में आल्हा-उदल की कहानियों के चंद्रावल का डोला, आल्हा मनउआ, बेतवा की लड़ाई, इंदल हरण के कई एपिसोड मिल जाएंगे जिनके आगे रूस-यूक्रेन और इजराइल-ईरान वॉर फेल है। बस इसमें सावधानी इतनी रखी जाती थी कि वर महोदय को इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था।

मामला इतना समकालीन हो जाता है कि इंदल हरण में राजकुमारी चित्रलेखा बिना पासपोर्ट के सीधे बलख बुखारे से गढ़ बिठूर में गंगा किनारे आई थीं। युवा इंदल का अपहरण करके सीधे अपने घर ले गईं। आज के भूगोल के हिसाब से गूगल माई कहती हैं: ये दोनों मध्य एशिया के ऐतिहासिक शहर हैं। बलख, उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित है और प्राचीन काल में बैक्ट्रिया के रूप में जाना जाता था। यह सिल्क रोड पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। बुखारा, उज्बेकिस्तान में स्थित है और यह भी सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।'

लब्बोलुआब यह है कि नाटक-नौटंकी और वीररस प्रधानता भारतीय परंपरा में ऐसा रचा बसा है कि ब्रजबाला होली के रास में हुरियारों पर लाठी झाड़ने के बाद प्रेम से कहती है, लला फिर अइयो खेलन होरी। लला चोटें सहलाते हुए पुनः आने का वादा करते हैं। इसलिए जो रील, वायरल विडियो, शॉर्ट इत्यादि में प्यार और जूतम पैजार का कॉकटेल चल रहा है उसे प्रेम के साथ बिना अचकचाए ग्रहण कर लीजिए।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

अकेलापन डराता है, क्योंकि हमने उसे समझा नहीं

जे. कृष्णमूर्ति

हममें से अधिकतर लोग सोचते हैं कि खुशियां हमें तभी मिलेंगी, जब हमें मनपसंद चीजें मिल जाएं या कोई अपना हमारे पास हो। इसलिए जब हम अकेले होते हैं, तो किसी न किसी रिश्तेदार, मित्र या किसी जरूरी चीज की तलाश में लग जाते हैं, जिससे हमें सुख या संतोष मिल सके। लेकिन, सच यह है कि चाहे हम किसी से जुड़ भी जाएं, वह अकेलापन फिर भी हमारे भीतर कहीं गहराई में मौजूद रहता है।

हम इस अकेलेपन से डरते हैं। इसे समझने की बजाय, हम किसी न किसी चीज में उलझे रहना चाहते हैं, जैसे घर, सामान, रिश्ते, किताबें, पूजा-पाठ, मान्यताएं, रीति-रिवाज। हम सोचते हैं कि शायद इनमें से कोई चीज हमें सुख दे देगी। इसीलिए हम इन सब पर निर्भर हो जाते हैं और उनके जरिए अपने दुख या खालीपन को भरना चाहते हैं। दरअसल, हमारे भीतर जो बेचैनी, डर और खालीपन है, उसे भर नहीं पाते। हम उसे समझे बिना ही बस उसे छिपाने या उससे भागने की कोशिश करते हैं। हम हर बार कुछ नया पकड़ने की कोशिश करते हैं, किसी व्यक्ति, विचार या भावना को। लेकिन उस खालीपन की जड़ तक नहीं जाते। अगर मैं किसी से इसलिए जुड़ता हूं कि वह मुझे खुशी देगा, तो सच यह है कि मेरा मकसद उस इंसान से जुड़ना नहीं, बल्कि उसमें अपनी खुशी की तलाश है। तब वह व्यक्ति मेरे लिए केवल एक साधन बन जाता है। यही बात विचारों, सिद्धांतों और धार्मिक रीतियों पर भी लागू होती है।

इसलिए सवाल यह है कि क्या मैं अपने अकेलेपन को वाकई समझता हूं? क्या मैं उसे देख और स्वीकार कर सकता हूं जैसे वह है? हममें से अधिकतर किसी न किसी तरह के संगठन से जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या उससे अकेलापन मिट जाता है? शायद नहीं। वह गहराई में अब भी बना रहता है, छाया की तरह। हमें अकेलेपन से डर क्यों लगता है? शायद इसलिए क्योंकि हमने उसे कभी ठीक से समझा ही नहीं। हमने स्वयं को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया और मन में यह बैठा लिया कि दूसरों से ही समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि हमारा मन बस यह कहता रहता है कि अकेलापन बुरा है, डरावना है और इससे बचना चाहिए। इसी सोच से डर पैदा होता है और हम उस डर से भागने लगते हैं।

अगर हम अपने अकेलेपन को बिना डर, बिना किसी राय के, बस वैसे ही देख सकें जैसे वह है, तो हो सकता है कि हम उसमें कुछ नया जान पाएं। हो सकता है, वह अकेलापन ही हमारे भीतर की गहराई से हमें जोड़ दे, जहां न किसी चीज की जरूरत होगी, न किसी व्यक्ति की। आखिर में हम शांति की ओर भागते हैं। और यही हमारा लक्ष्य भी होता है। लेकिन गहराई से देखें तो शांति तब आती है जब हम अपने भीतर के खालीपन को समझ लेते हैं, न कि जब हम उसे भरने की कोशिश करते हैं।

विशुद्ध राजनीति

पॉलिटॉक

बिहार में 'दामाद आयोग'

बिहार में इन दिनों कई आयोगों में हुई राजनीतिक नियुक्तियां राजनीतिक विवाद का विषय बनी हुई हैं।

RJD नेता तेजस्वी यादव ने उसे चुनाव से पहले मुद्दा बनाने की कोशिश की है। उन्होंने इसे 'दामाद आयोग' का नाम दिया है। जीतन मांझी और चिराग पासवान के रिश्तेदारों के अलावा जेडीयू नेता और राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के रिश्तेदार को भी इसमें जगह मिली है। हालांकि पलटवार करते हुए जीतन मांझी ने भी तेजस्वी यादव को परिवारवाद पर घेरने की कोशिश की। लेकिन इन आरोप-प्रत्यारोपों के बीच खुद NDA के अंदर भी इन नियुक्तियों को लेकर असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं। खासकर, BJP नेताओं का एक वर्ग इस पर खफा है। वह इस फैसले का बचाव करने के मूड में नहीं है। ये नेता मानते हैं कि भले तेजस्वी यादव परिवारवाद के प्रतीक हैं, लेकिन उस कारण इस नियुक्ति को सही नहीं ठहरा सकते हैं। ये नेता अशोक चौधरी के उस बयान से भी नाराज हैं जिसमें उन्होंने कहा कि उनके दामाद को RSS कोटे से यह राजनीतिक नियुक्ति मिली है।

क्या पका रहे हैं चिराग

बिहार में चिराग पासवान को लेकर चर्चा का दौर जारी है। उनके तेवर को लेकर NDA में गहमागहमी है तो महागठबंधन में उत्सुकता। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या BJP से उनके रिश्ते ठीक हैं? इस सिलसिले में BJP के एक शीर्ष नेता ने पिछले दिनों अनौपचारिक मुलाकात में कहा कि पिछले कुछ दिनों से वह लगातार चिराग पासवान के संपर्क में हैं। बात और मुलाकात भी नियमित अंतराल पर होती रही है। फिर भी, उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आखिर चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं? वह इस बात से भी दूरी बना रहे थे कि उनके बदले हुए तेवर में BJP की कोई भूमिका है। दरअसल, 2020 चुनाव में जब चिराग पासवान NDA से अलग होकर चुनाव लड़े थे, तब कहा गया था कि इसके पीछे कहीं न कहीं BJP की ही शह है। यही कारण है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच कई महीनों तक सियासी रिश्ते ठीक नहीं थे। हालांकि, BJP के इस शीर्ष नेता ने यह भी स्वीकार किया कि चिराग पासवान के तेवर संकेत जरूर दे रहे हैं कि उनके मन में कुछ खिचड़ी पक रही है।

सांसद के मूड पर सवाल

एक क्षेत्रीय दल के राज्यसभा सांसद का रवैया क्यों बदल गया? जुझारू नेता ने अचानक सक्रिय राजनीति से दूरी क्यों बना ली? राजनीतिक गलियारे में यह सवाल पिछले कुछ महीनों से जोर पकड़ने लगा है। कभी वह अपने दल के सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी माने जाते थे। इतने करीबी कि बाकी दूसरे नेताओं को यह चीज अखरती भी थी। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह खुद को अपने नेता और दल से दूर करने लगे। हालांकि पार्टी या नेता के खिलाफ उन्होंने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के संघर्ष के समय साथ भी नहीं देखे गए हैं। अब उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। दिलचस्प बात है कि इस दल के कुछ और राज्यसभा सांसदों के तेवर इन दिनों पार्टी को ठीक नहीं लग रहे हैं।

अभी से सेटिंग

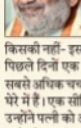

अब तक यही उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा में एक तिहाई महिला आरक्षण 2034 आम चुनाव से लागू होगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस बीच कई मौकों पर दावा किया कि हर हाल में इसे अगले चुनाव, मतलब 2029 से ही लागू किया जाएगा। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। किसकी सीट आरक्षण के दायरे में आएगी, किसकी नहीं- इस पर तरह-तरह के अनुमान लग रहे हैं। पिछले दिनों एक बड़े राजनीतिक समारोह में यही मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में था। बड़े-बड़े नेता अनिश्चितता के घेरे में हैं। एक सीनियर नेता ने तो सबके सामने कहा कि उन्होंने पत्नी को अभी से ही अपने क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहने को कह दिया है।

बंगाल में कैसे बढ़े सीट

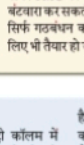

कांग्रेस ने राज्यों में अपनी रणनीति बदल ली है। पार्टी को लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को चुनाव में गठबंधन के समय न सिर्फ कमतर आंका, बल्कि सीटों के बंटवारे में भी उचित जगह नहीं दी। मसलन, लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस चार लोकसभा सीट लेकर भी ममता के साथ गठबंधन को तैयार थी, लेकिन TMC ने किसी भी सूरत में दो से अधिक सीट नहीं देने की बात कही। अब कांग्रेस अगले साल वहां होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खुद की स्थिति मजबूत करना चाहती है। पार्टी अगले कुछ दिनों तक वहां के कई मुस्लिम नेताओं को अपने साथ जोड़ने वाली है। कांग्रेस को लगता है कि अगर TMC को लगेगा कि मुस्लिम वोट में कांग्रेस बड़ा बंटवारा कर सकती है तो विधानसभा चुनाव में वह खुद न सिर्फ गठबंधन करेगी, बल्कि ठीक-ठाक सीटें देने के लिए भी तैयार हो जाएगी।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

महंगाई बढ़ेगी

यह पत्र 23 जून के संपादकीय 'टकराव बढ़ेगा' से संबंधित है। अमेरिका का ईरान को दो हफ्ते की चेतावनी देकर अचानक उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर देना पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि इस कार्रवाई से ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो गया या उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की सत्ता खत्म हो जाएगी। ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। अब यह लगभग तय है कि ईरान मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला करेगा। संभव है कि कुछ और देश भी उसका साथ दें। अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर देता है, जिससे लाखों बैरल कच्चा तेल गुजरता है, तो पूरी दुनिया के लिए यह किसी संकट से कम नहीं होगा। पूरी दुनिया को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है।

बाल गोविंद, नोएडा

ट्रंप का ढोंग

23 जून के स्पीकिंग ट्री कॉलम में 'वसुधैव कुटुम्बकम का उद्घोष प्रेम से आता है' लेख पढ़ा। यह लेख प्रेम की गहराई और उसके आध्यात्मिक स्वरूप को बहुत संवेदनशील तरीके से समझाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का 'I love Pakistan' वाला बयान राजनीतिक मंशा से प्रेरित लगता है, उसमें सच्चा प्रेम नहीं दिखता। लेख इस बात को समझने की प्रेरणा देता है कि प्रेम धर्म या पहचान में नहीं बंधता। गीता में श्रीकृष्ण ने भी प्रेम को समभाव से जोड़ा है। अगर हम प्रेम को राजनीतिक फायदे का जरिया बनाएं, तो वह अपने मूल भाव से दूर चला जाता है।

कविता सिंह, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

ट्रंप के ऐक्शन से बढ़ेगी इकॉनमी की टेंशन - एक खबर

- टेंशन देने में ट्रंप कंजूसी नहीं करते चाहे सामने दोस्त हो या दुश्मन!

रितु यादव

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 109

वैश्विक स्थिरता को खतरा

गत सप्ताहांत अमेरिकी वायु सेना के बी-2 स्टेल्थ बम वर्षक विमानों ने ईरान के उन तीन ठिकानों पर हमले किए जो परमाणु हथियार कार्यक्रम से संबंधित हैं। फोर्दो, नतांज और इस्फहान नामक इन शहरों में ये परमाणु ठिकाने जमीन के बहुत नीचे स्थित हैं और इसलिए अधिकांश हमलों से सुरक्षित भी हैं। गत सप्ताह जब इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू किए तो यह माना जा रहा था कि जमीन के भीतर दबी ये परमाणु इकाइयां सुरक्षित हैं। केवल अमेरिकी बंकर बस्टर बम (जीबीयू-57) ही 60 मीटर की गहराई पर स्थित इन ठिकानों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे।

इस बात की काफी अटकलें थीं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प इजरायल के लगातार अनुरोधों पर आगे बढ़ेंगे और वह करने की कोशिश करेंगे जो उसके हवाई हमले नहीं कर सके। उन्होंने अपने चुनावी वादे में कहा था कि वह अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं शामिल करेंगे लेकिन उन्होंने ईरान पर बमबारी को लेकर भी सकारात्मक रुख दर्शाते हुए कहा है कि अमेरिका लंबे समय से ईरान को लेकर नरमी बरत रहा है। उनका यह बयान खासतौर पर परमाणु प्रतिबंध समझौते को लेकर रहा जिसे उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आगे बढ़ाया था।

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक दशक पीछे धकेलने जैसा वांछित परिणाम हासिल हुआ है अथवा नहीं। संवर्धित यूरेनियम की जिस छोटी सी मात्रा के लिए तथा और अधिक यूरेनियम संवर्धन की संभावना के चलते ये हमले किए थे, संभव है कि उसे पहले ही किसी नए ठिकाने पर पहुंचाया जा चुका हो, जो हमले से दूर हो। चाहे जो भी हो अगर ईरान की क्षमताओं को नियंत्रित करना प्राथमिकता थी तो भी ऐसे हमले को शायद ही जरूरी माना जा सकता हो। जंगी परमाणु हथियार के तत्व तैयार करना एक बात है और उसे इस तरह तैयार करना कि उसे मिसाइल के जरिये हमले में इस्तेमाल किया जा सके एकदम दूसरी बात है। इजरायल सार्वजनिक और निजी रूप से लंबे समय से यह कहता आ रहा है कि ईरान कुछ ही महीने में अपना परमाणु कार्यक्रम पूरा कर सकता है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस मौके पर अमेरिका एक बेलगाम महाशक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। दुनिया के बाकी देश इसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वह अपनी शक्ति का उपयोग उन देशों पर हमले करने के लिए कर रहा है जिनके अंतर-राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ईरान के साथ निरंतर संघर्ष से कोई हित पूरा नहीं होता सिवाय इसके कि इजरायल के मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान को बनाए रखा जाए। वह सरकार जो फिलिस्तीनी नागरिकों पर ऐसे हमलों में शामिल है जिन्होंने दुनिया को झकझोर दिया है। इससे न तो वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है और न ही अमेरिकी राष्ट्रीय हित पूरे हो रहे हैं।

निश्चित तौर पर यह वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिका ने दिखाया है कि वह पूरी तरह अनियंत्रित व्यवहार कर सकता है। यहां तक कि वह यूरोप के करीबी सहयोगियों से मशविरा किए बिना भी कदम उठा सकता है। यह परमाणु अप्रसार के ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो सकती है। जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं मसलन यूक्रेन, ईरान आदि, उनके अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो गया है जबकि उत्तर कोरिया और इजरायल जैसे परमाणु हथियार संपन्न देश पूरी तरह बेलगाम हैं। इससे विभिन्न देश यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उन्हें भी परमाणु हथियार संपन्न देशों के हमलों से दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए परमाणु कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि परमाणु हथियार बनाने वाले नए देश भी परमाणु हथियारों को लेकर भारत की तरह जवाबदेह हों। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक निर्णय से इस आशंका को जन्म दे दिया है कि ईरान दोगुने जोश से परमाणु हथियार बनाने में लग सकता है और तमाम अन्य देश उसका अनुसरण कर सकते हैं।

अजय मोहंती

दुष्प्रचार से लड़ने के लिए सधे नजरिये की जरूरत

दुष्प्रचार एवं भ्रामक खबरों के बीच तथ्यों की जांच और सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के तौर-तरीके प्रभावी बनाने होंगे। बता रहे हैं अजय कुमार

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक नया मोर्चा खुलता साफ दिखाई दिया। इस मोर्चे पर लड़ाई मिसाइल और मशीनों से नहीं बल्कि गलत धारणाओं एवं दुष्प्रचार को हथियार बनाकर लड़ी गई। सभी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां परोसी जा रही थीं और इन्हें इस कदर गढ़ा गया था कि वे जनमानस की सोच को प्रभावित कर रही थीं और लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही थीं। यद्यपि, इन दुष्प्रचारों से लड़ने में तथ्यों की जांच करने वाले दलों (फैक्ट-चेकिंग इकाइयों) ने पूरी मेहनत की लेकिन वे एक सधी रणनीति के साथ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार एवं लोगों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के आगे टिक नहीं पाए। सूचना युग की वास्तविकता यह है कि सच्चाई स्वतः नजर नहीं आती है बल्कि उसे लोगों के सामने सही रणनीति के साथ रखना पड़ता है।

दुष्प्रचार तेजी से फैलता है क्योंकि उन्हें रोचक कहानियों के जरिये आगे बढ़ाया जाता है जिन्हें लोग तथ्यों से अधिक याद रखते हैं। कहानियां हमारा ध्यान खींचती हैं, भावनाओं को जगाती हैं और हमें चीजों को समझने में मदद करती हैं, भले ही वे सही हो या न हों। उदाहरण के लिए षडयंत्र के सिद्धांत पेचीदा विषयों का सहज जवाब देते हैं जिन्हें दूसरों के साथ साझा करना आसान और भूलना मुश्किल होता है। अल्गोरिद्म से चलने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुश्किलें और बढ़ा देते हैं क्योंकि वे ऐसी सामग्री दिखाते हैं जो उपयोगकर्ताओं (यूजर) की मौजूदा धारणाओं एवं भावनाओं के साथ मेल खाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि लोग केवल उसी विषय या घटना से संबंधित पोस्ट देखते है जिनके बारे में उनके मन में पूर्व से ही एक धारणा तैयार रहती है। यानी वे वही सुनते एवं देखते हैं जो वे सुनना एवं देखना चाहते हैं। यह समस्या अधिक विकराल हो जाती है क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से उन विचारों का बचाव करते हैं जो उनके समूह या उनकी पहचान से मिलते-जुलते हैं और उन तथ्यों को अस्वीकार कर देते हैं जो उनकी राय का समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे में फर्जी कहानियां न केवल अपनी जगह बना लेती हैं बल्कि वे लोगों का भरोसा भी जीत लेती हैं। केवल सच्चाई सरल रूप में लाकर दुष्प्रचार से मुकाबला नहीं किया जा सकता बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव को एवं समूहों से उनका जुड़ाव खत्म करना पड़ता है।

मुख्यधारा की मीडिया को इस नए युग में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में सोशल मीडिया सार्वजनिक चर्चा की दिशा तय कर रहा है जिसे देखते हुए परंपरागत समाचार माध्यम लोगों का ध्यान खींचने की होड़ में फंस कर रह गए हैं। इस चक्कर में वे तथ्यों की व्यापक जांच किए बगैर आनन-फानन में खबरें परोसते हैं और सनसनी मचाने की कोशिश करते हैं। एक समय था जब तथ्यों की जांच पत्रकारिता में सर्वाधिक महत्त्व रखती थी। आर्थिक कारणों और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच दर्शकों के बंटने से समाचार चैनल वैसी सामग्री अधिक दिखाने लगे हैं जो विशेष समूहों को आकर्षित करते हैं। यह बदलाव जाने-अनजाने में दुष्प्रचार को बढ़ावा देता है।

फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 2019 में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) फैक्ट-चेक यूनिट की स्थापना की थी और 2021 में नियमों में संशोधन किए थे। इन संशोधनों के बाद सरकार द्वारा अधिसूचित फैक्ट चेक यूनिट को सरकार के काम-काज से जुड़ी भ्रामक खबरों को खोज निकालने और मध्यस्थों (सोशल मीडिया या मेनस्ट्रीम मीडिया) को इन्हें हटाने के लिए कहने का अधिकार मिल गया। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भ्रामक एवं फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के उपाय किए हैं। इन उपायों में किसी तीसरे पक्ष के फैक्ट-चेकर के साथ साझेदारी, क्राउड-सोर्स वेरिफिकेशन का तरीका अपनाना और उपयोगकर्ताओं के सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं के आधार पर सूचना समितियों का गठन एवं डिस्क्लेमर देना आदि शामिल हैं। हालांकि, ये प्रयास केवल दो निष्कर्षों पर पहुंच कर रह जाते हैं- सामग्री को केवल 'सत्य' या 'फर्जी' के रूप में चिह्नित कर दिया जाता है।

फैक्ट चेकिंग इकाइयों के अस्तित्व में आने के बावजूद उनका प्रभाव सीमित ही है क्योंकि वे नीरस तरीके से काम करती हैं और लोगों के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ने में विफल रहती हैं। फर्जी खबरों को खारिज करने की उनकी औपचारिक तकनीक लोगों की भावनाओं को उकसाने वाली फर्जी खबरों के प्रभाव को कम नहीं कर पाती है। इसका एक प्रभावी तरीका दिलचस्प रूप में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण हो सकता है। कहानी कहने का तरीका अधिक प्रभावी है - तथ्यों को संबंधित, आकर्षक और सांस्कृतिक रूप से परिचित कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। फैक्ट-चेकिंग इकाइयां वास्तविक जीवन के दृश्य, शॉर्ट क्लिप या रोजमर्रा की ऐसी दिलचस्प कहानियों का सहारा ले सकती हैं जो लोगों के दिलो-दिमाग पर असर डाल सकते हैं। यह तरीका भ्रामक खबरों को उजागर करने के साथ-साथ लोगों की धारणा बदलने में भी सहायक होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मन की बात' कार्यक्रम में जिस तरह कहानियों के जरिये संवाद करते हैं उससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में आम नागरिकों के जीवन से जुड़ी रोचक एवं प्रेरक घटनाओं का इस्तेमाल सकारात्मक संदेश देने और राष्ट्रीय पहल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। लोगों के प्रयासों का उल्लेख कर प्रधानमंत्री नीतिगत संदेश को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं जिसे आसानी से याद रखा जा सकता है। फैक्ट चेकिंग इकाइयां इसी दृष्टिकोण के साथ अपना काम कर सकती हैं। मानव केंद्रित कहानियों के जरिये प्रामाणिक खबरें एवं जानकारियां प्रस्तुत करने से लोग सच्चाई से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। केवल फर्जी खबरों के खंडन एवं उन्हें भ्रामक बताने से वास्तविकता लोगों तक नहीं पहुंचती है।

जिस तरह मन की बात में वास्तविक लोगों की आवाज को बढ़ावा दिया जाता है उसी तरह फैक्ट-चेकिंग से जुड़ी पहल उन लोगों का उदाहरण पेश कर सकती है जो फर्जी खबरों या दावों से नुकसान उठा चुके हैं, मगर बाद में संभल गए हैं। इस कार्य में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों की मदद से तथ्यों को संवाद के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। जब लोग स्वयं अपने आप को किसी कहानी में पाते हैं तो वे अपनी धारणाओं में बदलाव को लेकर अधिक तैयार रहते हैं।

लोगों के वास्तविक जीवन एवं मूल्यों जैसी सहानुभूति एवं उत्साह से जुड़ी बातें प्रामाणिक खबरों को और अधिक यादगार बना सकती हैं। साक्ष्य, व्यंग्य, रील या लोक कथाओं के माध्यम से सच्चाई लोगों के बीच अधिक मजबूती के साथ पहुंचाई जा सकती है। जब सच्चाई ठोस एवं बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखी जाती है तो यह दुष्प्रचार का असर लोगों के मन से निकाल सकती है।

भ्रामक खबरों एवं दुष्प्रचार की काट अब भी मौजूद हैं मगर आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि नहीं किए जाने के कारण बहुत अधिक सफलता नहीं मिलती है। अगर तथ्यों की जांच करने वाली आधिकारिक विश्वसनीय इकाइयां तैयार की जाए तो दुष्प्रचार पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाया जा सकता है।

अगर फैक्ट चेकिंग इकाइयों को दुष्प्रचार से सुरक्षा का मजबूत कवच बनाना है तो उन्हें लोगों तक ठोस नजरिया ले जाने में सबसे आगे रहना होगा। सच्चाई को उबाऊ और नीरस रूप में प्रस्तुत करने से दुष्प्रचार का जंजाल नहीं तोड़ा जा सकता। फैक्ट-चेकिंग टीम को उन रोचक कहानियों एवं आख्यान का सहारा लेना चाहिए जो लोगों के दिल और दिमाग में जगह बना सकते हैं। वैसे भी वर्तमान समय में मीडिया की इस सुनामी में अगर आप अपनी कहानी स्वयं नहीं बताएंगे तो कोई और इसे अपने तरीके से लोगों को सुनाएगा।

(लेखक यूपीएससी के चेयरमैन और पूर्व रक्षा सचिव हैं)

वैश्विक हालात के बीच एफडीआई के लिए जोखिम बढ़ा

अर्थतंत्र

राजेश कुमार

हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर कम होकर मई में 2.8 फीसदी रह गई। यह पिछले 75 महीनों का सबसे निचला स्तर है। खुदरा मुद्रास्फीति में हुई भारी कमी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 6 जून को रीपो दर में 50 आधार अंक की कमी कर दी। यह उम्मीद से बड़ी कमी थी क्योंकि बाजार और विशेषज्ञ रीपो दर 25 आधार अंक घटने की उम्मीद कर रहे थे।

रीपो दर में बड़ी कटौती करने के साथ एमपीसी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए अब उसके पास अधिक गुंजाइश नहीं बची है। निजी क्षेत्र के कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चालू वर्ष में मुद्रास्फीति आरबीआई के अनुमान 3.7 फीसदी से कहीं कम रहेगी। उनके अनुसार मुद्रास्फीति कम रहने से नीतिगत दरों में कमी की और गुंजाइश बन जाएगी। नीतिगत दर कम रहने से ऋणों पर ब्याज कम हो जाएगा और आर्थिक गतिविधियों को मदद मिलेगी मगर पूंजीगत प्रवाह पर इसके प्रभाव और बाहरी वित्तीय स्थिति पर पैनी नजर रखनी होगी। इजरायल-ईरान के बीच युद्ध पर भी नजरें टिकी रहेंगी। इस युद्ध से निकट अवधि में निवेशक जोखिम लेने से दूर रह सकते हैं।

वर्ष 2025 की शुरुआत से 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड लगभग 50 आधार अंक कम हो गई है, लेकिन अमेरिका के 10 वर्ष की अवधि के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड हाल के महीनों में बढ़ गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि इन दोनों बॉन्ड के बीच अंतर कम होकर 2 फीसदी से भी कम रह गया है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय बॉन्ड में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को अधिक फायदा नजर नहीं आ रहा है। रुपये में सालाना 2 फीसदी से कम गिरावट (जिसकी आशंका हमेशा रहती है) भी विदेशी निवेशकों को बड़ा झटका दे सकती है। उदाहरण के लिए कोविड महामारी के दौरान 2020 में यील्ड में अंतर 5 फीसदी से अधिक था।

यह अंतर दो कारणों से कम हो रहा है। पहला कारण यह है कि कोविड महामारी के बाद अमेरिका सहित पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति काफी बढ़ गई। इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को नीतिगत दरें बढ़ानी पड़ीं। आरबीआई ने भी रीपो दर बढ़ा दी। हालांकि, भारत में मुद्रास्फीति कम होकर निचले स्तर पर आ गई है मगर अमेरिका में मुद्रास्फीति अब भी ऊंचे स्तर पर है। इसके अलावा डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा शुल्क बढ़ाने एवं इससे जुड़ी अनिश्चितताएं (जो मुद्रास्फीति पर प्रभाव डाल सकती हैं) बाजार को निराश कर रही हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के नवीनतम अनुमान के अनुसार इस साल की अंतिम तिमाही में अमेरिका में मुद्रास्फीति लगभग 4 फीसदी तक पहुंच जाएगी, जो फेडरल रिजर्व के मध्यम अवधि के अनुमान का दोगुना होगी। अनुमान में यह भी कहा गया है कि मुद्रास्फीति 2026 में भी इस लक्ष्य से अधिक रह सकती है। ऊंची मुद्रास्फीति फेडरल रिजर्व को दरें घटाने नहीं देगी।

दूसरा कारण (जिसकी चर्चा हाल में इसी स्तंभ में की गई है) यह है कि अमेरिकी कांग्रेस के बजट कार्यालय के अनुमानों के अनुसार अमेरिका में बजट घाटा काफी ऊंचे स्तरों पर पहुंच चुका है। अमेरिका में कर्ज का स्तर मौजूदा इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 100 फीसदी से बढ़कर 2055 तक 156 फीसदी से अधिक हो जाएगा। अमेरिका में बजट घाटा और कर्ज को लेकर अनुमान बाजार में एक वर्ग को झटका दे रहे हैं जिससे निवेशक ऊंची यील्ड की मांग कर रहे हैं। इन दोनों कारणों से बॉन्ड यील्ड ऊंचे स्तरों पर है। यह यील्ड में अंतर कम होने की एक वजह बन रही है।

यील्ड में अंतर कम रहने से बॉन्ड पर दांव खेलने वाले विदेशी निवेशकों में उत्साह कम हो सकता है, वहीं पूंजी आने के दूसरे माध्यम भी प्रभावित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी बजट घाटा बढ़कर जीडीपी के 6 फीसदी से अधिक हो गया है, जो पिछले 50 वर्षों के औसत 3.8 फीसदी से अधिक है। अतः अमेरिकी सरकार को अपना घाटा कम करने के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत है। मगर बजट घाटा कम करने के चक्कर में पूंजी लागत और रकम के प्रवाह पर असर होगा।

भारत जैसे देश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पूंजी का श्रेष्ठ जरिया माना जाता है। रकम के साथ ही एफडीआई तकनीक एवं उत्कृष्ट व्यवहार भी अपने साथ लाता है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर एफडीआई का प्रवाह हाल के वर्षों में शिथिल हो गया है। वैश्विक स्तर पर व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताएं और पूंजी पर लागत बढ़ने से एफडीआई प्रवाह और अवरुद्ध हो सकता है। इस बीच, भारत में भी विदेशी निवेशक तेजी से अपना निवेश निकाल रहे हैं और एफडीआई में कमी आती दिख रही है। उदाहरण के लिए भारत में पिछले वित्त वर्ष में सकल एफडीआई 81 अरब डॉलर से अधिक रहने के बावजूद शुद्ध एफडीआई महज 35 करोड़ डॉलर रह गया।

वैश्विक वित्तीय एवं आर्थिक स्थितियां संकेत दे रही हैं कि निकट से मध्यम अवधि के बीच विदेशी रकम की आमद अनुकूल नहीं रह सकती है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए निवेश की खास जरूरत है। लिहाजा, निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम से कम तीन मोर्चों पर काम करना होगा। पहली बात, भारत को निवेश के एक आकर्षक स्थान के रूप में अपनी दावेदारी मजबूत करनी होगी। दूसरी बात, विदेशी पूंजी में संभावित कमी की भरपाई करने और निवेश बढ़ाने के लिए भारत को अपनी बचत दर में इजाफा करना होगा। तीसरी बात, भारत को उपलब्ध बचत का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। इसे अंजाम देने का एक तरीका यह हो सकता है कि बजट घाटे में वाजिब एवं स्थायी कमी लाकर सरकारी बचत योजनाओं पर निर्भरता कम की जा सकती है। दुनिया बदल रही है और भारत को भी हालात के अनुसार बदलाव के रास्ते पर चलना चाहिए।

आपका पक्ष

स्कूली शिक्षा को सशक्त बनाने की जरूरत

भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से असमानता और व्यवसायीकरण के दुष्चक्र में फंसी है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग पर छात्रों की निर्भरता कम करने के लिए एक समिति का गठन निश्चित रूप से सराहनीय है। मगर सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या यह सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा या वास्तव में ठोस बदलाव आ पाएगा। कोचिंग उद्योग का बदस्तूर पनपना न केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि कई कोचिंग संस्थान तो अब सरकारी भर्ती परीक्षाओं को भी प्रभावित करने लगे हैं। इसके विपरीत, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में शिक्षा प्रणाली समावेशी और समान है, जहां स्कूल ही प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते हैं। वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आधुनिक पाठ्यक्रम और व्यक्तिगत विकास पर जोर दिया

शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए समिति गठित की है मगर इसका असर क्या होगा यह अभी सवालों के घेरे में है

तैयारी भी स्कूलों में ही कराई जाती है। इन देशों में शिक्षा या तो मुफ्त है या न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है। भारत में, स्कूल स्तर पर ही शिक्षा प्रणाली कमजोर हो गई है, जिससे अभिभावक और छात्र कोचिंग पर निर्भर हो गए हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां जेईई, नीट और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग अनिवार्य मानी जाने लगी है। यह स्थिति गरीब और मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन गई है। सरकार को स्कूली शिक्षा को सशक्त करने, शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश करने और प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और समाज के लिए योगदान होना चाहिए।

राजूराम प्रजापत, नागौर, राजस्थान

उड़ान से पहले विमान की पूरी जांच हो

किसी भी हवाई जहाज के उड़ने से पहले उसकी पूरी जांच होनी चाहिए जैसे कि पर्याप्त ईंधन का होना, वॉल्व का काम करना, तकनीकी परीक्षण, लैंडिंग गियर का काम करना, हवा का दबाव सहन करने की स्थिति, रनवे की स्थिति, प्लेन में भार क्षमता उठाने की स्थिति। मौसम की स्थिति, ब्लैक बॉक्स का काम करना, स्टाफ को पर्याप्त आराम मिलना, नई तकनीक का उपयोग करना, सुरक्षा के नियमों का पालन करना ये सभी बातें भी हादसों को रोकने का काम करती है।

भगवानदास छारिया, इंदौर

समय रहते ठीक हों गड़बड़ियां

तकनीक अभी तक मानव जीवन के अनुकूल नहीं हुई है। इसमें सदैव जोखिम रहता है। यातायात के हवाई साधन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। उड़ान भरने के बाद जो तकनीकी खराबी पकड़ी जाती है वो उड़ान भरने से पहले क्यों नहीं जांची जाती? एक बड़े हादसे के बाद जाकर पता चलता है कि विमान में तकनीकी खराबी आई थी। सतर्कता और सावधानी तभी कारगर होती है, जब तय समय के भीतर इसकी जरूरत को समझा जाए। ये विमान हादसे एक गंभीर चेतावनी है। इसलिए उन सभी चीजों को अतिशीघ्र दुरुस्त किया जाए, जो मानव की दिनचर्या में शामिल हैं।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 12वें राष्ट्रीय दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के संकट का उल्लेख करते हुए कहा कि अब समय वह नही है कि कॉरपोरेट संगठन केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करें बल्कि अब उन्हें पर्यावरणीय कीमत को ध्यान में रखना होगा।

अमर उजाला

प्रवाह

77 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 ■ आगरा

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 24 जून 2025

युद्ध का एलान बूढ़ों द्वारा किया जाता है, लेकिन लड़ना और मरना युवाओं को पड़ता है। -हर्बर्ट हूवर

ईरानी संसद के होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करने के फैसले पर अगर वहां की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मुहर लगाती है, तो इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति शृंखला पर संकट आएगा। आपूर्ति-स्रोतों में विविधता लाने की नीति से भारत पर फिलहाल संकट नहीं है, लेकिन कीमतों में उतार-चढ़ाव चुनौती न बने, इस पर ध्यान देना होगा।

होर्मुज संकट और भारत

अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध किए जाने के प्रस्ताव पर ईरान की अभूतपूर्व मंजूरी ने वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजारों में तो हलचल मचाई ही है, यह कदम सामरिक के साथ आर्थिक दृष्टि से भी वैश्विक संतुलन को हिला सकता है। हालांकि, इस फैसले को अंतिम रूप देने का अधिकार ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पास है, लेकिन विश्व के इस सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक, जहां से प्रतिदिन करीब 30 फीसदी वैश्विक तेल और दुनिया की एक-तिहाई एलएनजी की ढुलाई होती है, के बंद होने की आशंकाओं ने फिलहाल भारत समेत तमाम ऊर्जा आयातक देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला होर्मुज जलडमरूमध्य वैसे तो अपने सबसे संकरे बिंदु पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है और इसके शिपिंग लेन तो और भी अधिक संकरे हैं, लेकिन इसका महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत जैसे प्रमुख तेल उत्पादक अपने तेल निर्यात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं। बावजूद इसके कि कम चौड़ा होने की वजह से इसे अवरुद्ध करना या फिर गुजरने वाले जहाजों पर हमला करना आसान हो जाता है, तथ्य यह भी है कि ईरान ने अब तक किसी संघर्ष के दौरान इसे अवरुद्ध नहीं किया है। 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान भी दोनों देशों ने वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला तो किया, लेकिन यातायात नहीं रोका। वजह यह है कि ईरान खुद अपने व्यापार के लिए भी जलडमरूमध्य पर ही निर्भर है और इसे अवरुद्ध किए जाने पर ईरान के दुश्मनों के साथ दोस्तों को भी नुकसान पहुंचेगा। शायद इसलिए ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन से ईरान को समझाने के लिए कहा है। जहां तक बात भारत के आयात की है, तो फिलहाल तो इसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यह ईरान से कच्चे तेल का आयात नहीं करता है, लेकिन भारत

के आयातित कच्चे तेल का आधे से अधिक और प्राकृतिक गैस का तकरीबन 80 फीसदी इसी मार्ग से गुजरता है, इसलिए आशंकाएं तो बनी ही हुई हैं। पेट्रोलियम मंत्री भी आश्वासन दे चुके हैं कि भारत के पास कई हफ्तों का रणनीतिक तेल भंडार शेष है। इसके अतिरिक्त, भारत ने हाल के वर्षों में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और तेल आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, इसलिए उसे पर्याप्त तेल और गैस तो मिलती रहेगी, लेकिन कीमतों में उतार-चढ़ाव बड़ी समस्या न बने, इसके लिए जरूरी है कि भारत संकट की इस घड़ी को अपनी ऊर्जा कूटनीति को मजबूत करने, रणनीतिक भंडारण क्षमता बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने के अवसर के रूप में ले।

यह सिर्फ पश्चिम एशिया की लड़ाई नहीं

अगर अमेरिका ईरान की शक्ति को कम करने के साथ-साथ द्वि-राष्ट्र समाधान की दिशा में काम कर सके और रूस का विरोध करने के लिए यूक्रेन की सहायता इस्राइल की तरह करे, तो वह यूरोप और पश्चिम एशिया, दोनों में शांति, सुरक्षा और समावेशिता में वास्तविक योगदान देगा, जो ऐतिहासिक होगा।

ईरान के तीन प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले को लेकर इतनी बातें हो रही हैं कि इनमें खो जाना आसान है, लेकिन मैं इस आख्यान को आकार देने वाले वैश्विक, क्षेत्रीय एवं स्थानीय ताकतों का पता लगाते हुए यह जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में यहां हो क्या रहा है। यह एक बड़ा खेल है, जो सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है। जैसे व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर हमले का एकमात्र उद्देश्य यूक्रेन के लोकतंत्र को नक्शे से मिटाना और उसे रूस में शामिल करना है, उसी तरह 2023 में लेबनान, यमन और इराक में आतंक के ईरानी प्रतिनिधियों तथा हमास द्वारा इस्राइल पर हमला समावेशी ताकतों और प्रतिरोध की ताकतों के बीच वैश्विक संघर्ष है।

थॉमस एल फ्रीडमैन

द न्यूयॉर्क टाइम्स

इस संघर्ष में एक तरफ वैसे नेता शामिल हैं, जिनका देश व्यापार से ज्यादा लाभ उठाता है, जो वैश्विक खतरे के खिलाफ ज्यादा सहयोग करते हैं और भले ही लोकतांत्रिक न हों, मगर ज्यादा सभ्य तरीके से शासन करते हैं, दूसरी तरफ वैसे नेता हैं, जो इन सब प्रवृत्तियों का विरोध करते हैं, क्योंकि संघर्ष उन्हें अपने नागरिकों का दमन करने, अपनी सेना को मजबूत करने और अपने राजकोष से पैसा चुराने में सक्षम बनाते हैं। समावेशी ताकतें तेजी से मजबूत होती जा रही थीं। संक्षेप में कहें, तो यूक्रेन पश्चिम में शामिल होने के लिए तैयार दिख रहा था और इस्राइल पश्चिम एशिया में शामिल होने के लिए। लेकिन पुतिन ने हमला करके यूक्रेन को पश्चिम में शामिल होने से रोक दिया और हमास तथा ईरान के दूसरे प्रतिनिधियों ने इस्राइल पर हमला करके उसे सऊदी अरब के निकट आने से रोक दिया।

रविवार की सुबह ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद मेरे मन में पहला सवाल उठा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप समझते हैं कि इस वैश्विक संघर्ष में पुतिन किस तरफ हैं। ईरान और रूस करीबी सहयोगी हैं। ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस को ड्रोन उपलब्ध करवाए हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को रूस पर बम गिराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह कहना चाहता हूं कि

वह यूक्रेन को इतना सैन्य, आर्थिक एवं कूटनीतिक सहयोग करें कि वह रूस का विरोध कर सके, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका हमास और ईरान को हराने के लिए इस्राइल की मदद कर रहा है। पुतिन और अयातुल्ला एक ही तरह की दुनिया चाहते हैं, जो तानाशाही, धर्मतंत्र एवं उनके भ्रष्टाचार के लिए सुरक्षित हो। वे एक ऐसी दुनिया चाहते हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के शासन, स्वतंत्र प्रेस की हवाओं से मुक्त हो; और जो स्वतंत्र विचारों वाले पड़ोसियों के विरुद्ध रूसी और ईरानी, दोनों साम्राज्यवाद के लिए सुरक्षित हो।

चीन हमेशा से दोनों खेमों में शामिल रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था स्वस्थ और बढ़ी समावेशी दुनिया पर निर्भर करती है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व प्रतिरोधी दुनिया के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है। चीन ईरान से तेल खरीदता है, लेकिन हमेशा चिंतित रहता है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया, तो वह एक दिन शिनजियांग के मुस्लिम अलगाववादियों को भी इसे मुहैया करा सकता है। ईरान से चीन की तेल खरीद तेहरान की बाहरी आय का बड़ा स्रोत है, जिसने ईरान को हमास, हिजबुल्ला और हाल तक सीरिया को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाया। आइए, अब इस संघर्ष को विशुद्ध पश्चिम एशिया के नजरिये से देखें।

मैंने 1979 में बेरूत में एक युवा विदेशी संवाददाता के रूप में अपना कॅरिअर शुरू किया। यहां मैंने पहले वर्ष चार बड़ी खबरें कवर कीं-ईरान में इस्लामी क्रांति ने शाह को उखाड़ फेंका, सऊदी शासक परिवार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे शुद्धतावादी जिहादियों द्वारा मक्का में ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा, इस्राइल और मिस्र के बीच कैंप डेविड शांति संधि पर हस्ताक्षर तथा संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में जेबेल अली बंदरगाह का उद्घाटन, जो दुनिया में सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक बन गया। और फिर पश्चिम एशिया में समावेशी और प्रतिरोधी ताकतों के बीच एक विशाल क्षेत्रीय संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ वे देश थे, जो इस्राइल को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि वह फलस्तीनियों के साथ प्रगति करे, और जो इस क्षेत्र को पश्चिम और पूर्व के साथ और अधिक घनिष्ठ रूप से जोड़ना चाहते थे। दूसरी ओर ईरान, मुस्लिम ब्रदरहुड और जिहादी सुन्नी आंदोलनों के नेतृत्व में प्रतिरोधी ताकतें खड़ी थीं, जो मूल रूप से 1979 के बाद सऊदी अरब में पनपीं और बाद में पूरे क्षेत्र की मस्जिदों तक अपना प्रभाव फैलाया। वे सभी इस क्षेत्र से पश्चिमी प्रभावों को खत्म करना चाहते थे।

अमेरिका और इस्राइल ने यह युद्ध अपनी सेनाओं के साथ लड़ा, जबकि अलकायदा और आईएसआईएस जैसे समूहों ने आतंकवादी समूहों के साथ यह युद्ध लड़ा और ईरान ने लेबनान, सीरिया, यमन और इराक में धीरे-धीरे छद्म सेनाओं का एक नेटवर्क बनाकर ऐसा किया, जिससे ईरान को अप्रत्यक्ष रूप से सभी चार देशों पर नियंत्रण करने और पश्चिमी तट व गाजा में भी पैर जमाने में मदद मिली। तेहरान में सत्ता परिवर्तन के खिलाफ चेतावनी देने वाले लोग अक्सर इराक का उदाहरण देते हैं। लेकिन यह तुलना गलत है। इराक में अमेरिका का राष्ट्र-निर्माण प्रयास कई वर्षों तक मुख्यतः ईरान के कारण विफल रहा। कह नहीं सकता कि अगर ईरान में शासन गिर गया, तो वहां क्या होगा। लेकिन मौजूदा संघर्ष के अंत के लिए यही एकमात्र शर्त नहीं है।

कभी कभी एक ही समय में दो विरोधाभासी चीजें सच हो सकती हैं। आज उन द्वंद्वों में से एक यह है कि इस्राइल एक लोकतंत्र है, लेकिन इसकी सरकार खुले तौर पर पश्चिमी तट और संभवतः गाजा को भी अपने में मिलाने की इच्छा रखती है। यह आकांक्षा अमेरिकी हितों, इस्राइली हितों और दुनिया भर के यहूदियों के हितों के लिए एक बुनियादी खतरा है। यदि हम इस क्षेत्र में समावेशी ताकतों की विजय देखना चाहते हैं, तो ट्रंप ने आज जो सैन्य कार्य किया है, वह आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं। यदि ट्रंप ईरान की शक्ति को कम करने के साथ-साथ द्वि-राष्ट्र समाधान की दिशा में काम कर सकें और रूस का विरोध करने के लिए यूक्रेन की सहायता इस्राइल की तरह करें, तो वह यूरोप और पश्चिम एशिया, दोनों में शांति, सुरक्षा और समावेशिता में वास्तविक योगदान देंगे, जो ऐतिहासिक होगा।

©The New York Times 2025

जीवन धारा

एचजी वेल्स

जो लचीला है, वही जीवित रहता है। यह न केवल व्यक्तियों पर, बल्कि समाजों और सभ्यताओं पर भी लागू होता है। यदि हम पुरानी घृणाओं और युद्धों को थामे रहेंगे, तो हमारा अंत निश्चित है।

जो लचीला है वही जीवित रहता है

दूसरो से हारकर तो हम फिर भी जीत सकते हैं, मगर एक बार मन के आगे हथियार डाल दिए, तो संभावना यही रहती है कि हम फिर कभी न जीत पाएं। मेरे विचार से युद्ध हमें स्वयं से करना चाहिए, ताकि ज्ञान और प्रेम का दीप हमेशा हमारे भीतर जलता रहे। दूसरा 'युद्ध' जो हिंसा को जन्म देता है, यह कितना भयावह है! यह मानवता का वह अभिशाप है, जो न केवल शरीर को, बल्कि आत्मा को भी कुचल देता है। जलते हुए नगर, बिखरते परिवार, और वह मूक चीख, जो हर विस्फोट के साथ गूंजती है। यदि हम युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे, तो युद्ध हमें समाप्त कर देगा। युद्ध कोई समाधान नहीं, बल्कि वह अंधकार है, जो हमारी बुद्धि, करुणा और मानवता को निगल लेता है। युद्ध, चाहे वह बाहरी शत्रुओं से हो या भीतर की घृणा से, अंततः हमें ही नष्ट करता है।

युद्ध की जड़ें हमारे मन की संकीर्णता में हैं। हम राष्ट्रीयता, धर्म और जाति की दीवारें खड़ी करते हैं, और भूल जाते हैं कि 'हमारी सच्ची राष्ट्रीयता मानवता है।' यदि हम स्वयं की अज्ञानता के बंधनों को तोड़ दें और अपने भीतर मौजूद शत्रु से युद्ध करें, तो हिंसक युद्ध की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। बाहरी शत्रु से पहले हमें अपने भीतर के शत्रु, अहंकार, लोभ और भय को हराना होगा। जीवन केवल युद्ध की छाया में नहीं जिया जाता। जीवन एक अनमोल उपहार है, एक ऐसी यात्रा, जिसमें हर कदम पर नई आशा और संभावनाएं छिपी हैं। हम सभी समय के यात्री हैं, जो भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और कोई नहीं जानता कि अगला क्षण क्या लाएगा। जीवन की अनिश्चितता ही उसका सौंदर्य है। हर सुबह एक नया अवसर है, सीखने का, बढ़ने का, और अपने सपनों को साकार करने का। मैंने हमेशा शिक्षा को मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार माना है। यदि हम अपनी बुद्धि को तेज करें, यदि हम अपने बच्चों को प्रेम, सहानुभूति और ज्ञान सिखाएं, तो हम उस आपदा को टाल सकते हैं, जो युद्ध और अज्ञानता लाते हैं। शिक्षा वह दीपक है, जो अंधेरे को चीरता है और हमें प्रगति के पथ पर ले जाता है।

सभ्यता एक ऐसी दौड़ है, जिसमें हमें या तो तेजी से दौड़ना होगा, या फिर हमेशा के लिए ठहर जाना होगा। यह दौड़ केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक भी है। जो लचीला है, वही जीवित रहता है। यह न केवल व्यक्तियों पर, बल्कि समाजों और सभ्यताओं पर भी लागू होता है। यदि हम पुरानी घृणाओं और युद्धों को थामे रहेंगे, तो हमारा अंत निश्चित है। पर यदि हम प्रेम, सहयोग और नवाचार को अपनाएं, तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं, जो सबसे सुंदर हो। युद्ध हमें सीमित करता है, लेकिन जीवन हमें मुक्त करता है। जीवन को प्रेम से जियो, और युद्ध को ज्ञान से हराओ। सब मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें, जहां युद्ध केवल किताबों में पढ़ा जाए। हमारा भविष्य हमारी पसंद पर निर्भर करता है। इसलिए अच्छा चुनें, बेहतर चुनें।

हर दिन सीखें

सूत्र

जीवन एक अनमोल यात्रा है, प्रत्येक सुबह नई आशा लाती है। हम समय के यात्री हैं, भविष्य की ओर बढ़ते हुए। प्रेम और शिक्षा चुनें, युद्ध और घृणा त्यागें। परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बेहतर करें, अन्यथा विनाश निश्चित है। अपनी सच्ची राष्ट्रीयता में मानवता को अपनाएं। हर दिन सीखें, आगे बढ़ें और एक बेहतर संसार बनाएं।

दूसरा पहलू

भोजन की तलाश के लिए मधुमक्खियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नृत्य भाषा को वैगल डांस के नाम से जाना जाता है।

मधुमक्खियों की भाषा-वैगल डांस

हम लोग एक-दूसरे से बात करते समय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार वैगल डांस मधुमक्खियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक नृत्य भाषा है, जिसका उपयोग वे अपने कुनबे के अन्य सदस्यों को भोजन, पानी या घोंसले के स्थानों जैसे संसाधनों के बारे में जानकारी देने के लिए करती हैं। ऑस्ट्रियाई एथोलॉजिस्ट कार्ल वॉन फ्रिश ने 20वीं सदी के मध्य में पहली बार वैगल डांस को डिकोड किया था। इसके लिए उन्हें 1973 में फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार मिला। माना जाता है कि वैगल नृत्य का विकास करीब दो करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। वैगल डांस के लाभ मौसम के साथ बदलते रहते हैं। मधुमक्खियों के वैगल नृत्य के तरीके न केवल उनके भोजन के स्रोतों का वर्णन करते हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए भी बड़ा संदेश देते हैं।

डॉ. दीपक कोहली

यदि मधुमक्खी ऊर्ध्वाधर छत्ते पर ऊपर की ओर बढ़ते हुए हिलती है, तो भोजन का स्रोत सूर्य की दिशा में स्थित है।

मधुमक्खियों की दुनिया में, वैगल डांस संचार का उल्लेखनीय उदाहरण है। ये खाद्य स्रोतों की जानकारियां देती हैं, जिससे उनके कुनबे को संसाधनों का कुशलतापूर्वक दोहन करने में मदद मिलती है।

वैगल नृत्य का अभिविन्यास सूर्य के संबंध में भोजन स्रोत की दिशा को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, यदि मधुमक्खी ऊर्ध्वाधर छत्ते पर ऊपर की ओर बढ़ते हुए हिलती है, तो भोजन का स्रोत सूर्य की दिशा में स्थित है। यदि यह नीचे की ओर बढ़ते हुए हिलती है, तो भोजन स्रोत सूर्य के विपरीत है। वैगल जितना अधिक समय तक दौड़ता है, भोजन स्रोत छत्ते से उतना ही दूर होता है। ऐसे ही अधिक जोरदार और ऊर्जावान नृत्य एक समृद्ध या अधिक प्रचुर भोजन स्रोत का संकेत दे सकता है। वैगल नृत्य मधुमक्खियों को अपने छत्ते के अंधेरे वातावरण में संवाद करने की अनुमति देता है, जिससे छत्ते को आसपास के वातावरण में खाद्य संसाधनों का शीघ्रता से और सामूहिक रूप से दोहन करने में मदद मिलती है। भारत मधुमक्खियों की कई प्रजातियों का घर है, जो देश की समृद्ध जैव विविधता में योगदान देती हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों में भारतीय छत्ता मधुमक्खी, पश्चिमी मधुमक्खी (यह प्रजाति मूल रूप से भारत की नहीं है, लेकिन इसे देश में लाया गया है। इसका शहद उत्पादन के लिए इसका महत्व है।) रॉक बी, छोटी मधुमक्खी और भारतीय काली मधुमक्खी (यह विभिन्न फूलों वाले पौधों से अमृत और पराग एकत्र करती है, जो फसलों और जंगली फूलों के परागण में योगदान देती है।)

मधुमक्खियों की दुनिया में, वैगल डांस संचार का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जो इन महत्वपूर्ण प्राणियों की सहकारी प्रकृति को दर्शाता है। सटीक गतिविधियों के माध्यम से, मधुमक्खियां खाद्य स्रोतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देती हैं, जिससे उनके कुनबे को संसाधनों का कुशलतापूर्वक दोहन करने में मदद मिलती है। इन प्राकृतिक चमत्कारों को समझकर और उनकी सराहना करके, हम मधुमक्खियों और उनके द्वारा समर्थित पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध वातावरण सुनिश्चित हो सके।

आंकड़े

पौधों का निर्यात

भारत से दुनिया भर में हर्बल और औषधीय महत्व के पौधों का निर्यात किया जाता है। इनमें अमेरिका में सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है।

अमेरिका	31.5%
जर्मनी	13.5%
इटली	7.5%
चीन	4.2%
यूएई	3.5%

आंकड़े पौधों के निर्यात के प्रतिशत में | स्रोत : APEDA

सूफी संत हुसैन ने रबिया से पूछा, 'तुम्हारा मन विवाह करने का है?' उन्होंने कहा, 'विवाह तो शरीर का होता है और यह शरीर तो मैं ईश्वर को अर्पित कर चुकी हूं।'

विवाह तो शरीर का होता है

सूफी परंपरा में रबिया नाम की बड़ी संत हुई हैं। उनका जन्म बसरा के एक गरीब परिवार में हुआ। माता-पिता का बचपन में ही देहांत हो गया, तो किसी ने रबिया को एक सेठ के यहां बेच दिया। वह सेठ निर्दयी था, उनसे काम कराता और पीटता था। रबिया एक रात में घर से निकल पड़ीं। जंगल में वह ठोकर खाकर गिर गईं और उनका हाथ टूट गया। उन्होंने धरती पर माथा टेकते हुए प्रार्थना की, 'हे प्रभु! मुझे अपनी इस दुर्दशा का शोक नहीं है। मैं तुझे भूलूं नहीं और तू मुझ पर प्रसन्न रहे, बस यही एक प्रार्थना है।' इसके बाद वह लौटकर फिर सेठ के यहां पहुंच गईं।

एक दिन रात में वह प्रार्थना कर रही थीं, 'हे प्रभु! तेरी सेवा में ही मेरा दिन-रात बीते, ऐसी मेरी इच्छा है, पर क्या करूं? तूने मुझे पराधीन दासी बनाया है, इसलिए सारा समय तेरी उपासना में नहीं दे सकती। इसके लिए मुझे क्षमा करना।' रबिया की प्रार्थना सेठ ने सुन ली। उसे अपनी कठोरता पर पश्चाताप हुआ और उनसे क्षमा-याचना कर कहा, 'आप मेरे घर में रहेंगी, तो मैं आपकी सेवा कर अपना जीवन बिताऊंगा। यदि जाना चाहें, तो आपकी इच्छा।'

अंतर्यात्रा

संकलित

इसके बाद रबिया सत्संग में जाने लगीं। उन दिनों सूफी संत हुसैन बसरा में ही थे। उन्होंने रबिया से पूछा, 'तुम्हारा मन विवाह करने का है।' रबिया ने उत्तर दिया, 'विवाह तो शरीर का होता है, यह शरीर तो मैं ईश्वर को अर्पित कर चुकी हूं, अब किस शरीर से मैं विवाह करूं।' इस तरह वह जीवन पर्यंत ईश्वर भक्ति में लीन रहीं।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 27 जून, 1951

ईरानी तेल कंपनी के दफ्तरों पर हमले, साइनबोर्ड उखाड़कर फेंके

ईरानी तेल कंपनी के दफ्तरों पर हमले
साइन बोर्ड उखाड़ कर फेंक दिये गये

तेहरान रेडियो ने घोषणा की कि सरकार के आदेशानुसार ईरानी पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने तेल कंपनी की इमारतों, दफ्तरों और कारखानों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया है। कंपनी के साइनबोर्ड भी उखाड़ दिए हैं।

क्या हम तीसरे विश्वयुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं

इस्राइल और ईरान जंग के बहाने कहीं पर्दे के पीछे ईरान में तख्तापलट की पटकथा तो नहीं लिखी जा रही।

डॉ. एसडी वैष्णव

मुद्दा

पश्चिम एशिया में युद्ध की विभीषिका के बीच यह चर्चा आम है कि इस्राइल जैसा छोटा-सा देश, जो मुस्लिम देशों से घिरा होने के बावजूद, ईरान जैसे ताकतवर मुस्लिम राष्ट्र से युद्ध भूमि में दो-दो हाथ कैसे कर पा रहा है। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों-हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों को बैकफुट पर धकेलकर अब सीधे ईरान में बारूदी कोहराम मचा रखा है। यह कैसे संभव हो पा रहा है?

वर्तमान परिदृश्य में इसके चार कारण सीधे-सीधे नजर आते हैं-पार्श्व में अमेरिका, खुफिया एजेंसी मोसाद, इस्राइल डिफेंस फोर्स और उनका मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन, इनके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कारण और है। वह भले ही युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उसके दंश ने यहूदियों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए फौलाद के समान मजबूत और साहसी बना दिया और वह है-

1940 के दशक में यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार हुआ, जिसे होलोकॉस्ट के रूप में जाना जाता है। जर्मनी में 1933-45 तक तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर का शासन रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नाजी जर्मन और उसके सहयोगियों ने करीब 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया था। इतिहास में यह एक ऐसी त्रासदी थी, जिसमें यहूदियों का ही नहीं, सोवियत

हुआ। उस वक्त हिटलर के खौफ के कारण पोलैंड से कई नागरिक समुद्री मार्ग से भागकर गुजरात के जामनगर तट पहुंचे, जहां उन्हें तत्कालीन महाराजा दिग्विजय सिंह ने, जिन्हें हम जाम साहिब के नाम से भी जानते हैं, वर्षों तक अपने यहां शरण दी। यही कारण है कि आज पोलैंड में जाम साहिब का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है।

हिटलर के शासनकाल में पूरे यूरोप में नाजी विचारधारा ने यहूदियों की आजीविका छीन ली, उनके घर और प्रार्थना स्थल नष्ट करके उन्हें यातना शिविरों में कैद कर दिया गया। सितंबर 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण ने यहूदियों के उत्पीड़न के साथ एक नई चरमपंथी सोच को भी जन्म दिया। यूरोपीय यहूदियों पर हुए अत्याचारों का जीवंत और रूह कंपा देने वाला चित्रण *ऐनी फ्रैंक की डायरी* में देखने मिलता है; जिसमें उसने एमस्टर्डम में प्रिंसेंग्राच पर स्थित एक गुप्त एनेक्स यानी 'छिपा हुआ कमरा' का उल्लेख किया है, जहां होलोकॉस्ट की शिकार ऐनी अपने परिवार के साथ एक बंदी के रूप में यातना से गुजरते हुए नाजी अत्याचारों की पराकाष्ठा को अपनी डायरी में शब्दबद्ध करती हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध है, तो यहूदियों के लिए काला अध्याय भी। लाखों यहूदी मार दिए गए और जो बचे, उन्हें विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। होलोकॉस्ट के लिए हिब्रू भाषा में 'शोआह' शब्द का जिक्र होता है, जो होता है। होलोकॉस्ट रूपी दर्दनाक घटना के बाद यहूदी समुदाय ने अपनी पहचान एवं संस्कृति को जिंदा रखने की दिशा में काम किया। भयंकर उत्पीड़न के उस नाजी दंश को जेहन में ताजा रखते हुए, एकजुटता, आत्मविश्वास, जिजीविषा एवं पुनर्निर्माण के संकल्प को जिंदा रखा। होलोकॉस्ट की घटना यहूदियों के राष्ट्र प्रेम को और मजबूत करती है। 1948 में हुई आधुनिक इस्राइल की स्थापना भी इसी का परिणाम है। 1959 में इस्राइल की राष्ट्रीय विधायिका नेसेट ने प्रतिवर्ष 'होलोकॉस्ट स्मरण दिवस' मनाने की घोषणा की, ताकि नाजी अत्याचारों की वह दास्तां उन्हें हमेशा याद रहे।

आज पश्चिम एशिया सुलग रहा है। इस्राइल-ईरान में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। चाहे तेल अवीव हो या तेहरान, दोनों ओर के आम नागरिक मारे जा रहे हैं या विस्थापन को मजबूर हैं। इस्राइल-ईरान जंग के बहाने अमेरिका ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रमों पर रोक लगाना चाहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस युद्ध के बरक्स हो सकता है, पर्दे के पीछे ईरान में तख्तापलट की पटकथा भी लिखी जा रही हो।

डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी नागरिकों से तेहरान छोड़ने को भी कह चुके हैं। वहां से लोगों ने पलायन भी शुरू कर दिया है। बहरहाल, मनुष्यता दांव पर लगी है। संवाद करने के बजाय, क्या पश्चिम के बहाने हम तीसरे विश्वयुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? इन विकट हालात के बीच कवि बिलाल पठान 'वास्कोडिगामा' की एक कविता जेहन में ध्वनित हो रही है- *'युद्धों के निर्णय हमेशा शून्य आते हैं/एक दिन आग से मुठभेड़ करते हुए, पानी मारा गया/और एक दिन पानी से मुठभेड़ करते हुए, आग मारी गई।'*

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 24 जून • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

किसी की करुणा व पीड़ा को देख कर मोम की तरह पिघलनेवाला हृदय तो रखो, परंतु विपत्ति की आंच आने पर कष्टों-प्रतिकूलताओं के थपेड़े खाते रहने की स्थिति में चट्टान की तरह दृढ़ व ठोस भी बने रहो -द्रोणाचार्य

विश्व शांति की जरूरत

जब इस्राइल ने ईरान पर हमला शुरू किया तो अमरीका ने न सिर्फ दूरी बनाए रखी बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दो हफ्तों बाद निर्णय लेने का एलान किया। मगर अचानक ईरान के तीन परमाणु केंद्रों पर रातों-रात बमबारी करते हुए युद्ध में सीधा कूद पड़ा। हालांकि उन्होंने पहले भी संकेत दिए थे। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ में लिखा था-सबको तेहरान को खाली कर देना चाहिए। ट्रंप ने खुद हमलों की जानकारी देते हुए कहा, परमाणु केंद्र पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं। साथ ही ईरान को धमकी दी कि यदि उसने जवाबी कार्रवाई की तो उसके खिलाफ अधिक हमले किये जा सकते हैं। अमेरिका का यह ऑपरेशन मिड नाइट हैमर रहा, जिसमें फोर्डो व नतांज पर हमला किया गया। नौसेना की पनडुब्बी द्वारा क्रूज मिसाइल का प्रयोग करते हुए इस्फहान पर निशाना बनाया गया। ट्रंप के जी7 की बैठक बीच में छोड़ कर लौटने को भी लोगों ने आशंका भरी नजरों से देखा था। हालांकि पेंटागन समेत अमेरिकी सेंट्रल कमांड, राष्ट्रपति के सहयोगी व सलाहकार, प्रशासन के अधिकारी व सैन्य योजनाकार चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनमें से कई को यह ईरान को उकसाने वाली कार्रवाई प्रतीत हो रही है, जबकि दो सप्ताह वाले बयान को पक्षकार कूटनीतिक योजना का हिस्सा ठहरा रहे हैं और इसे जटिल व ऐतिहासिक सैन्य अभियान बता कर अपनी पीठ खुद ठोक रहे हैं, जबकि विरोधी इसे इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उत्कृष्ट रणनीति का हिस्सा ठहरा रहे हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अमरीकी हमलों को लेकर बैठक करने की तैयारी में है, जबकि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की विरोधाभासी बयानों के चलते ईरान आलोचना कर रहा है। सुगबुगाहट तो यह भी है कि ट्रंप की शेखी के बावजूद वास्तविक स्थिति अस्पष्ट ही है। कोई नहीं जानता कि ईरान के बम-ग्रेड यूरेनियम को आखिर कितना नुकसान पहुंचा है। धार्मिक कट्टरतावाद या खामेनेई युग का अंत इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि मुल्क में तख्तापलट तब तक संभव नहीं है, जब तक ईरानवासी या धार्मिक नेता के विराधी एकजुट न हो जाएं। दबी जबान से इसे तीसरे विश्व युद्ध का आगाज भी बताया जा रहा है। जिसका खामियाजा सारी दुनिया को भुगतने के लिए तैयार होना होगा। विश्व शांति की बातें बनाने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अमेरिका के आगे घुटने टेकने की बाजाए हरकत में आना होगा और कूटनीतिक तरीके से इस संघर्ष पर विराम लगाने के सख्त कदम उठाने होंगे।

नोबेल की लालसा

पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार-2026 के लिए की है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वह कुछ भी कर लें उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। ट्रंप पिछले दिनों भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद के बाद कई दफा दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष रुकवाया था। हालांकि भारत सरकार ने उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पिछले दिनों ट्रंप ने पाकिस्तान के कथित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत पर बुलाया था और उसके तीन दिन बाद ही शनिवार को पाकिस्तान सरकार ने कहा कि भारत के साथ संघर्ष में ट्रंप का हस्तक्षेप एक वास्तविक शांतिदूत के रूप में उनकी भूमिका और बातचीत के माध्यम से संघर्ष समाधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ट्रंप ने हाल के समय में कई जगहों पर संघर्षरत देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने में पहल की बातें कही हैं। रूस-यूक्रेन के बीच काफी समय से चले आ रहे युद्ध को रुकवाने की भी कोशिश की। यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुला कर झिड़का भी, लेकिन युद्ध अभी तक थमा नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वह कांगो और रवांडा के बीच संघर्ष को रोकने लिए अद्‌भुत संधि करा रहे हैं। ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की लालसा को अरसे से अपने दिल में पाले हुए हैं, लेकिन वैश्विक घटनाक्रम के मद्‌देनजर उनकी लालसा पूरी होती दिखलाई नहीं पड़ रही। बीते चौबीस घंटे का घटनाक्रम तो एकदम से उनकी इच्छा पर कड़ा आघात करने वाला रहा। अमेरिका ने युद्धरत ईरान और इस्राइल के बीच तनाव को कम करने की बात तो कही, मगर रविवार तड़के इस्राइल की तरफ से ईरान पर बम डाल कर ईरान के तीन सामरिक ठिकाने नष्ट कर दिए। इस हरकत को युद्ध रुकवाने का कार्य तो नहीं ही कहा जा सकता। शांति तो वार्ता की टेबल पर होती है, लेकिन हमलावर होकर एक पक्ष का साथ देते हुए दूसरे पक्ष को शस्त्रविहीन कर देना शांति स्थापना करार नहीं दिया जा सकता। वैसे भी पाकिस्तान ने भले ही शांति के नोबेल के लिए ट्रंप को नामित करने की बात कही है, लेकिन उसके अपने देश में ही इसका तीव्र विरोध शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजूदत रह चुकीं मलीहा लोधी ने एक्स पर लिखा है कि ट्रंप को नोबेल नामित करने संबंधी सरकार का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है।

सोशल डंपिंग/डॉ. राजेंद्र प्रसाद शर्मा

प्रभावित होती मानसिक शांति

दरअसल, आज अपनी समस्याओं का बोझ दूसरे पर लादने का दौर चल निकला है। खासतौर से सोशियल मीडिया का अधिकतम उपयोग आज इसी काम में होने लगा है। डिजिटलीय भाषा में कहें तो यह दौर इमोशनल डंपिंग का चल निकला है। कहने को तो यह कहा जाता है कि यदि आप किसी परेशानी में हो तो मन को हल्का करने के लिए अपनी समस्या को किसी संगी-साथी से साझा कर लें।

इससे दो लाभ है एक तो तनाव से तात्कालिक मुक्ति मिल जाती है दूसरी ओर हो सकता है कि सामने वाला कोई सकारात्मक हल निकाल दें। पर कहा यह भी जाता है कि अपना दुख दर्द उसी से साझा करें जो आपके प्रति गंभीर हो। आपके दुख दर्द को सुनकर सहानुभूति के स्थान पर आपको मजाक का कारण तो नहीं बना दे। इमोशनल डंपिग इससे थोड़ी अलग स्थिति है और आज यह बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। होने यह लगा है कि अपने मन मस्तिष्क का बोझ हम आसानी से दूसरे पर डाल देते हैं। यह भी नहीं सोचा जाता है कि जिससे आप साझा कर रहे हैं वह इस स्थिति में है भी नहीं कि आपकी समस्या के प्रति कुछ कर सकें। हो तो यह रहा है कि हम हमारे किस्से, दुख, तकलीफ या अन्य अच्छे बुरे समाचार मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, शार्टस या इसी तरह के किसी अन्य माध्यम से दूसरे पर थोप देते हैं और जाने-अनजाने में दूसरा व्यक्ति इमोशनल डंपिंग का शिकार हो जाता है।

आज हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। मनोविज्ञानियों के सामने आज इमोशनल डंपिंग बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। बदलते सामाजिक परिवेश में इमोशनल डंपिंग का दायरा बढ़ता जा रहा है तो लोग इमोशनल डंपिंग के आसानी से शिकार भी होते जा रहे हैं। एक तरह से यह तो भावनात्मक ब्लैकमेलिंग का माध्यम बनता जा रहा है। दूसरा यह कि जो सामग्री आपको विभिन्न प्लेटफार्म से मिल रही है उसे गंभीरता से लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस सामग्री पर प्रतिक्रिया के चक्कर या प्रतिक्रियाओं के चक्रव्यूह में फंसने से आपमी मानसिक शांति भंग होना स्वाभाविक है। इसलिए दिमाग पर अधिक बोझ डालने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

लोकतंत्र पर लगी थी बेड़ियां

आपातकाल

अवधेश कुमार

आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 25 जून, 1975 की अर्धरात्रि को स्वतंत्रता आंदोलन के महान सपनों, स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और संविधान निर्माताओं की भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की कल्पनाओं को रौंदते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति फखरुद्‌दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने के अध्यादेश पर हस्ताक्षर करवाए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने इसे 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय किया और यह सरकारी गजट में शामिल भी हो गया। कांग्रेस और कुछ पार्टियां आज इसे भाजपा की भाजपा और संघ की राजनीति तथा सत्ता का दुरुपयोग घोषित कर रहीं हैं किंतु वर्तमान राजनीतिक माहौल से परे होकर आपातकाल लागू होने की परिस्थितियों, आपातकाल के दौरान विरोधी कार्यकर्ताओं नेताओं के दमन, उत्पीरण, प्रेस की स्वतंत्रताओं के दमन तथा संविधान के साथ मनमाना छेड़छाड़ आदि को साथ मिलाकर देखें तो यह नामकरण उपयुक्त नजर आएगा। हालांकि यह सामान्य ट्रेजडी नहीं है कि आज की राजनीति के अनेक चेहरे आपातकाल में जेल जाने वालों या उनके परिजनों के हैं और जिनकी राजनीति में हैसियत इसी कारण है वे कांग्रेस के साथ राजनीति के दबाव में अपनी अंतरात्मा की आवाज के विरुद्ध आपातकाल की आलोचना तक करने को तैयार नहीं है। तब इंदिरा गांधी और कांग्रेस के नेता और आज उनके समर्थक भी यही कहते हैं कि आपातकाल संविधान की धाराओं के तहत ही लगाया गया था।

निस्संदेह, देश संविधान की धारा 352 में आंतरिक आपातकाल की व्यवस्था थी। किंतु संविधान सभा में हुई बहस और उस धारा को ठीक से देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इंदिरा जी की सत्ता को कायम रखने, उनकी चाहत के आधार पर देश चलाने तथा किसी भी विरोधी आवाज के सामने न आने की तानाशाही और हिटलरवादी सोच के तहत ही आपातकाल लागू किया गया। आखिर आपातकाल के पीछे कारण क्या थे? इसका तात्कालिक और मूल कारण 12 जून, 1975 का इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंह का इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को अवैध करार देने का आदेश था। 1971 के आम चुनाव में रायबरेली क्षेत्र से पराजित विपक्ष के नेता राजनारायण ने चुनाव में धांधली तथा सरकारी मशीनरी के व्यापक दुरुपयोग का मामला दर्ज कराते हुए चुनाव परिणाम रद्द करने की अपील की थी। न्यायालय ने इंदिरा जी को इसका दोषी पाते हुए न केवल अयोग्य घोषित कर दिया बल्कि 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर

भी रोक लगा दी। न्यायालय के फैसले के विरुद्ध 20 जून को शक्ति प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के समर्थन में दिल्ली में एक बड़ी रैली की। इसमें पहली बार इंदिरा गांधी के साथ पूरा परिवार उपस्थित था और उन्होंने देश की सेवा में अपने साथ परिवार का नाम लिया। प्रकारांतर से वे समर्थकों को यही कह रही थीं कि देश और हमारा परिवार एक दूसरे के पर्याय हैं और हमें ही सत्ता के हमारे अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तब देश की पूरी तस्वीर को देखें तो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सत्ता की लंपटयी एवं शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त दोषों के विरुद्ध आंदोलन और हड़ताल चल रहे थे।

लोगों में आक्रोश था। आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध गुजरात के छात्रों ने 'नवनिर्माण आंदोलन' प्रारंभ किया था। उनकी मांग थी, 'भ्रष्ट चिमन पटेल की सरकार को बर्खास्त किया जाए।' बिहार में भी इसी तरह आंदोलन चल रहा था। छात्रों के आग्रह पर जयप्रकाश जी ने इसका नेतृत्व संभाला। इसी पृष्ठभूमि में 12 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया था। 25 जून को रामलीला मैदान में विपक्ष की पहली ऐसी रैली हुई जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में जन समूह उमड़ा। एक स्वर से इंदिरा गांधी के त्यागपत्र की मांग की गई। इस तरह का दृश्य इसके पूर्व कभी देखा नहीं गया था। 29 जून से आंदोलन करने की घोषणा की गई तथा जयप्रकाश जी ने पुलिस सहित सुरक्षा बलों से सरकार की बात न मानने की अपील की क्योंकि उनके अनुसार न्यायालय के फैसले के बाद इंदिरा गांधी का सत्ता से संवैधानिक और नैतिक अधिकार समाप्त हो चुका था। इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंची और राष्ट्रपति फखरुद्‌दीन अली अहमद को समझाया तथा उन्होंने एक कांग्रेसी के रूप में रात 11.45 बजे आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया।

आपातकाल लागू होते ही संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अंतर्गत सभी भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार समाप्त हो गए। जयप्रकाश जी सहित सारे विरोधी नेता जहां जिस शहर में थे वहीं गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए। दूसरे संगठनों के नेताओं के साथ भी ऐसा ही होने लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित 26 संगठन हालांकि 4 जुलाई को प्रतिबंधित हुए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं नेताओं की गिरफ्तारी पहले ही शुरू हो गई थी। 26 जून को संघ के सरसंघचालक बालासाहब देवरस को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। आज अपने वैचारिक विरोध में अनेक लोग आपातकाल में संघ द्वारा इंदिरा का साथ देने का शर्मनाक आरोप लगाते हैं जबकि खुफिया रिपोर्ट थी कि संघ के प्रचारक और कार्यकर्ता इंदिरा विरोधी आंदोलन को हवा दे रहे हैं। शुरू के दिनों में ही लगभग 50 हजार संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक गिरफ्तार हुए।

आपातकाल में इंदिरा सरकार ने 48 अध्यादेश जारी किए। मीसा संशोधन अध्यादेश को चार बार और जारी किया गया एवं सांसद द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई। रक्षा संशोधन अध्यादेश जारी किया गया जिसके द्वारा सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक अधिकार मिले। 3 फरवरी 1977 को एक अध्यादेश प्रधानमंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित था। हाई कोर्ट में चुनावी याचिका की जगह निपटने के लिए अथॉरिटी बनाई गई थी। सबसे विवादास्पद 42वां संशोधन था जिसने न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया। इस संशोधन ने संविधान की मूल संरचना को बदल दिया था। दिन रात संविधान बचाओ की रट लगाने वाले लोग जरा दिल पर हाथ रखकर सोचें उसके पहले या उसके बाद ऐसा कोई अवसर आया जब निर्दोष, नेताओं-कार्यकर्ताओं, आम लोगों को जेल में या भूमिगत होकर पुलिस प्रशासन के उत्पीड़न के भय में जीना पड़ा हो?

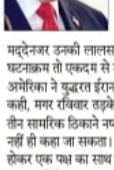

(लेख में विचार निजी हैं)

> आपातकाल में इंदिरा सरकार ने 48 अध्यादेश जारी किए। मीसा संशोधन अध्यादेश को चार बार और जारी किया गया एवं सांसद द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई। रक्षा संशोधन अध्यादेश जारी किया गया जिसके द्वारा सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक अधिकार मिले। 3 फरवरी 1977 को एक अध्यादेश प्रधानमंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित था

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक

- केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने है कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जहां 147 लाख टन को पार कर गया है

(मीडिया इनपुट्स)

- 'अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन-2025' के दौरान उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 9 प्रतिशत है, जो कृषि से जुड़े सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक है

पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने के 24 घंटे बाद ही ट्रंप ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले की इजाजत दे दी और अमेरिका को मध्य-पूर्व युद्ध में खींच दिया। इस तरह पाकिस्तान ने खुद को मूर्ख होने का तोहफा दे डाला।

मिन्हाज मर्चेंट, लेखक
@MinhazMerchant

विकसित भारत के लिए अभियान जरूरी

नशाखोरी **प्रो. (डॉ.) राजेंद्र प्र. गुप्ता**

युवाओं में नशे के प्रति बढ़ता आकर्षण पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती के रूप में सीना तानकर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी 'विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2024' के अनुसार 29.2 करोड़ से भी अधिक लोग पूरे विश्व में मादक पदार्थ के सेवन में लिप्त हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या में पिछले दशक की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। नशे के प्रति इतनी रुझान मानव सभ्यता के सामने एक गंभीर संकट की ओर संकेत कर रही है।

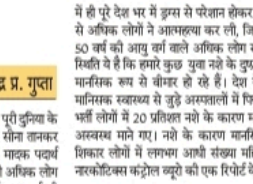

भारत में भी युवा बड़ी संख्या में नशाखोरी की चपेट में हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने युवाओं में नशे के प्रति बढ़ती रुचि को एक पीढ़ीगत संकट बताया है। यह चुनौती इतनी गंभीर है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' के तीसरे एपिसोड में 14 दिसम्बर 2014 को पूरी संवेदना के साथ देश के युवाओं से नशाखोरी से बाहर आने की विशेष अपील की थी। साथ ही उन्होंने युवाओं को विश्वास दिलाया कि राष्ट्र के सामने मौजूद इस गंभीर संकट से निपटने के लिए वे युवा वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आंकड़ों के मुताबिक, देश के लगभग 20 प्रतिशत लोग नशे की चपेट में हैं। इनमें 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। 10 वर्ष से 17 वर्ष की आयु वर्ग वाले लगभग 1.5 करोड़ किशोर भी इस खतरे की चपेट में हैं, जिनमें चिंताजनक संख्या में छोटी-छोटी बेटियां भी हैं। 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडीज 2017' के अनुसार पूरी दुनिया में 7.30 लाख लोग अवैध ड्रग्स के सेवन के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए, जिसमें से 22 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु भारत में भी हुई। एन.सी.आर.बी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ही पूरे देश भर में ड्रग्स से परेशान होकर लगभग 7800 से अधिक लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिसमें 20 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वर्ग वाले अधिक लोग रहे। कष्टदायक स्थिति ये है कि हमारे कुछ युवा नशे के दुष्प्रभाव के कारण मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। देश के लगभग 45 मानिसक स्वास्थ्य से जुड़े अस्पतालों में पिछले 10 वर्षों में भर्ती लोगों में 20 प्रतिशत नशे के कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ माने गए। नशे के कारण मानसिक बीमारी के शिकार लोगों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर

प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में नशे से संबंधित एफ.आई.आर की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में 3 करोड़ से अधिक लोग भांग के नशे में लिप्त हैं, जिनमें से 72 लाख से अधिक लोग इसकी वजह से अस्वस्थ हैं। 10 लाख के आसपास लोग इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स लेते हैं, जबकि 10 करोड़ से अधिक लोग अनेक अवैध नशीले पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही इस संकट से जूझ रहा है। अमेरिका, फ्रांस इत्यादि देशों के साथ सीरिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, रूस, ब्राजील इत्यादि देश भी इस समस्या से ग्रसित हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण दुनिया में सबसे अधिक मौतें अमेरिका और फ्रांस में ही हुई हैं। सीरिया में तो सरकार ने ही नशीली दवाओं के व्यापार को वित्त पोषित किया है। विश्व ड्रग रिपोर्ट 2017 के अनुसार केवल अमेरिका में ही नशीली दवाओं के कारण 70 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि भारत की शिक्षण संस्थाओं के आसपास चाय-नाश्ते की दुकानों, जनरल स्टोर्स इत्यादि के माध्यम से युवाओं को ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के दलदल में घसीटा जा रहा है। भारत सरकार की ओर से समय-समय पर अनेक आवश्यक कदम उठाए जाते रहे हैं। एक तरफ सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से ड्रग्स के अवैध व्यापार पर लगातार छापेमारी करके उन नशीले पदार्थों को नष्ट कर रही है तो दूसरी ओर इसमें लाभ कमाने की दृष्टि से जो असामाजिक तत्व लगे हुए हैं, उनको कानून के कड़े प्रावधानों के द्वारा दंडित भी कर रही है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नशाखोरी को समाप्त करने के लिए 'ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद से ही ड्रग्स माफिया पर लगातार प्रहार हो रहे हैं।

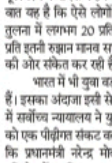

गृह मंत्रालय की सूचना के अनुसार देश की तमाम जांच एजेंसियों ने हाल ही में 2023 में 16 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का ड्रग्स जब्त किया था। 2024 में 25 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का ड्रग्स जब्त किया गया। 2023 की तुलना में 2024 में 55 प्रतिशत अधिक ड्रग्स जब्त किया गया। अगर हम नशे की गंभीर चुनौती को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें सरकार के प्रयासों को जन भागीदारी से जोड़कर उचित क्रियान्वयन में सहयोग करना होगा। आवश्यकता है विश्व के अग्रणी देशों में नशे की रोकथाम के लिए अमल में लाई जा रही कानून-व्यवस्था के अध्ययन की। इसके आधार पर भारत में नशे की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से अनुसंधान कर उपलब्ध प्रावधानों का आवश्यक संशोधन किया जा सके।

कस्तूरी कुंडल बसै **ओशो**

ध्यान का पहला सूत्र है जिसे तुम खोजने चले हो, वह खोजने वाले में छिपा है। कस्तूरी कुंडल बसै। यह ध्यान के पाठ का प्रारंभ है कि पहले अपने घर को टटोल लो। आनंद को खोजने चले हो? जगत बहुत बड़ा है। पहले घर में खोज लो, वहां न मिले, तो फिर जगत में खोजना। कहीं ऐसा न हो कि आनंद की राशि घर में लगी रहे और तुम जगत में खोजते फिरो। अकसर ऐसा ही होता है। ऐसा ही हुआ है। हम खोज रहे हैं, मिलता भी नहीं है वहां, तो हम और दूर निकलते जाते हैं खोज में। जितना ही पाते हैं कि मिलना नहीं हो रहा है, उतनी ही हमारी खोज बेचैन और विक्षिप्त होती जाती है। जितना ही हम पाते हैं कि दौड़कर नहीं पहुंच रहे हैं, हम दौड़ को और बढ़ाये जाते हैं। हमारे मन का तर्क कहता है कि शायद ठीक से नहीं दौड़ रहे, शायद जितनी शक्ति से दौड़ना चाहिए उतनी शक्ति से नहीं दौड़ रहे हैं। और दौड़ो, और उपाय करो; सारे लोग बाहर दौड़े जा रहे हैं, तो होगा तो जरूर बाहर, इतने लोग गलत थोड़े ही हो सकते हैं! हम जिस भीड़ में पैदा होते हैं, जन्म से ही हम पाते हैं कि भीड़ भागी जा रही है किसी के साथ। हम भी भीड़ के हिस्से हो जाते हैं। कोई धन खोज रहा है, कोई पद खोज रहा है, कोई यश खोज रहा है, लेकिन खोज बाहर है, सभी की बाहर है, तो हम भी उसमें लग जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। मनुष्य का मन भीड़ से चलता है। भीड़ का एक मनोविज्ञान है। तुम जहां बहुत लोगों को जाते देखते हो, तुम भी चल पड़ते हो। अनजाने यह बात स्वीकृत कर ली गई है कि जहां इतने लोग जा रहे हैं, वह ठीक ही जा रहे होंगे। इसीलिए तो दुनिया में बहुत-सी धारणाएं भी सदियों तक चलती हैं। पता भी चल जाता है कि गलत हैं, तो भी चलती हैं, क्योंकि भीड़ जब तक उन्हें न छोड़ दे तब तक नये लोग आते हैं और पुरानी धारणाओं को पकड़ते चले जाते हैं। जब तक भीड़ उन्हें पकड़े है तब तक नये बच्चे भी उन्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि बच्चे तो अनुकरण करते हैं। हम सब अनुकरण में हैं। इसलिए अलग-अलग संस्कृति, अलग-अलग समाज में, अलग-अलग चीजें मूल्यवान हो जाती हैं। किसी समाज में धन का बहुत मूल्य है। जैसे अमेरिका। तो अमेरिका में जो भीड़ है, वह धन की दीवानी है। और सब चीजें गौण हैं, धन प्रमुख है। हर चीज धन से खरीदी जा सकती है। इसलिए धन को पा लो। जिन समाजों में त्याग का बड़ा मूल्य रहा है उन समाजों में सदियों तक लोगों ने त्याग किया है।

रीडर्स मेल

शर्मिंदगी की बात

अमेरिका के विदेश विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि भारत में बढ़ते अपराध व विशेषकर बलात्कार की घटनाओं को देखते हुए अमेरिकी महिलाएं अकेले यात्रा न करें। वास्तव में देखा जाए तो यह खबर समूचे भारत के लिए शर्मसार करने के साथ ही चिंताजनक है। अमेरिका की नजर में भारत अपराधों व बलात्कारियों का देश है। अपराधी व बलात्कारी को कानून व सजा का कोई खौफ नहीं है। ऐसे प्रकरणों में गुनाहगार को समय-सीमा में कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलना भी अपराधियों के हौसले बुलंद करने वाला है। बढ़ते अपराध व बलात्कार के कारण देश का नाम व छवि खराब हो रही है। सोचने व समझने वाली बात है कि जिस देश में नवरात्रि में माता का पूजन व कन्याओं की पूजा की जाती है, उसी देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो ये पूजन केवल दिखावा बनकर नहीं रह जाते हैं? बढ़ते अपराध व बलात्कार पर प्राथमिकता के साथ नकेल कसने की दरकार है।

हेमा हरि उपाध्याय, 'अक्षत', उज्जैन

आपातकाल के सबक

25 जून 1975 की मध्यरात्रि को तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लागू कर लोकतंत्र का गला घोंटा था। आज जो कांग्रेस स्वयं को लोकतंत्र का प्रहरी और रक्षक कहते नहीं अघाती; उसका इतिहास लोकतंत्र की हत्या के अध्यायों से भरा है। 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के एक अभियोग में इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को अवैध घोषित कर दिया तो उन्होंने संविधान और लोकतंत्र दोनों को खिलौना बना डाला। समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ खाली ही नहीं बल्कि विरोध में काले छोड़े जाने लगे। क्योंकि समाचार पत्र और पत्रिकाओं में वही समाचार छपता था जो प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमोदित होता था। लालू प्रसाद यादव ने तो आपातकाल में जन्मी अपनी एक बेटी का नाम ही मीसा रख दिया। नियति का खेल देखिए कि आज वही मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की आंखों के तारे बने हुए हैं।

डॉ. नरेन्द्र टोंक, मेरठ

जल संरक्षण जरूरी

जल ही जीवन है, लेकिन प्राकृतिक जल स्रोतों की अनदेखी की वजह से कई विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं, कई स्थानों पर नदियों, पोखर आदि का अतिक्रमण हो चुका है। देश के 21 बड़े शहर जीरो ग्राउंडवाटर स्तर के बेहद करीब पहुंच चुका है। देश में 80 फीसद बारिश मानसून सीजन में होती है। आज के विकास के दौर में भी हम सिर्फ 12 प्रतिशत बारिश के जल का उपयोग कर रहे हैं, शेष जल बर्बाद हो रहा है। यदि हम शेष जल को धरती के गर्भ तक पहुंचाने में सफल रहे, तो हमें सालों भर पानी की कमी महसूस नहीं होगी। भूजल दोहन में हम दुनिया मे प्रथम स्थान पर है। भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। भूमिगत जल का स्तर वर्षा की पानी से ही बढ़ता है। यदि हम बारिश की बूंदों को धरती के गर्भ तक पहुंचाने में सफल रहे तो साल भर हमें पेयजल, घरेलू काम और सिंचाई कार्यों में पानी की कमी नहीं होगी। प्राकृतिक जल संरक्षण के स्रोतों को बचाना होगा, उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखना चाहिए।

हिमांशु शेखर, गया

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक [illegible] द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा कक्ष 1209-1210, [illegible], 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। | स्थानीय संपादक - [illegible] |
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय -011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750